नवबिहार टाइम्स

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी दैनिक

कई जिलों में बारिश, तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट

● बोकारो, गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 ● वर्ष : 09 ● अंक : 340 ● पृष्ठ : 12 ● मूल्य : 3.00 रु. ● RNI No. : JHAHIN2017/72655 ● बोकारो व औरंगाबाद से प्रकाशित

ब्रह्मोस खरीदने भारत आ रहे वियतनाम के राष्ट्रपति

● 5,800 करोड़ की डील! मित्र रूस ने भी कहा 'हां'

नई दिल्ली (एजेंसी)। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम अगले हफ्ते भारत यात्रा पर आ सकते हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद भारत के साथ सामरिक और सैन्य साझेदारी को और आगे बढ़ाना है। लेकिन, उनकी इस यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य करीब 5,800 करोड़ (700 मिलियन डॉलर) की ब्रह्मोस मिसाइल की प्रस्तावित डील है। इस मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से यह बातें सामने आई हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम की भारत यात्रा के दौरान वह ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के अलावा भी कई और तरह के हथियार और रक्षा उपकरणों को खरीदने की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित डील में ब्रह्मोस के एंटी-शिप वर्जन शामिल हो सकते हैं, जिससे वियतनाम को अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है। रूस भारत का तो भरोसेमंद मित्र है ही, वियतनाम

का भी एक बहुत पुरानी सहयोगी है। रिपोर्ट के अनुसार रूस ने वियतनाम को भारत के अत्याधुनिक स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का पूर्ण समर्थन कर दिया है और उसे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लाम को वियतनाम का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है।

भारत और वियतनाम की रणनीतिक साझेदारी

यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वह चीन गए और उसके तुरंत बाद भारत आ रहे हैं। भारत और वियतनाम के संबंधों में तब और मजबूती आनी शुरू हुई, जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम यात्रा पर पहुंचे। यहीं से दोनों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। तो लाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक दशक पूरे होने पर भारत आने वाले हैं। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग व्यापक रणनीतिक साझेदारी के मुख्य आधार है। यह साझेदारी 2009 के रक्षा सहयोग पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और 2015 के रक्षा सहयोग के संयुक्त दृष्टिकोण पर आधारित है। जून 2022 में दोनों देश एक ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया-वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड 2030 के लिए भी सहमत हुए थे और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर एक एमओयू भी साइन किया था।

संक्षिप्त समाचार

शेरों की सल्तनत में ट्रेन से सफारी का मिलेगा रोमांच

● गुजरात के गिर में अब शुरू होगी सपनों की 'ट्रेन जर्नी'!

अहमदाबाद (एजेंसी)। सोचिए, आप एक लग्जरी ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन की छत और खिड़कियां कांच की हैं। आप अपनी सीट पर फेवरेट गुजराती खाना खा रहे हैं... और तभी कांच के ठीक उस पार 'जंगल का राजा' बब्बर शेर शाही अंदाज में गुजर जाए! जल्द ही गुजरात के गिर नेशनल पार्क में

आपका यह सपना सच होने वाला है। भावनगर रेलवे डिवीजन जंगल के बीच मौजूद पुराने मीटर गेज ट्रैक पर एक स्पेशल सफारी ट्रेन चलाने जा रहा है। इसमें 'विस्टाडोम' कोच होंगे, जिनकी 360-डिग्री घूमने वाली सीटों से जंगल का हर खूबसूरत नजारा साफ दिखेगा। यह अनोखी ट्रेन शेरों के घर से गुजरने वाले दो खास रूट-'जूनागढ़ से देलवाड़ा' और 'तालाला से कांसियानेश' पर चलेगी। इस पूरी सफारी का मेन सेंटर 'सासन गिर' होगा। डिविजनल रेलवे मैनेजर (डीआरएम) दिनेश वर्मा ने बताया कि प्लान पास होते ही यह सफारी शुरू कर दी जाएगी।

सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं कर सकते

● सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम इस देश की सभ्यता और धार्मिक इतिहास नहीं भूल सकते

नई दिल्ली (एजेंसी)। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने एडवोकेट इंदिरा जयसिंह की दलीलों के जवाब में कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। एडवोकेट जयसिंह ने

सुनवाई के 10वें दिन कहा कि सबरीमाला मंदिर में एंट्री का फैसला अब भी लागू है। इस पर स्टे नहीं है लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं मिल रहा है। जय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसकी रिव्यू पिटिशन पर सुनवाई कर रहा है। हालांकि, कोर्ट कभी यह तय नहीं करता कि धर्म में क्या जरूरी है या और क्या नहीं। इसका फैसला तो धर्म ही करता है। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि हम इस भूमि के सभ्यता के विकास और धार्मिक इतिहास को नजरअंदाज नहीं कर सकते।

बंगाल -असम में एनडीए , केरल में कांग्रेस तो तमिलनाडु में डीएमके

एग्जिट पोल 2026

नई दिल्ली (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। चुनाव के परिणाम 4 मई को आएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है। दो चरणों में हुए मतदान में पहले चरण में 16 जिलों की 152 सीटों पर रिकॉर्ड 92.88 फीसदी मतदान हुआ। दूसरे चरण में 7 जिलों की 142 सीटों पर भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। अब तक आए 6 एग्जिट पोल में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है तो वहीं सिर्फ एक एग्जिट पोल में टीएमसी को बढ़त है।

छह सर्वे में भाजपा को बहुमत, दो में तृणमूल की वापसी का दावा- पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले हैं। सामने आए आठ प्रमुख सर्वे में से छह में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पूर्ण बहुमत के साथ राज्य में अपनी पहली सरकार बनाती दिख रही है।

पांचों सर्वे में एनडीए को स्पष्ट बहुमत

बंगाल में जहां पांच एग्जिट पोल्स में भाजपा आगे है, वहीं पुदुचेरी के सभी पांच प्रमुख सर्वे में एनडीए भारी बहुमत के साथ सरकार बनाता दिख रहा है। 'प्रजा पोल' और 'कामाख्या एनालिटिक्स' के अनुमानों के अनुसार तो एनडीए 20 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। इन रुझानों से एकदम साफ है कि पुदुचेरी की जनता ने सत्ता की चाबी एक बार फिर एनडीए गठबंधन को सौंपने का मन बना लिया है, जबकि कांग्रेस गठबंधन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे छूट गया है।

तमिलनाडु में द्रमुक को भारी बढ़त

एग्जिट पोल के आंकड़ों के आधार पर, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में द्रमुक गठबंधन को भारी बढ़त मिलती दिख रही है। सभी चार एजेंसियों के अनुमानों में द्रमुक को सबसे अधिक सीटें मिलने की संभावना जताई गई है।

- मैट्रिज- इस एजेंसी के अनुसार, सत्ताधारी द्रमुक गठबंधन को 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए 87 से 100 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रह सकता है।
- पीपल्स पल्स- इस सर्वे में द्रमुक गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। एनडीए को 65 से 80 सीटें मिल सकती हैं। टीवीके को यहां सबसे ज्यादा 18 से 24 सीटें मिलने की संभावना है।
- चाणक्य स्ट्रैटजी- इसके मुताबिक, द्रमुक+ को 145 से 160 सीटों के साथ बड़ी जीत मिल सकती है। एनडीए को 50 से 65 सीटों तक ही सीमित रहना पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल

एजेंसी	तृणमूल+	भाजपा	अन्य
मैट्रिज	125-140	146-161	6-10
पोल डायरी	99-127	142-171	5-9
चाणक्य स्ट्रैटजीज	130-140	150-160	6-10
प्रजा पोल	85-110	178-208	0-0
पीपल्स पल्स	177-187	95-110	1-4
पी- मारक्यू	118-138	150-175	2-6
जनमत पोल्स	195-205	80-90	4-9
जेवीसी	131-152	138-159	2-4

पुदुचेरी एग्जिट पोल 2026

एजेंसी	एनडीए	कांग्रेस+	टीवीके+	अन्य
पीपल्स पल्स	16-19	10-12	0-0	1-2
एक्सिस माय इंडिया	16-20	6-8	-	3-7
प्रजा पोल	19-25	6-10	0-0	0-0
कामाख्या एनालिटिक्स	17-24	4-7	1-2	0-1
जेवीसी	15-17	11-13	1-2	0-1

चुनाव में गजब की धांधली, 'खेला' होबे

● बीजेपी को वोट देने का ऑप्शन ईवीएम से हुआ गायब ● बीजेपी का हल्ला बोल, आयोग बोला-कराएंगे री वोटिंग

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के सेकंड फेज में बीजेपी ने बड़ा अरोप लगाया है वहीं ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पक्षपात के आरोप लगाए हैं। इसी बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि कई बूथों पर ईवीएम मशीन से कमल के निशाना वाला बटन ही गायब कर दिया गया है। आरोप है कि ऑप्शन वाले बटन पर टेप लगा है, जिससे लोग बीजेपी को वोट न दे सकें। बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने कुछ वीडियो भी शेयर किए हैं, जिसमें ईवीएम में बीजेपी का बटन ही नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच चुनाव आयोग का बयान आया है। आयोग ने कहा कि जहां भी इस तरह की शिकायतें आई हैं, वहां फिर से चुनाव कराए जाएंगे। अमित मालवीय ने कहा कि यह हैं ममता बनर्जी। यह वहीं ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने जहांगीर खान के पक्ष में आवाज उठाई। जहांगीर, एक ऐसा अपराधी जो डायमंड हार्बर के फाल्टा से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वह उनके समर्थन में आवाज उठा रही हैं। आईटी सेल के अमित मालवीय ने कहा कि कई पोलिंग बूथों पर, बीजेपी को वोट देने का विकल्प टेप लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे वोटर अपना पसंदीदा उम्मीदवार चुनने से प्रभावी रूप से वंचित हो गए हैं। यही तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल है।

दूसरे दौर में बंगाल में शाम 5 बजे तक 90 प्रतिशत वोटिंग

टीएमसी-भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसा

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में सेकेंड फेज की 142 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। शाम 5 बजे तक 89.99 प्रतिशत वोटिंग हुई। यह आकंड़ा और बढ़ सकता है। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर हिंसा, झड़प, लाठीचार्ज और ईवीएमसे छेड़छाड़ की

घटनाएं सामने आईं नॉर्थ 24 परगना के अरविंद रैली में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे को दौड़ा-दौड़ाकर मुक्के, लाठियों से हमले किए। भारी संख्या में सुरक्षाबलों की मौजूदगी के बावजूद हालात बेकाबू दिखे। सीएम ममता ने सीआरपीएफ पर टीएमसी समर्थकों और वोटरों से मारपीट का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि सीआरपीएफ ने हमारे कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वोटरों और सेंट्रल ऑब्सर्वर लोगों को मार रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ के हमले से हावड़ा के उदयनारायणपुर में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि बुजुर्ग अपने बेटे के साथ वोट डालने गए थे। केंद्रीय बलों ने उन्हें धक्का दिया और मारपीट की।

पीएम मोदी ने यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस-वे का किया उद्घाटन

हरदोई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यूपी के हरदोई में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे का उद्घाटन किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने ऐलान किया कि एक्सप्रेस-वे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम ने सपा और कांग्रेस पर कहा- सपा विकास और नारी विरोधी है। बीते दिनों एक बार फिर देश ने इनका नारी विरोधी चेहरा देखा है। इन लोगों ने नारी शक्ति वंदन संशोधन के खिलाफ वोट किया। पीएम ने पश्चिम बंगाल में चल रही दूसरे चरण की वोटिंग का जिक्र किया। कहा- जो खबरें आ रही हैं, उनसे पता चलता है कि बंगाल में भारी मतदान हो रहा है। ऐसी वोटिंग दशकों में नहीं देखी। इससे पहले पीएम ने एक्सप्रेस-वे के किनारे पेड़ लगाया। सीएम योगी के साथ एक्सप्रेस-वे पर पैदल भी चले। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस-वे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे मेरठ से प्रयागराज की दूरी सिर्फ 6 घंटे में पूरी होगी।

बंगाल में अबकी लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं

बंगाल में पहले चरण की तरह ही जनता वोट देने के लिए बड़ी संख्या में घरों से निकल रही है। लंबी-लंबी कतारों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। पिछले 6-7 दशक में जो नहीं हुआ, जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी, लोग भयमुक्त होकर वोट दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इन पांच राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है एनडीए सरकार नारी शक्ति वंदन संशोधन लेकर आई थी। अगर यह संशोधन पास हो जाता तो 2029 के चुनाव से ही महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण मिलता, लेकिन सपा ने इसके खिलाफ वोट किया। सपा कभी भी परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर नहीं उठ सकती।

जेल से छूटकर भी इंदौर नहीं आ पाएगी सोनम रघुवंशी

● कोर्ट की परमीशन के बिना शिलॉन्ग नहीं छोड़ पाएगी कातिल

भोपाल (एजेंसी)। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा मोड़ आया है। मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में हनीमून के दौरान पति राजा के मर्डर की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के करीब 320 दिन बाद जमानत मिल गई है। हालांकि, अदालत ने शर्त रखी है कि ट्रायल के दौरान सोनम को शिलॉन्ग में ही रहना होगा। शिलॉन्ग कोर्ट ने सोमवार को उसकी जमानत मंजूर कर ली। मंगलवार को सोनम के पिता देवी सिंह शिलॉन्ग पहुंचे और जमानत भर दी। इसके बाद मंगलवार शाम को सोनम जेल से रिहा हो गई। रिहाई के बाद मीडियाकर्मियों ने सवाल किए तो पिता और बेटी बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। बता दें कि कोर्ट ने चौथी सुनवाई के बाद सोनम को राहत दी है।

कोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया पर सवाल उठाए- सोनम की जमानत की मुख्य वजह गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियां रहीं। उसके वकील ने दलील दी कि 7 जून 2025 को गाजीपुर में गिरफ्तारी के समय कारण स्पष्ट नहीं बताया गया था। अदालत ने जांच में दस्तावेज में गंभीर त्रुटियां पाईं। कोर्ट ने अनुच्छेद 22(1) का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत कारण बताना अनिवार्य है। ऐसा न करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

प्रोफाइल और परिस्थितियों का भी लाभ मिला

मेघालय पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए आशंका जताई कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, जिससे दोष साबित हो। चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हैं और सबूत कोर्ट की निगरानी में हैं, इसलिए छेड़छाड़ की आशंका निराधार है। वकील ने तर्क दिया कि सोनम इंदौर की स्थायी निवासी है और बड़े कारोबारी परिवार से आती है, जिसका व्यापार कई राज्यों में फैला है। उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए फरार होने की आशंका नहीं है। 25 वर्षीय महिला होने के कारण जमानत में नरमी के सिद्धांत का हवाला दिया।

हमारा जहाज जब्त करना समुद्री डकैती, सुरक्षा परिषद ऐक्शन ले

● अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पहुंचा ईरान, कर दी बड़ी मांग

तेहरान/वॉशिंगटन (एजेंसी)। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की है। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके 'समुद्री डकैती' की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा कि अमेरिका ने 'मैजेस्टिक' और 'टिफनी' नाम के जहाजों को कब्जे में लिया और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल भी जब्त कर लिया। उनके मुताबिक यह कदम गैरकानूनी है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दखल देने जैसा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है।

नगर निगम में विवाद गहराया

महापौर अरविन्द कुमार राणा ने नगर आयुक्त पर लगाए गंभीर आरोप

नवीन सिन्हा

हजारीबाग। नगर निगम में प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर हजारीबाग महापौर अरविंद राणा और नगर आयुक्त के बीच टकराव तेज हो गया है। महापौर ने आरोप लगाया है कि निगम में जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है और उन्हें काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह स्थिति संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।हजारीबाग महापौर अरविन्द कुमार राणा ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 243 और झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 में महापौर को निगम का प्रथम नागरिक एवं लोक सेवक माना गया है, लेकिन हजारीबाग में इन प्रावधानों का पालन नहीं हो रहा है।उन्होंने 25 अप्रैल को आयोजित बोर्ड बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक के दौरान नियमों की अनदेखी की गई और आयुक्त द्वारा बीच बैठक में ही एएमसी को जिम्मेदारी सौंपकर चले जाना पूरी तरह अनुचित था। महापौर के अनुसार, बिना किसी आपात स्थिति के ऐसा निर्णय लेना बोर्ड की गरिमा और जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का उल्लंघन है।

महापौर ने 22 अप्रैल को जारी पत्र को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा 33 का गलत हवाला देकर नियमों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने निगम की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि शहर में जगह-जगह कचरे का अंबार लगा है, करोड़ों रुपये के वाहन बिना उपयोग के कबाड़ बनते जा रहे हैं और विकास कार्यों की कोई ठोस योजना नजर नहीं आ रही है। महापौर ने आरोप लगाया कि

उन्हें फाइलों का निरीक्षण करने नहीं दिया जा रहा, समीक्षा बैठक करने से रोका जा रहा है और योजनाओं की जानकारी भी साझा नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का सीधा हनन है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें मीडिया में बयान देने के लिए भी आयुक्त से अनुमति लेने को कहा जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है।महापौर अरविन्द कुमार राणा ने कहा कि आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को दरकिनार कर फाइलों का निपटान किया जा रहा है, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे जनहित के मुद्दों पर चुप नहीं बैठेंगे और जनप्रतिनिधियों के सम्मान व अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा।महापौर अरविन्द कुमार राणा ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच की मांग की है और नगर निगम में कानून व प्रोटोकॉल के सख्ती से पालन की आवश्यकता जताई है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए है।

स्ट्रीट फूड विक्रेताओं पर प्रशासन का सख्त एक्शन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू)। खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मेदिनीनगर शहर में स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के खिलाफ औचक निरीक्षण अभियान चलाया। मंगलवार और बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी लव कुमार गुप्ता के नेतृत्व में टीम ने शहर के प्रमुख इलाकों–रेड़मा चौक, रेलवे स्टेशन रोड, बेलावटिका चौक और गांधी मैदान रोड–पर स्थित गोलगप्पे (गुपचुप) एवं अन्य फास्ट फूड दुकानों और ठेलों की जांच की।

निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विशेष रूप से गोलगप्पे के मसाले, चोखा और चटनी में औद्योगिक रंगों के इस्तेमाल की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए गए इन खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी विक्रेताओं को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि खाद्य सामग्री बेचते समय मास्क, एप्रन और ग्लव्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। साथ ही स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ जार का ही इस्तेमाल सुनिश्चित करें।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

स्थानीय विधायक कल्पना सोरेन भी हुईं शामिल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। शहर के मक्तापुर रोड स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर में चल रहे मंदिर जीर्णोद्धार सह प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तीसरे दिन बुधवार को श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। कार्यक्रम में गांडेय के विधायक कल्पना सोरेन मंदिर परिसर पहुंचे और मां संतोषी के चरणों में माथा टेककर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ एसपी डॉ. विमल कुमार, डीडीसी स्मिता कुमारी, मेयर प्रमीला मेहरा उपनगर आयुक्त उप महापौर सुमित कुमार सहित कई गणमान्य लोग और समर्थक मौजूद रहे। सभी ने मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में प्रवेश के दौरान प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समिति के सदस्य प्रदीप अग्रवाल, शशीर साव, दिलीप केसरी, डिंपल साव, दीपक

मोदी और इन्दुन केसरी ने अतिथियों का भव्य स्वागत किया। मौके पर मौजूद महिलाओं ने गांडेय की कल्पना सोरेन को पारंपरिक परिधान पहनाकर तथा माता की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कल्पना सोरेन ने नव-निर्मित मंदिर की भव्यता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और एकता का संदेश देते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही।

एसपी पहुंचे सिविल कोर्ट परिसर, लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हजारीबाग। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक हजारीबाग द्वारा सिविल कोर्ट परिसर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिसकर्मियों को सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान एसपी ने परिसर में मौजूद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सतर्क एवं मुस्तैद रहने का निर्देश दिया। साथ ही, सिविल कोर्ट परिसर स्थित कार्यालय में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों को कार्यालयी कार्यों के निष्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कर्मियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा के साथ निभाने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त के जन समाधान दिवस में दिखी प्रशासनिक संवेदनशीलता

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू)। आज बुधवार को उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने समाहरणालय सभागार में जन समाधान दिवस का आयोजन किया, जहां प्रशासनिक संवेदनशीलता और तत्परता दोनों का स्पष्ट उदाहरण देखने को मिला। कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस हॉल के टेबल के बाएं तरफ आमजन एवं दाहिने तरफ संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी-अपनी समस्याएं उपायुक्त के समक्ष रखीं।आवेदनों के आधार पर उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को मामलों का त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया।

इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका चयन में अनियमितता,भू-माफिया द्वारा जमीन कब्जा,भूमि मापी,गलत रसीद,रास्ता अवरुद्ध,भू-अर्जन के बाद मुआवजा न मिलना,दोहरी जमाबंदी,ट्रांसफर,आपसी विवाद एवं जमीन ऑनलाइन नहीं होने जैसे कई मामले सामने आये।कुछ मामलों में उपायुक्त ने सीओ को ऑन स्पॉट कॉल कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। उपायुक्त श्री शेखावत ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि मामलों को अनावश्यक लंबित न रखें–या तो समाधान करें, अन्यथा स्पष्ट रूप से अस्वीकृत

करें।इसी दौरान एक भावुक कर देने वाला दृश्य भी सामने आया। सूचना मिली कि मेदिनीनगर की दिव्यांग महिला शीला कुमारी समाहरणालय पहुंची हैं, लेकिन दोनों पैरों से असमर्थ होने के कारण सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रही हैं।यह सुनते ही उपायुक्त स्वयं नीचे सीढ़ियों तक पहुंचे, उनसे मिलकर उनकी समस्या सुनी और संबंधित पदाधिकारी को त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि अब उन्हें दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जिला में 90दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान का शुभारंभ

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए), गिरिडीह द्वारा बुधवार को 90 दिवसीय सघन विधिक जागरूकता व जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया। यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डीएलएसए मार्तण्ड प्रताप मिश्रा के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है, जिसे तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। अभियान की शुरूआत सिविल कोर्ट परिसर से टावर चौक तक निकाली गई प्रभातफेरी से हुई। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारी, पैनल अधिवक्ता, मध्यस्थगण, पीएलवी एवं डीएलएसए कर्मियों ने भाग लिया और आम लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रत्येक गांव तक पहुंचकर जरूरतमंद लोगों की पहचान करना और उन्हें विधिक सहायता के साथ साथ सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है।

इसके तहत घर-घर जागरूकता अभियान, विधिक सशक्तिकरण शिविर, आईईसी सामग्री का वितरण और महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांगजनों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा मंडल कारा गिरिडीह में बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विचाराधीन बंदियों के मामलों की समीक्षा के साथ उनके परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनके जीवनयापन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।अभियान के सफल संचालन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिससे इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

आरके महिला कॉलेज की 18 कैडेट प्रशिक्षण के लिए रवाना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। आरके महिला कॉलेज की 18 एनसीसी कैडेट्स दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए हजारीबाग स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिलवार पहुंच गई हैं। यह शिविर 29 अप्रैल से 8 मई तक आयोजित किया जा रहा है। जिसमें कैडेट्स के सीएटीसी 1 के तहत विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगी। शिविर के दौरान कैडेट्स को शारीरिक शिक्षा, ड्रिल, योग, नेतृत्व क्षमता विकास, संचार कौशल, फायरिंग सहित कई महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिए जाएंगे। इसके साथ ही वे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगी। शिविर में रहते हुए टीएससी थल सैनिक कैंप के लिए प्रतिभागियों का चयन भी किया जाएगा, जिसमें ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, फायरिंग, हेल्थ एंड हाइजीन तथा जेडीएफएस जैसी

परीक्षाओं के माध्यम से अगले चरण के लिए चयन होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान कैडेट्स को एकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को समझने का अवसर मिलेगा। सभी कैडेट्स कॉलेज की सीटीओ डॉ. पूनम प्रभा मुंडु के नेतृत्व में हजारीबाग गई हैं। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. केएन शर्मा ने सभी छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस कैंप के माध्यम से न सिर्फ उनका प्रशिक्षण होगा, बल्कि उनकी प्रतिभा में निखार आएगा और उनमें नेतृत्व क्षमता का भी विकास होगा।

डीसी ने ली राजस्व विभाग के कार्यों की जानकारी

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पलामू। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बुधवार को रेवेन्यू विभाग की समीक्षा बैठक में भूमि अधिग्रहण एवं एनएच 75 परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।बैठक में भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं,

खनन कार्यों एवं विभिन्न लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान के सेक्शन- एवं सेक्शन-क्कक्के फोरलेन निर्माण कार्य की प्रगति पर चर्चा की गयी।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करते हुए परियोजनाओं में तेजी लाई जाए। भूमि अधिग्रहण के तहत प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कहा कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा विवादित मामलों का शीघ्र समाधान कर कार्य में बाधा न आने दी जाए। बैठक में विभिन्न कोल ब्लॉक्स एवं खनन परियोजनाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान पाया गया कि कुछ परियोजनाओं में भूमि हस्तांतरण, भुगतान लंबित रहने एवं स्थानीय स्तर की समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित है। इस पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया साथ ही म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।इस अवसर पर अपर समाहर्ता कुंदन कुमार,तीनों डीसीएलआर,जिला खनन पदाधिकारी समेत विभिन्न सीओ उपस्थित रहे।

हजारीबाग यूथ विंग ने की एसपी अमन कुमार से शिष्टाचार मुलाकात

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हजारीबाग यूथ विंग के प्रतिनिधिमंडल ने जिले के नवपदस्थापित पुलिस अधीक्षक अमन कुमार से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। संस्था के संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन एवं अध्यक्ष करण जायसवाल के निर्देश पर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, जिसमें सचिव रितेश खंडेलवाल, सह सचिव अभिषेक पांडे, कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद ताजुद्दीन, सत्यनारायण सिंह एवं उदित तिवारी उपस्थित रहे।प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को पुष्पगुच्छ एवं शॉल भेंट कर उनका स्वागत किया तथा हजारीबाग में उनके पदस्थापन पर शुभकामनाएं दीं। इस दौरान संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों की जानकारी दी गई। हाल ही में आयोजित रक्तदान शिविर का उल्लेख करते हुए बताया गया कि हजारीबाग पुलिस के सहयोग से आयोजित इस शिविर में 326 यूनिट रक्त संग्रह किया गया।

इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने छठ पूजा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा आगामी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की योजना से भी अवगत कराया। संस्था द्वारा जल्द ही जागरूकता रथ के माध्यम से एवं विद्यालयों में जाकर युवाओं और बच्चों को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक किया जाएगा।

पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की सेवा भावना समाज के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनहित के हर कार्य में पुलिस विभाग पूरा सहयोग करेगा।संस्था के संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन ने कहा कि हजारीबाग यूथ विंग समाजहित के कार्यों के लिए सदैव तत्पर रही है और पुलिस प्रशासन के सहयोग से इन प्रयासों को और व्यापक बनाया जाएगा। वहीं अध्यक्ष करण जायसवाल ने कहा कि संस्था का लक्ष्य सेवा के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाना है।

हुसैनाबाद में पेट्रोल को लेकर हाहाकार

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

पलामू। हुसैनाबाद शहर में इन दिनों पेट्रोल की भारी किल्लत से हाहाकार मचा हुआ है।अधिकांश पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।हालात यह हैं कि सुबह से ही पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। पेट्रोल की कमी का सबसे ज्यादा असर बाइक और कार चालकों पर पड़ रहा है। लोग जरूरी कामों के लिए भी अपने घरों से निकलने में असमर्थ हो रहे हैं। कई लोग पेट्रोल पंप तक पहुंचने के बाद खाली हाथ वापस लौट रहे हैं, जिससे नाराजगी भी बढ़ रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। शादी-विवाह, इलाज और अन्य आवश्यक कार्यों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।हालांकि, पेट्रोल की कमी के पीछे स्पष्ट कारण सामने नहीं आ पाया है।लेकिन इस समस्या का मुख्य कारण क्या हैं यह तो जाँच का विषय हैं, लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप कर पेट्रोल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है,

कोयलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स को मिली मान्यता

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। व्यवसायिक जगत के लिए एक अहम उपलब्धि सामने आई है। कोयलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सीसीआई को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एफजीसीसीआई से आधिकारिक मान्यता मिल गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए केसीसीआई के अध्यक्ष राहुल वर्मन ने बताया कि यह सफलता संगठन के सभी सदस्यों की अटूट मेहनत, समर्पण और निरंतर प्रयासों का परिणाम है।

उन्होंने इस उपलब्धि के लिए फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ रीजनल वाइस प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह सलूजा को भी बधाई दी। गौरतलब है कि जिले के व्यवसायियों और उद्यमियों के हितों की रक्षा एवं उनके विकास के उद्देश्य से करीब छह वर्ष पूर्व केसीसीआई का गठन किया गया था। गठन के समय से ही फेडरेशन से मान्यता प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। मान्यता मिलने के बाद संगठन के सदस्यों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

कॉपर तार लूटकांड का खुलासा, तीन अपराधी गिरफ्तार

पिकअप सहित 267 किलो तार बरामद

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। निमियाँघाट थाना क्षेत्र में विगत दिनों हुई बड़ी लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन के कार्य के दौरान कॉपर वायर लूटने वाले तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से भारी मात्रा में कॉपर तार, पिकअप वाहन और अन्य सामान बरामद किया है। जानकारी के अनुसार, डीबीसी निमियाँघाट सब स्टेशन के पीछे खेत में निमियाँघाट से मतारी सब स्टेशन तक रेलवे के माध्यम से केबल बिछाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने वहां तैनात गार्ड के साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। इसके बाद लगभग 193 मीटर कॉपर वायर अनुमानित मूल्य 15,58,316 काटकर लूट लिया गया था। साथ ही गार्ड अनिल कुमार महतो और रंजीत ठाकुर से

मोबाइल फोन और 5,000 नकद भी छीन लिया गया। इस मामले में निमियाँघाट थाना कांड संख्या 41/26 दर्ज किया गया था।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसडीपीओ डुमरी और पुलिस निरीक्षक डुमरी के नेतृत्व में गठित टीम ने तकनीकी और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया।गिरफ्तार आरोपी कल्लू कुमार उर्फ कल्लू पासी 23 वर्ष धनबाद राजू भुईयाँ उर्फ कारू भुईयाँ 25 वर्ष धनबाद नरेश भुईयाँ उर्फ बिट्टल कुटुम्ब भुईयाँ 32 वर्ष धनबाद पुलिस के अनुसार, तीनों का आपराधिक इतिहास रहा है और वे पहले भी विभिन्न मामलों में जेल जा चुके हैं।

गंदगी व पेयजल समस्या को ले माले ने उप नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गिरिडीह। शहर में गंदगी, पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा ने उप नगर आयुक्त से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को रखा। उन्होंने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण आम जनता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। श्री सिन्हा ने विशेष रूप से आकांक्षा कचरा गाड़ियों और पोल्ट्री (मुर्गा) ढोने वाली गाड़ियों को ढककर चलाने की मांग की। उनका कहना था कि बिना कवर के कचरा ढोने से रास्ते में गंदगी फैलती है, जिससे बदबू और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री वेस्ट खुले में ले जाने से संक्रमण फैलने का खतरा भी बना रहता है। उन्होंने नगर निगम से सभी नालियों को ढकने की व्यवस्था करने और इसके लिए जल्द टेंडर जारी कर कार्य शुरू कराने की मांग की। शहर में पेयजल समस्या को अविलंब दूर करने पर जोर दिया और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर वार्ड में नियमित रूप से फॉगिंग मशीन चलाने की मांग की।

उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान में केवल कुछ अधिकारियों के घरों के आसपास ही फॉगिंग की जा रही है, जबकि आम लोग परेशान हैं। इसके अलावा उन्होंने पुराने नगर निगम में पड़ी अत्याधुनिक गाड़ियों को उपयोग में लाने तथा खराब हो रही नई टेंपो को जल्द चालू कराने की भी मांग उठाई। सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई कर्मियों और निगरानी कर्मियों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत बताई। उप नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया कि नगर निगम अच्छे कार्यों के लिए हमेशा तैयार है और एक महीने के अंदर इन समस्याओं के समाधान का असर दिखने लगेगा। बैठक में अर्बन मैनेजर मंजूर आलम भी मौजूद थे। मौके पर सहयोगी मिराज खान और अविनाश कुमार भी राजेश सिन्हा के साथ उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

गिरिडीह में संतोषी माता महोत्सव में पहुंचीं विधायक कल्पना सोरेन

गिरिडीह, एजेंसी। झारखंड के गिरिडीह शहर के मकतपुर स्थित प्राचीन संतोषी माता मंदिर के जीर्णोद्धार और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे तीसरे दिन बुधवार को गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन मंदिर पहुंचीं। उन्होंने माता संतोषी के दरबार में माथा टेका और पूरे श्रद्धा भाव के साथ पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर पहुंचने पर आयोजक समिति के अध्यक्ष टुनटुन केशरी, सचिव डिम्पल साव, उपमेयर सुमित कुमार, सतीश साह, प्रदीप कुमार, प्रदीप चौरसिया, हब्लू गुप्ता, दीपक शर्मा, प्रदीप अग्रवाला, वीरेंद्र, सिंकल, विक्रम, रिशु, राकेश बरनवाल, संदीप डेंगेज, लखन बरनवाल, झुन्नू, कुशल सलूजा, बंटी, दिलीप केशरी समेत सदस्यों ने बुके देकर विधायक कल्पना सोरेन का स्वागत किया। पूजा के बाद उन्होंने आयोजन समिति को इस भव्य धार्मिक आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि संतोषी माता महोत्सव जैसे आयोजन समाज में आस्था के साथ-साथ सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार करते हैं।

नोवामुंडी प्रखंड में 10 आवासों का गृह प्रवेश, लाभुकों के चेहरों पर खुशी

नोवामुंडी, एजेंसी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी प्रखंड में मंगलवार को 'गृह प्रवेश' कार्यक्रम के तहत अलग-अलग पंचायतों में करीब 10 आवासों में लाभुक परिवारों को विधिवत प्रवेश कराया गया। अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने इन घरों में प्रवेश के साथ पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया। कादाजामदा पंचायत के जामपानी गांव में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में एलआरडीसी अनीता केरकेट्टा ने नारियल फोड़कर और फीता काट कर नए आवास का शुभारंभ किया और लाभुकों को गृह प्रवेश कराया। इस मौके पर अंचल अधिकारी मनोज कुमार और बीडीओ पप्पू रजक भी मौजूद रहे। सुंदरी नायक और कैरि चातार सहित अन्य लाभुकों को उनके नए घरों में प्रवेश दिलाया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का ग्रामीणों द्वारा गुलदस्ता देकर स्वागत और सम्मान किया गया।

श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर डीआईजी अंबर लकड़ा ने की समीक्षा बैठक

दुमका, एजेंसी। झारखंड के संथाल परगना प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) अंबर लकड़ा की अध्यक्षता में बुधवार को दुमका में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमंडल के सभी छह जिलों के पुलिस अधीक्षक शामिल हुए और क्षेत्र की कानून-व्यवस्था से जुड़े अलग-अलग अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकिनाथ धाम में आगामी श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं को लेकर रणनीति बनाई गई, जिससे कि मेले के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इसके अलावा, क्षेत्र में अपराध नियंत्रण को और सशक्त बनाने, लंबित कांडों के त्वरित अनुसंधान, साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश और आम लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उपायों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। डीआईजी ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने जिलों में संवेदनशील मामलों पर विशेष निगरानी रखें और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान यह भी जोर दिया गया कि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जाए और लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं। साथ ही, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों के सख्त अनुपालन और जनजागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही गई।

कोडरमा में महुआ की लालच में जंगल में आग लगा रहे लोग

कोडरमा, एजेंसी। वन प्रमंडल कोडरमा इन दिनों जंगली हाथियों के आबादी वाले क्षेत्र में आने से इन्हें जंगल की ओर भगाने में जुटा है तो वहीं दूसरी ओर एक अलग चुनौती विभाग के सामने आ रही है। ग्रामीण इलाकों में इन दिनों महुआ चुनने और इसे जमा करने पर लोगों का जोर है तो कुछ लोग जंगल क्षेत्र में स्थित पेड़ से गिरने वाले महुआ को चुनने के लिए जंगल में आग लगा दे रहे हैं। जंगल में आग लगाने के बाद इसे तुरंत बुझाना वन विभाग के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ऐसे समय में जब अधिकतर कर्मी हाथियों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर जंगल में रखने और कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने में जुटे हैं तो आग की घटनाएं काम को और बढ़ा रही है। हालांकि, इस दबाव के बावजूद विभाग आग की इन घटनाओं पर तुरंत काबू पाने में जुटा है। पिछले करीब ढाई माह में जंगल में महुआ चुनने को लेकर आग लगा देने की 34 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आग लगने की सूचना समय पर मिलने के बाद विभाग ने इन जगहों पर टीम भेजकर आग बुझा भी दी, पर जंगल क्षेत्र का नुकसान जरूर हुआ। इस बीच जंगल क्षेत्र में महुआ चुनने के दौरान आग लगने की घटनाएं कम हो इसको लेकर विभाग कई स्तर से प्रयास कर रहा है।

पेसा पर राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस

अब कागजी दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेगी नियमावली- मंत्री

रांची, एजेंसी। पेसा नियमावली पर रांची में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यस्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के। राजू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।

इस कॉन्फ्रेंस में पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड में पेसा नियमावली अब कागजी दस्तावेज तक सीमित होकर नहीं रहेगा बल्कि यह धरातल पर नजर आएगा। राज्य के गांव-पंचायत तक पेसा नियमावली को मजबूती से लागू करने के लिए सरकार के सभी विभाग संयुक्त रूप से जोर लगाएंगे। इसके साथ ही राज्य में पेसा कॉर्डिनेशन कमेटी का गठन प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर पर किया जाएगा। जिससे इसकी लगातार समीक्षा और अड़चनों का समय सीमा के अंदर निदान हो सके।

राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित क्षेत्रों में प्रभावी स्वशासन की स्थापना के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। इसमें नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के राजू ने कहा कि देश भर में झारखंड का सबसे बेहतर है पेसा नियमावली बनाने वाला राज्य है। आज के कॉन्फ्रेंस में विभागीय सचिव मनोज कुमार, निदेशक राजेश्वरी बी सहित विभागीय एवं सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली आदिवासी क्षेत्र की व्यापक मांग को पूर्ण करता है। आने वाले समय में झारखंड का पेसा नियमावली देश का मॉडल साबित हो इस दिशा में काम किया जा रहा है। सहायक सचिव के पद पर पहली बार महिलाओं को प्राथमिकता दिया जाना, ग्राम सभा में आधी आबादी के अधिकार को मजबूती प्रदान करता है।मंत्री ने कहा कि जब पेसा नियमवाली का प्रस्ताव कैबिनेट में आने वाला था तब उन्हें रात भर नींद नहीं आई, उनके मन में बस एक ही सवाल था कि एक समुदाय के साथ न्याय करना है। दृढ़ इच्छा शक्ति और पेसा नियमवाली को लेकर ज्यादा से ज्यादा विचार-विमर्श के बाद इसे लागू किया गया।

उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में गैर आदिवासी प्रधान का मामला विभाग के संज्ञान में है। इस मामले में सरकार अपने स्तर पर पहल करेगी। पेसा नियमावली का लाभ कैसे ज्यादा से ज्यादा अनुसूचित क्षेत्र के लोगों को मिले इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। इस नियमावली के तहत ग्राम सभा को मिलने वाले अधिकार को जानना-समझना और उसे पाने के लिए सकारात्मक पहल करना हम सभी की जवाबदेही है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के पूर्व सदस्य के राजू ने कहा कि झारखंड का पेसा नियमावली देश का सबसे बेहतर नियमावली है। ये बात राष्ट्रीय स्तर के नीति निर्धारण और नियमावली का अध्ययन करने वाले भी मान चुके हैं। बेहतर नियमावली को धरातल पर उतारने के लिए अब हम सभी को अपनी-अपनी भूमिका अदा करनी होगी। देश के दूसरे राज्यों में जहां पेसा नियमवाली बने है वहां वो प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सके है। झारखंड को इस मिथक को तोड़ते हुए इस नियमावली से अनुसूचित क्षेत्र के अधिकार को संरक्षित करने के साथ, उन्हें प्रभावी बनाना है।

हमारा उद्देश्य पॉवर को सेंट्रलाइज रखना नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइज करना है। के राजू ने कहा कि पेसा नियमावली सिर्फ पंचायती राज विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि इसे मजबूती प्रदान करने में सरकार के सभी विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगले दो से तीन साल में झारखंड के पेसा नियमवाली को देश का मॉडल के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य तय करना होगा।

उन्होंने विभागीय मंत्री के समक्ष इसके लिए पेसा कॉर्डिनेशन कमिटी का गठन करने की सलाह दी। इसके साथ ही पेसा नियमवाली के तहत किए जा रहे कार्य और महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी टीएसी को देने का भी विचार रखा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सचिव मनोज कुमार ने कहा कि ये नियमावली गांव के बदलाव और उसके हक अधिकार के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। विभाग इस नियमावली को स्थानीय भाषा में भी गांव के लोगों को उपलब्ध करा रही है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस नियमावली से मिलने वाले अधिकार को जान सकें। उन्होंने कहा कि नियमावली की जानकारी के लिए प्रशिक्षण से लेकर वृहद प्रचार प्रसार भी चलाया जा रहा है।

इस कॉन्फ्रेंस को पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने संबोधित करते हुए कहा कि इस नियमावली को तैयार करने से पहले दो बार डेढ़-डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों की आपत्तियों को विभाग ने ग्रहण किया है।

जामताड़ा में भोजपुरी गायिका देवी ने बिखेरा सुरों का जादू, अपने गीतों से लोगों को किया मंत्रमुग्ध

जामताड़ा, एजेंसी। भोजपुरी जगत की मशहूर गायिका देवी के भक्ति जागरण कार्यक्रम में श्रद्धालु जमकर झूमे। देवी के भजन गीत सुनने और उनको देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। उन्होंने भी अपने भक्ति भजन और गीत से लोगों को खूब झुमाया।

जामताड़ा के मटटार गांव में चल रहे नौ दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान महायज्ञ में आयोजित भक्ति जागरण में भोजपुरी गायिका देवी ने अपने भजन से लोगों को खूब झुमाया। भक्ति जागरण कार्यक्रम में मशहूर भोजपुरी गायिका देवी को देखने और उनके गीतों को सुनने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। भोजपुरी सिंगर देवी ने अपने भजनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के मटटार गांव में पार्वती मंदिर में मां देवी की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर शिव शक्ति महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया। जहां अयोध्या से आए कथा वाचक द्वारा भव्य राम कथा का प्रवचन चला। वहीं, भजन कीर्तन, भव्य मेला एवं भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया।

जागरण कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कलाकारों ने अपना भजन प्रस्तुत किए। बीते रात आयोजित भक्ति जागरण कार्यक्रम में भोजपुरी की मशहूर सिंगर देवी ने भी भक्ति जागरण प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अपने भजनों और गानों से भक्तों का मनोरंजन किया। इस मेले और अनुष्ठान में हिस्सा लेने के लिए दूर-दूर से भक्त पहुंच रहे हैं।

गिरिडीह गोलगप्पा कांडः सफाई का नहीं है ख्याल

जिले में 8 सौ से अधिक चाट-गोलगप्पे बेचने वाले

गिरिडीह, एजेंसी। चाट-गोलगप्पे का व्यवसाय पूरी तरह से बेहतरीन स्वाद और विश्वास पर टिका हुआ है। लोग इस विश्वास से ठेले-खोमचे वालों से गोलगप्पा या चाट खरीद कर खाते हैं कि विक्रेता ने अच्छी सामग्री और सफाई का ध्यान दिया होगा। लेकिन यह विश्वास गिरिडीह के गोलगप्पा कांड से टूट गया है।

गोलगप्पा खाने के बाद 49 लोगों के बीमार पड़ने जिसमें एक की मौत हो जाने की घटना के बाद गुणवत्ता ओर सफाई पर सीधा सवाल उठने लगा है। यहां एक बात तो साफ हुई कि गोलगप्पा विक्रेता ओभी लाल रजक ने लापरवाही की। लापरवाही जानबूझ कर की गई या कैसे हुई इसकी जांच जारी है।

उन्होंने बताया कि गोलगप्पा का पानी बनाने में मात्र सौ से डेढ़ सौ रुपया का ही खर्च आता है। गोलगप्पा बेचने के दौरान विक्रेता को कई दफा पानी में हाथ डालना पड़ता है, ऐसे में एक ही दिन में गोलगप्पा का पानी खराब हो जाता है। इसलिए पानी को किसी भी हाल में दूसरे दिन यूज नहीं करना है। उनका कहना है कि गोलगप्पा कांड में पानी ही खराब हुआ होगा, जिसका उपयोग किया गया और लोगों की तबियत बिगड़ गई। गंगा बताते हैं कि गोलगप्पा कांड के बाद बिक्री पर इसका असर दिखा है। ग्राहक कम संख्या में आए हैं। गंगा कहते हैं कि विक्रेता को सबसे पहले सफाई का ध्यान रखना होगा। लोग विश्वास के साथ ठेला पर आते हैं। वहीं, विक्रेता गोपाल राम कहते हैं कि घटना गंभीर है। अब देखते हैं इसका कितना असर दुकानदारी पर पड़ता है।

इधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजा कुमार कहते हैं कि जिले में गोलगप्पा-चाट बेचने वालों की संख्या लगभग आठ सौ है। इनमें से बहुत से लोगों ने निबंधन नहीं करवाया है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी वाली है। इतना ही नहीं हर ठेला में जाकर चेक करने का काम शुरू किया गया है। जो लोग सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं या फूड कलर के नाम पर घटिया रंग सामग्री में डालते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई तय है। उन्होंने बताया कि गोलगप्पा कांड के बाद विक्रेता के घर पर छापेमारी की गई थी। इनके यहां से चम्पई रंग मिला था, जो सेहत के लिए सही नहीं है।

वैसे तो इस घटना के बाद कार्रवाई हुई और विक्रेता को जेल भी भेजा गया लेकिन इस प्रकरण ने निश्चित तौर पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाया है।

चाईबासा में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़, रुक-रुककर फायरिंग जारी

चाईबासा, एजेंसी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में बुधवार तड़के एक बार फिर नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। यह मुठभेड़ उस वक्त हुई जब रूट्गुटू के घने जंगलों में चल रहे सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा 209 बटालियन के जवान गश्त पर निकले थे।

जानकारी के अनुसार, सुरक्षा बल पिछले दो दिनों से गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोरोई और तूनबेड़ा के आसपास लगातार सर्च अभियान चला रहे है। इसी क्रम में बुधवार सुबह करीब साढ़े चार बजे जवानों की टीम जैसे ही जंगल के भीतर आगे बढ़ी, पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों से उनका सामना हो गया। इसके बाद दोनों ओर से तेज फायरिंग शुरू हो गई। मुठभेड़ सुबह से बीच-बीच में जारी रही, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सुरक्षा बलों ने क्षेत्र को घेराबंदी कर दी है और अतिरिक्त जवानों को भी अलर्ट पर रखा गया है। सर्च ऑपरेशन को और तेज करते हुए आसपास के जंगलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेनू ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है। जवान पूरी सतर्कता के साथ स्थिति को संभाल रहे हैं।

बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एक पूर्व माओवादी की हत्या के बाद से इस इलाके में गतिविधियां बढ़ने की आशंका जताई जा रही थी। माओवादी नेता मिसिर बेसरा के नेतृत्व में संगठन अभी भी इस क्षेत्र में सक्रिय है और अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।

सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही इनपुट मिले थे कि सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में माओवादी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। मुठभेड़ ने इन आशंकाओं को और पुख्ता कर दिया है। फिलहाल पूरे इलाके में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।

हजारीबाग में पत्रकार के साथ बदसलूकी और हाथापाई, मंत्री के सामने हुई घटना

हजारीबाग, एजेंसी। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल करने पर असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार और मारपीट की है।

इस घटना पर पत्रकारों ने सदर थाना में आवेदन दिया है। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोकतंत्र के चौथे स्थान पर हमला का निंदा किया है। इसपर सदर विधायक ने कहा कि पत्रकारों का काम है सवाल करना है। जिस तरह से मारपीट और अभद्र व्यवहार किया जाएगा वो सरासर गलत है। लोकतंत्र में ऐसी घटना का जगह नहीं है।

हजारीबाग शेख भिखारी कॉलेज अस्पताल परिसर में पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की घटना घटी है। दरअसल हजारीबाग में तीन संदिग्ध मौत की जानकारी लेने के लिए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे। इस दौरान जहां इन्होंने परिजनों से वार्ता किया और प्रशासन को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

दूसरी ओर पत्रकार के सवाल पर वहां उपस्थित असामाजिक तत्वों ने मंत्री के सामने ही पत्रकारों के साथ बदसलूकी और हाथापाई कर दी। आलम यह रहा कि एक पत्रकार को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ा। इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। एक पत्रकार को जान बचाकर भागना पड़ा।

महत्वपूर्ण बात यह है कि घटना के समय जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद थी। घटना के बाद पत्रकारों में काफी आक्रोश है कि आखिर सवाल करने पर तकलीफ वहां उपस्थित लोगों को क्यों हुई। मंत्री के सामने घटना घटने के बाद मंत्री ने बीच बचाव क्यों नहीं किया।

इसकी जानकारी मिलने पर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद पत्रकारों से मुलाकात करने पहुंचे और इस घटना पर दुख जाहिर किया। विधायक ने कहा कि वह हमेशा पत्रकारों के साथ खड़े हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हजारीबाग में अपना दायित्व को पूरा कर रहा है। मंत्री के सामने घटना घटी है और उन्होंने घटना को रोकने तक का भी प्रयास नहीं किया यह काफी निंदनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से घटना पर संज्ञान लेने की मांग कि है।

कैबिनेट के फैसले से सिर्फ सरकार का अहंकार बढ़ा: जेटेट और वंशीधर नगर के नाम पर भानु प्रताप शाही का हमला

गढ़वा, एजेंसी। झारखंड कैबिनेट के हालिया फैसलों को लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है। जेटेट की सूची से क्षेत्रीय भाषाओं को बाहर रखने और श्री वंशीधर नगर के नाम में बदलाव को लेकर विपक्ष ने हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोला है।

पूर्व मंत्री सह भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही ने जेटेट की सूची से क्षेत्रीय भाषाओं को बाहर रखने और श्री वंशीधर नगर के नाम में 'उंटारी' शब्द जोड़े जाने पर हेमंत सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से जनता का कोई भला नहीं होने वाला, बल्कि यह केवल सत्ता के अहंकार की पूर्ति है। भानु प्रताप शाही ने जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि यह मांग केवल भाजपा की नहीं थी, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी उठाई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब झामुमो केंद्रीय महासचिव सह पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह जैसे नेता इसकी मांग कर रहे थे, तो कैबिनेट ने इसे अनसुना क्यों किया?

कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के बीमार होने पर तंज कसते हुए भानु ने कहा वह वास्तव में बीमार हैं या मुख्यमंत्री का मूड भांपकर उन्होंने चुप्पी साध ली, यह जांच का विषय है। श्री वंशीधर नगर के नाम में 'उंटारी' शब्द जोड़े जाने को भानु प्रताप शाही ने विधायक अनंत प्रताप देव की 'राजशाही आकांक्षा' करार दिया।

पलामू के पिपराटांड़ में गोली मारकर हत्या

घर से बाहर बुलाया फिर सिर में मार दी गोली

पलामू, एजेंसी। जिले के पिपराटांड़ थाना क्षेत्र के कर्मा गांव में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने 65 वर्षीय राजमुनी पाठक के सिर में गोली मारी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन कर रही है। मृतक की पहचान कर्मा गांव निवासी राजमुनि पाठक के रूप में हुई है।

बताया जा रहा है कि मंगलवार की देर रात राजमुनि पाठक अपने घर में सोए हुए थे। इसी दौरान कुछ लोग घर में पहुंचे और किसी बहाने से उन्हें बाहर बुलाया। इसके बाद घर से करीब 200 मीटर दूर ले जाया गया। जहां आरोपियों ने राजमुनि पाठक के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त घर में उनकी पत्नी मौजूद थी। जबकि उनके दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं।

पिपराटांड़ थाना प्रभारी निलेश कुमार ने बताया कि गोली मारकर हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। प्रारंभिक जानकारी में परिजनों ने जमीन विवाद की बात बताई है, लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर अनुसंधान कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि अंजान लोग राजमुनी पाठक को घर से बुलाकर ले गए, उस दौरान पत्नी ने भी ध्यान नही दिया। सुबह मृतक का शव बरामद हुआ है।

मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू किया गया है।

इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं परिजन मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों ने पुलिस को बताया कि कर्मा इलाके में किसी के साथ राजमुनि पाठक का पांकी के कुछ लोगों के साथ जमीन का विवाद चल रहा है।

सरायकेला-खरसावांः भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा विभाग का निर्देश, स्कूलों में लगेगा वाटर बेल

सरायकेला, एजेंसी। झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिला में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा ने जिले के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों के लिए निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश में निश्चित अंतराल पर वाटर बेल को लागू करने और बच्चों के लिए स्कूल में ठंडा पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने की बात कही है। डीईओ ने सभी विद्यालयों को इस निर्देश का कड़ाई के साथ पालन करने का निर्देश दिया है। डीईओ ने बताया कि भीषण गर्मी में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे डिहाइड्रेशन का खतरा ना रहे। उन्होंने कहा कि बच्चे अकसर पानी बहुत कम पीते हैं और खेल खुद में पसीना अधिक बहाते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। उन्होंने बताया कि वाटर बेल के माध्यम से विद्यालय संचालन के दौरान कम से कम तीन बार एक साथ सभी बच्चों को पानी पीने के लिए छुट्टी दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक खुद मौजूद रहकर बच्चों को पानी पीने के लिए प्रेरित करेंगे।

डीईओ ने सभी विद्यालय प्रबंधन को अपने अपने विद्यालय में बच्चों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके तहत विद्यालय प्रबंधन की ओर से विद्यालयों में मिट्टी के घड़े और वाटर कूलर लगाने की बात कही है, जिससे बच्चों को शीतल जल उपलब्ध हो सके।

भीषण गर्मी को देखते हुए डीईओ ने सभी विद्यालयों को विद्यालय के फर्स्ट एड किट में पर्याप्त मात्रा में ओआरएस और ग्लूकोज रखने का निर्देश दिया है। इस भीषण गर्मी में बच्चों की तबियत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत प्राथमिक उपचार पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही डीईओ ने सभी शिक्षकों को प्रार्थना सभा के दौरान बच्चों को हाइड्रेटेड रहने के लिए जागरूक करने की बात कही है।

पुलिस मुठभेड़ में कार्यपालक पदाधिकारी का हत्यारा ढेर

राजनीति में रखता था रसूख

लड़ चुका था विस का चुनाव

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

भागलपुर। जिले के सुल्तानगंज मेंदिनदहाड़े नगर परिषद कार्यालय में घुसकर कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या और सभापति पर जानलेवा हमला, यह साबित करता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके थे। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया, जब जांच की परतें खुलीं और आरोपी कोई बाहरी नहीं, बल्कि सत्ता के बेहद करीब का आदमी निकला।

सीसीटीवी फुटेज ने सच्चाई को बेनकाब कर दिया। मुख्य आरोपी रामधनी यादव, जो उपसभापति का पति था, वही इस खूनी खेल का मास्टरमाइंड निकला। उसने अपनी पत्नी नीलम देवी 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के टिकट पर सुलतानगंज से विधानसभा चुनाव भी लड़वाया था।

मंगलवार सुबह जब पुलिस रामधनी यादव को हथियार बरामदगी के लिए ले जा रही थी, तब उसने अज्ञात अपराधियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर ही गोलियां बरसा दीं। लेकिन इस बार जवाब भी उतना ही सख्त था, बिहार पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए उसे ढेर कर दिया।

इस मुठभेड़ में डीएसपी नवीन, इंस्पेक्टर परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय घायल हो गए। तीनों का इलाज चल रहा है।

एक आरोपी मारा जा चुका है, दूसरा घायल है। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है- उस पूरे नेटवर्क को उजागर करना, जिसने इस साजिश को जन्म दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी को हथियार बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने अपने सहयोगियों के साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। उन्होंने बताया कि घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

टीबी उन्मूलन को लेकर सौ दिवसीय अभियान तेज

एक्सरे से मरीजों की पहचान एवं उपचार पर जोर

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान एवं प्रभावी उपचार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा संचालित सौ दिवसीय विशेष अभियान (24 मार्च से जून के अंत तक) को गति देने के लिए स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार द्वारा आज जिले के सभी सीनियर टीबी सुपरवाइजर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की गई।

इस दौरान डीपीएम मो. अनवर आलम ने अभियान से सम्बंधित सभी सुपरवाइजर को निर्देश दिया कि टीबी रोग के लिए जोखिमपूर्ण आबादी में से मरीजों की पहचान कर उन्हें जांच एवं उपचार से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि सघन घर-घर सर्वे, संपर्क जांच (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग) तथा हाई-रिस्क क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि कोई भी मरीज छूट न जाए। निर्देशित किया कि जांच की संख्या बढ़ाई जाए, चेस्ट एक्स-रे में स्पॉट मिलने की स्थिति में सीबी-नाट टेस्ट कराया जाए। नेशनल लेवल पर सर्वे के अनुसार ओपीडी मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जाए क्योंकि दस प्रतिशत ओपीडी केस टीबी पॉजिटिव आ सकते हैं। डिफरेंशियल टीवी के केस में लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट एवं सीबीसी जांच करा कर निक्षय पोर्टल पर रियल टाइम एंट्री किया जाए। साथ ही, मरीजों को नियमित दवा सेवन के प्रति जागरूक करने एवं उपचार पूर्ण कराने पर विशेष बल दिया गया।

वीसी में यह भी कहा गया कि अभियान की सफलता के लिए सभी स्वास्थ्य कर्मियों के बीच समन्वय आवश्यक है। उन्होंने फील्ड में सक्रियता बढ़ाने और लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया।

स्वास्थ्य विभाग के इस प्रयास से जिले में टीबी उन्मूलन अभियान को नई गति मिलने की उम्मीद है। बैठक में जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉ. रवि रंजन एवं इंचार्ज डीपीसी अजीत शर्मा भी उपस्थित रहे तथा आवश्यक निर्देश दिए।

दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बने रिजवान खान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी में दूसरी बार जिला उपाध्यक्ष बनने पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी एवं जुझारू जिला अध्यक्ष विमला कुमारी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा की पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है। मैं ईमानदारी पूर्वक निभाऊंगा एवं पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहूंगा और नए उत्साह के साथ काम कर पार्टी एवं संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे ।अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक करूंगा और समर्पण भाव से कार्य करते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का कार्य करेंगे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एवं आम जनता की आवाज को गांव-गांव तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ।

पोखर में डूबने से दो चचेरे भाईयों की मौत

एकमा थाना क्षेत्र के फुचटी कला गांव की घटना

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

एकमा (सारण)। जिले के एकमा थाना क्षेत्र के फुचटी कला गांव में बुधवार की शाम एक हृदय विदारक घटना में एक ही परिवार के दो चचेरे भाइयों की पोखर में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है ।जबकि परिजनों में कोहराम मच गया।

मृतकों की पहचान रमेश राय के 9 वर्षीय पुत्र गुड्डू कुमार और रविन्द्र यादव के 8 वर्षीय पुत्र अक्षय कुमार के रूप में हुई है। दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई थे और गांव के अन्य बच्चों के साथ पास के पोखर में स्नान करने गए थे।

ग्रामीणों के अनुसार बुधवार की अपराह्न करीब तीन बजे पांच बच्चे पोखर में नहा रहे थे। इसी दौरान एक बच्चा गहरे पानी में चला गया और

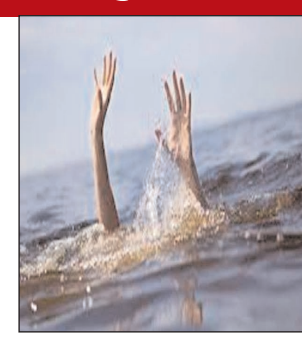

डूबने लगा। उसे बचाने के प्रयास में दूसरा बच्चा भी गहराई में पहुंच गया और दोनों की डूबने से मौत हो गई। साथ मौजूद अन्य तीन बच्चे किसी तरह बाहर निकलकर गांव पहुंचे और घटना की जानकारी दी।

सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भारी भीड़ पोखर के पास जुट गई। काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मामले में मृतक के पिता रमेश राय ने इसे दुर्घटना बताते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराने का आवेदन दिया। थानाध्यक्ष राम बालक यादव ने बताया कि परिजनों के अनुरोध पर शव का पंचनामा तैयार कर उन्हें सौंप दिया गया है।

घटना के बाद से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों परिवारों में शोक की गहरी छाया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने पोखरों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

ट्रक से कुचलकर युवक की मौत

बेगूसराय। खगड़िया से मुंगेर बारात में शामिल होने जा रहे दो युवकों की बाइक को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा एनएच-333बी पर साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के हीरा टोल जीरोमाइल से मुंगेर पुल के बीच देर रात हुआ।

जानकारी के अनुसार, खगड़िया जिले के रहीमपुर निवासी विनय कुमार की शादी मुंगेर जिले के नौवागढ़ में थी। परिवार के अधिकांश लोग चारपहिया वाहन से बारात में गए थे ।जबकि 23 वर्षीय अजय कुमार मंडल अपने साथी संजीत कुमार मंडल के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलते ही साहेबपुर कमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

जरूरतमंदों को नहीं मिला आवास योजना का लाभ

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

डोभी/गयाजी। प्रखंड क्षेत्र के पचरतन पंचायत अंतर्गत अमारूत मे कई जरूरतमंद परिवार आज भी आवास योजना के लाभ से वंचित हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी आवास योजना के बावजूद गरीब एवं असहाय परिवार अब भी कच्चे और जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। अमारूत ग्राम निवासी जनार्दन पाठक जी का कहना है कि सिर्फ भोट के समय नेता आते हैं कई वादे कर जाते हैं। पर उस वादे पर खरे नहीं उतरते हैं जरूरतमंदो को लगातार कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता हैं। बरसात और गर्मी के दिनों में जर्जर घरों में रहने से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में कई ऐसे परिवार हैं, जिन्हें अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला। स्थानीय ग्रामीणों का कहना हैं, की सम्बंधित बिभाग को सर्वे कर जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिलना चाहिए ताकि गरीबों को पक्का घर का सपना पूरा हो सके।

शादी से लौट रहे सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

आरा। भोजपुर जिले के कोईलवर थाना क्षेत्र अंतर्गत आरा-पटना हाईवे पर कोईलवर अंडरपास के समीप बुधवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित पिकअप वाहन ने बाइक सवार दो युवकों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र के कटेसर गांव निवासी नंदा महतो के 35 वर्षीय पुत्र अमित कुमार तथा बृजनंदन सिंह के 30 वर्षीय पुत्र सुजीत कुमार के रूप में हुई है। दोनों आपस में मित्र थे और शादी समारोह से लौट रहे थे।

हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन समेत फरार हो गया। प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और अनियंत्रित वाहन बताया जा रहा है।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। फरार पिकअप वाहन की पहचान कर उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

सुजीत कुमार पेशे से सीएसपी संचालक थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सुजीत कुमार अपने मित्र अमित के साथ अपनी भांजी की शादी में शामिल होने के लिए आरा मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महुली गांव गए थे।

₹धरती बचाओ अभियान₹के तहत पंचायत स्तरीय कमिटी गठित

मेदिनीनगर (पलामू)। हैदरनगर प्रखंड के इमामनगर बरेवा पंचायत सचिवालय सभागार में ₹धरती बचाओ अभियान₹के तहत किसानों के साथ जागरुकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस मौके पर उर्वरकों को संतुलित उपयोग के लिए पंचायत स्तरीय कमिटी का गठन किया गया। जिसमें मुखिया को अध्यक्ष, सदस्य पंचायत सचिव शैलेन्द्र चौधरी व योग्य किसान रेशमी देवी, बीरेंद्र सिंह का नाम शामिल किया गया है। इस कमेंटी का गठन सहायक तकनीकी प्रबंधक परवीन जहां ने किया। उन्होंने बताया कि निगरानी कमेटी का उदेश्य पंचायत स्तर पर किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरुक करना है। इस अभियान के तहत रासायनिक खाद की जगह जैविक उर्वरकों उपयोग करने की सलाह दी गई। यह अभियान मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर किसानों को जागरुक ही किया गया। इसी तरह का कार्यक्रम हैदरनगर पश्चिमी पंचायत में आयोजित कर वहां पर भी पंचायत स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया गया। इस अवसर पर मुखिया शहनाज परवीन, पंचायत समिति सदस्य गुलशन आरा, फरहाना खातून, समाजसेवी सज्जू खान, अशरफ हसन, राजू खान सहित कई योग्य किसान मौजूद थे।

सड़क हादसे में मौत

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बिहारशरीफ। थाना क्षेत्र के चरुईपर गांव में मंगलवार की देर रात बिहटा सरमेरा फोरलेन पर हुए सड़क हादसे में एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक आरजू पासवान थे।

मृतक के भांजे सुदामा पासवान ने बताया कि उनके घर में छोटी बेटी की शादी थी, बरात नाचते-गाते दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। घर में पारंपरिक रस्म ह्यसमधी मिलनह्ल की तैयारी चल रही थी।

इसी दौरान वे समधी से मिलने के लिए घर से निकले। जैसे ही वे पास के फोरलेन सड़क पर पहुंचे, तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वे सड़क पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

इस खबर के मिलते ही शादी वाले घर में खुशियों का माहौल पल भर में मातम में बदल गया। परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे किसी तरह भारी मन से शादी की रस्में पूरी कराई गईं।

आपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने लौटाये 202 मोबाइल

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हाजीपुर। बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत वैशाली पुलिस ने 202 लोगों के चोरी या गुम हुए मोबाइल बरामद कर वापस लौटाए। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 50 लाख रुपये आंकी गई है।

एसपी विक्रम सिहाग ने बुधवार को पुलिस कार्यालय सभागार में आयोजित समारोह में मोबाइल धारकों को उनके फोन सुपुर्द किए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। कई लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन की सक्रियता से ही उनका मोबाइल वापस मिल पाया। बर्ष 2026 में अब तक कुल 731 मोबाइल वास्तविक धारकों को लौटाया गया।

एसपी ने बताया कि बीते 30 मार्च को ऑपरेशन मुस्कान के तहत

165 मोबाइल धारकों को मोबाइल लौटाए गए थे। वहीं 2024 से अब तक जिले में कुल 1694 मोबाइल धारकों को उनके फोन वापस सौंपे जा चुके हैं। 25 जनवरी को 200 मोबाइल,25 फरवरी को 164 मोबाइल ,30 मार्च को 165 मोबाइल एवं 29 अप्रेल को 202 मोबाइल धारकों को वापस करवाया गया है।

एसपी ने बताया कि मोबाइल चोरी या गुम होने पर थाने में सनहा दर्ज कराने के बाद जिला आसूचना इकाई और सभी थानों की टेक टीम सीईआईआर पोर्टल के जरिए लगातार मोबाइल बरामद कर रही है। मोबाइल कैसे और कहां से बरामद हुआ, यह अनुसंधान का विषय है।

एसपी ने वैशाली जिलावासियों से अपील की कि यदि किसी का मोबाइल चोरी या गुम हो जाए तो तुरंत नजदीकी थाने में इसकी शिकायत करें। इसके लिए सभी थानों में एक टीम बनाई गई है। सीईआईआर पोर्टल पर मोबाइल का विवरण अपलोड किया जाता है, जिससे मोबाइल तुरंत ब्लॉक हो जाता है। उन्होंने बताया कि मोबाइल में प्रयुक्त सिम के माध्यम से संभावित वित्तीय लेनदेन पर भी रोक लग जाती है। मोबाइल चोरी के बाद उसके दुरुपयोग की आशंका भी समाप्त हो जाती है। मोबाइल दोबारा सक्रिय होने पर पुलिस को नोटिफिकेशन मिल जाता है,

दो बंद घरों को चोरों ने खंगाला

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

औरंगाबाद। शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने एक बार फिर स्थानीय निवासियों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला वार्ड संख्या 11 स्थित कांदुराम की गड़ही इलाके की है, जहां सोमवार की रात चोरों ने दो बंद घरों को निशाना बनाते हुए लगभग दो लाख रुपये की संपत्ति चुरा लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत और असुरक्षा का माहौल व्याप्त है। पहली घटना शत्रुघ्न चंद्रवंशी के घर की है। गृहस्वामी सोमवार की शाम अपने घर में ताला बंद कर सूर्य मंदिर के पास आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे ।मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे जब वापस लौटे, तो घर का मंजर देखकर दंग रह गए। चोरों ने मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और बक्सों की कुंडी काटकर उसमें रखे 40 हजार रुपये नकद समेत सोने-चांदी के कीमती जेवरात चुरा लिए।

पीड़ित परिवार की सदस्य सुरभि कुमारी ने तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने उसी घर के पास स्थित संध्या देवी के बंद मकान को निशाना बनाया। गृहस्वामी के अनुसार, चोरों ने उनके घर से लगभग 40 हजार रुपए नकद की चोरी की है ।एक ही रात में दो घरों में हुई इस सेंधमारी से पुलिस की गश्ती व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने घटना के पीछे इलाके में बढ़ती नशेबाजी को मुख्य कारण बताया है। घटनास्थल के पास बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई सीरिंज और अन्य नशीले पदार्थों के अवशेष बिखरे मिले हैं। आरोप है कि खाली घरों को देखते ही यह इलाका नशेड़ियों का सुरक्षित अड्डा बन जाता है। लोगों ने मांग की है कि पुलिस नशेड़ियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाए।

छड़वा डैम पानी सप्लाई केंद्र का महापौर ने किया निरीक्षण, शुद्ध पेयजल को लेकर जताई चिंता

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

हजारीबाग। शहरवासियों को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर महापौर अरविन्द कुमार राणा गंभीर नजर आए। इसी कड़ी में उन्होंने मंगलवार को छड़वा डैम स्थित पानी सप्लाई केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान महापौर ने केंद्र की साफ-सफाई व्यवस्था, मशीनों की स्थिति तथा जल आपूर्ति प्रणाली का बारीकी से जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहरवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कर्मियों को नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करने और जल आपूर्ति प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पेयजल की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में गुणवत्ता और आपूर्ति दोनों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

महापौर अरविन्द कुमार राणा ने पानी सप्लाई केंद्र में लगे विभिन्न मशीनों और उपकरणों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान यह बात सामने आई कि कुछ महंगी मशीनों के रख-रखाव में लापरवाही बरती जा रही थी। जानकारी के अनुसार, पानी के रिसाव के कारण लाखों रुपये की लागत से स्थापित तीन मशीनों में पानी भर गया था, जिससे उनके खराब होने का खतरा उत्पन्न हो गया था।

हालांकि, स्थानीय कर्मियों की सूझबूझ और तत्परता के कारण समय रहते स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और मशीनों को सुरक्षित बचा लिया गया।

इस पर महापौर ने एक ओर जहां लापरवाही को लेकर प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी, वहीं दूसरी ओर त्वरित कार्रवाई कर मशीनों को बचाने वाले कर्मियों की सराहना भी की। उन्होंने कर्मियों की तत्परता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसी जिम्मेदारी और सजगता ही व्यवस्था को मजबूत बनाती है।

निरीक्षण के दौरान महापौर ने साफ-सफाई व्यवस्था को संतोषजनक बताया, लेकिन इसे और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि परिसर में नियमित सफाई हो, जलाशयों की समय-समय पर सफाई की जाए और किसी भी प्रकार की गंदगी या लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि साफ-सफाई का सीधा संबंध लोगों के स्वास्थ्य से है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।

महापौर अरविन्द कुमार राणा ने प्रबंधन को यह भी निर्देश दिया कि सभी मशीनों का समय-समय पर मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की तकनीकी खराबी उत्पन्न न हो और जल आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई गई तो संबंधित जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी।

कुल मिलाकर, महापौर के इस निरीक्षण से पानी सप्लाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। शहरवासी भी उम्मीद कर रहे हैं कि इस पहल के बाद उन्हें नियमित रूप से शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल होगा जब सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा : श्रवण कुमार

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह के अवसर पर जदयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मूल्यों को विशेष महत्व देकर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। बुधवार को अभिलेखागार भवन हॉल में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्रवण कुमार ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का जन्म एक साधारण और दलित परिवार में हुआ था। उनका बचपन कठिनाइयों और सामाजिक भेदभाव के बीच बीता, लेकिन इन परिस्थितियों ने उनके हौसले को और मजबूत किया। उन्होंने कहा कि डॉ. अंबेडकर ने शिक्षा की शक्ति को समझा और उसे समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनाया। उन्होंने भारत के लोगों के जीवन में शिक्षा के माध्यम से बदलाव लाने का कार्य किया और सभी को समान अवसर दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक योगदान दिया। श्रवण कुमार ने कहा कि छुआछूत और असमानता के खिलाफ संघर्ष कर दलितों को उनका अधिकार दिलाने में डॉ. अंबेडकर की भूमिका अतुलनीय रही। कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने बताया कि डॉ. अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें 'भारतीय संविधान का शिल्पकार' कहा जाता है। महिलाओं को हिन्दू कोड बिल के माध्यम से समान अधिकार दिलाने में भी उनका योगदान ऐतिहासिक रहा। श्रवण कुमार ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष, शिक्षा और आत्मविश्वास के बल पर किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। एक न्यायपूर्ण और समतामूलक भारत के निर्माण के लिए हमें उनके विचारों और संविधान की मूल भावना को अपने जीवन में अपनाना होगा।

विधान सभाध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार से मिले बिहार पिट्ठू संघ के अध्यक्ष

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार से आज उनके कार्यालय कक्ष में बिहार पिट्ठू संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, सचिव आशुतोष कुमार तिवारी एवं कोषाध्यक्ष रितेश सिंहल के नेतृत्व में सूरत (गुजरात) में आयोजित होने वाले तृतीय पिट्ठू जूनियर सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप-2026 में भाग लेने वाली बिहार पिट्ठू बालक एवं बालिका टीम के प्रतिभागियों ने मुलाकात की। अध्यक्ष ने आगामी 3 से 6 मई 2026 तक सूरत (गुजरात) में आयोजित होने वाले तृतीय पिट्ठू जूनियर-सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप-2026 प्रतियोगिता में क्रमशः अनुराग राणा एवं अपर्णा तन्नू कुजूर के नेतृत्व में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली बालक एवं बालिका टीम के प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बिहार पिट्ठू बालक एवं बालिका टीम के प्रतिभागियों के साथ ग्रुप फोटोग्राफी कर उनका मनोबल बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बिहार पिट्ठू के बालक एवं बालिका टीम नेशनल चैम्पियनशिप में उम्दा प्रदर्शन कर प्रदेश को गौरवान्वित करेगी। उन्होंने बिहार पिट्ठू संघ के पदाधिकारियों को इस परंपरागत खेल को और बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। मौके पर बिहार पिट्ठू संघ के अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, सचिव आशुतोष कुमार तिवारी एवं कोषाध्यक्ष रितेश सिंहल, लीगल सेल के संयोजक एवं पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सोनू कुमार सिंह, बिहार राज्य नागरिक परिषद् के सदस्य नीरज गौतम सहित सभा सचिवालय के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।

अब नहीं हो रहा छात्रों का पलायन, राज्य में मिल रही बेहतर शिक्षा : उपमुख्यमंत्री

नीतीश कुमार के कार्यों और नीतियों को आगे बढ़ाने का नये मुख्यमंत्री ने लिया है निर्णय

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राज्य से पढ़ाई खासकर तकनीकी विषयों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों का पलायन अब तकरीबन बंद हो गया है। इसकी मुख्य वजह यहीं छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है जिससे उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। राज्य में शीघ्र ही मंत्री परिषद का विस्तार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों और नीतियों को नये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उसपर कार्य भी शुरू हो गए है। ये बातें उप-मुख्यमंत्री सह विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कही। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कुल स्वीकृत पद 3406 है जिसके विरूद्ध कुल 1616 नियमित शिक्षक कार्यरत है तथा 906 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अलावा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल स्वीकृत पद 2480 है जिसके विरूद्ध कुल 1001 नियमित शिक्षक कार्यरत है तथा 273 पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जा चुकी है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में अनुदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 723 पदों एवं प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु कुल 1093 पदों का विज्ञापन, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के स्तर से प्रकाशित किया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेजों में सेटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। उन कॉलेजों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई गई है। इसका परिणाम है कि उसकी मांग बढ़ गई है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 14553 है। इसी प्रकार राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में कुल स्वीकृत सीटों की संख्या 17243 है। साथ ही कुल 10 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (एमटेक) विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 612 सीटों पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 से पठन-पाठन प्रारम्भ है। उद्योग के मांग के अनुरूप वर्तमान में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के चार वर्षीय पाठ्यक्रमों में कुल 33 विधाओं में पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है तथा राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों के तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों में कुल 26 विधाओं में पठन-पाठन का कार्य किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि सुशासन के कार्यक्रम (2020-25) के तहत सात निश्चय-2 के अन्तर्गत सभी राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान में उभरते हुए तकनीक में उच्चस्तरीय 'सेंटर ऑफ एक्सेलेंस' आईआईटी, पटना के सहयोग से संचालित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बी.डी. कॉलेज पटना में द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न

जब शब्द तकनीकी तो विचार वैश्विक : प्रो. रत्ना अमृत

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बी.डी. कॉलेज, पटना और वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 : सामाजिक विज्ञान शिक्षण में तकनीकी शब्दावली का प्रयोग' विषय पर द्वि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफल आयोजन किया गया। प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत के नेतृत्व में आयोजित इस संगोष्ठी ने शिक्षा, संस्कृति और तकनीकी शब्दावली के समन्वय को नई दिशा प्रदान की। उद्घाटन दिवस 28 अप्रैल को पूर्व कुलपति प्रो. रास बिहारी प्रसाद सिंह ने बीज वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए मातृभाषा, संस्कृति और बहुविषयक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं और ज्ञान परंपरा को केंद्र में रखना आवश्यक है। प्रो. एस.पी. सिंह ने हिंदीभाषी विद्यार्थियों की सफलता में तकनीकी शब्दावली की भूमिका को रेखांकित किया जबकि प्रो. अनवारुल हक अंसारी ने आयोग के प्रयासों को कानूनी मान्यता देने तथा संस्थागत वेबसाइटों पर आयोग के लिंक प्रदर्शित करने की आवश्यकता बताई। प्रथम दिन के तकनीकी सत्रों में शिक्षा और सामाजिक विज्ञान में मानकीकृत शब्दावली के महत्व पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रो. नागेंद्र प्रसाद वर्मा और प्रो. राजीव रंजन ने शिक्षा में सटीकता, वैज्ञानिकता और सामाजिक विज्ञान की टर्मिनोलॉजी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। डॉ. भुवन कुमार झा और डॉ. अविनाश कुमार झा ने समाज विज्ञान की तकनीकी शब्दावली के व्यावहारिक उपयोग पर अपने विचार रखे। संगोष्ठी प्रभारी अधिकारी दीपक कुमार ने आयोग की स्थापना, 'शब्द सिंधु' पोर्टल तथा 22 भाषाओं में उपलब्ध मानकीकृत शब्दावली की उपयोगिता पर विस्तार से जानकारी दी। 29 अप्रैल को दूसरे दिन प्राचार्या प्रो. रत्ना अमृत ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चार प्रमुख स्तंभ–बहुविषयकता, अनुभवनात्मक शिक्षण, मातृभाषा का उपयोग और 21वीं सदी के कौशल–तकनीकी शब्दावली से गहराई से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि 'रिमोट सेंसिंग', 'जीआईएस', 'जीडीपी', 'क्वालिटेटिव रिसर्च', 'सैंपल सर्वे' जैसे शब्दों को मूल रूप में अपनाना चाहिए जबकि 'हिस्टोरियोग्राफी', 'प्राइमरी सोर्स' और 'न्यूमिस्मेटिक' जैसे शब्दों को स्थानीय उदाहरणों के साथ समझाना अधिक प्रभावी होगा।

सचिव जय सिंह ने संभाला राजस्व विभाग का प्रभार, जनहित पहली प्राथमिकता

विभाग की कार्य प्रणाली को जन हितैषी बनाना पहली प्राथमिकता

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव के तहत सचिव जय सिंह ने औपचारिक रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की और स्पष्ट संकेत दिया कि विभाग की कार्य प्रणाली को जन हितैषी बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। सचिव जय सिंह ने कहा कि आम जनता से जुड़े इस विभाग की जिम्मेदारी बेहद संवेदनशील है, इसलिए कार्यों में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा राजस्व संबंधी सेवाओं को अधिक सरल और सुगम बनाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से कार्यों को तेज और प्रभावी बनाया जाएगा, ताकि आम लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। भूमि से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं को और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिव श्री सिंह के साथ विभाग की वर्तमान स्थिति और चल रही योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।

तीन नए पथों का होगा निर्माण, सोनपुर, बक्सर, गयाजी में सुगम होगा यातायात

कैबिनेट की बैठक में लिया गया अहम निर्णय, 63 एजेंडों पर लगी मुहर

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। राजधानी पटना के आसपास के तीन प्रमुख शहरों में सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल करने और इसकी कनेक्टिविटी पटना समेत अन्य शहरों से बेहतर करने के लिए तीन प्रमुख सड़क सर्किट का निर्माण होगा। इन सड़कों का निर्माण गंगा नदी के पास कराया जाएगा। इन तीनों सड़कों का निर्माण पीपीपी डीबीएफओटी टॉल मोड पर कराया जाएगा। यानी इसका निर्माण चयनित निजी कंपनी करेगी। इसमें राज्य सरकार सिर्फ जमीन समेत अन्य जरूरी संसाधन मुहैया कराएगी। निजी कंपनी इस सड़क से निर्धारित टॉल वसूलकर अपना मुनाफा वसूलेगी। इस महत्वपूर्ण एजेंडा पर कैबिनेट की बैठक में समहति बनी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 63 एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तृत जानकारी सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने दी। उनके साथ संबंधित विभागों के सचिवों ने भी अपने-अपने विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण एजेंडों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि सारण जिला के अंतर्गत दरिहारा (कोन्हुआ) से गोपालगंज में डुमरिया घाट के बीच 4 लेन ग्रीनफिल्ड सड़क को मंजूरी दी गई है। इसकी लंबाई 73.51 किमी है। इनका क्रियान्वयन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से कराया जाएगा। यह नई सड़क सोनपुर स्थित प्रसिद्ध हरिहरनाथ मंदिर के साथ बन रहे हरिहरनाथ कॉरिडोर और प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को भी जोड़ेगी। इसका नाम नारायणी पथ होगा।

सचिव ने कहा कि बक्सर से आरा-मनेर होते हुए कोईलवर तक गंगा किनारे एक नई सड़क बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 90 किमी होगी। इसका नाम विश्वामित्र गंगा पथ रखा गया है। इसे पटना स्थित जेपी गंगा पथ से जोड़ा जाएगा। इसके तैयार होने से पटना से बक्सर और आगे तक जाने में लोगों को काफी सुविधा होगी। इसके अलावा गयाजी में कोठवारा बाजार से इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के बीच गम्हरिया सामुदायिक भवन के पास फल्गु नदी पर दो लेन का आरसीसी पुल सह पहुंच पथ का निर्माण कराया जाएगा। इसके निर्माण पर 113 करोड़ 84 लाख रुपये का अनुमान है। इसका नाम गयाजी अंबिका पथ रखा गया है। इस पथ की संपर्कता डोभी-चतरा एनएच-99 से भी होगी।

एनपीसीआई महत्वपूर्ण सुझावों के साथ नागरिकों को कर रहा सशक्त

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। डिजिटल भुगतान ने भारत भर में लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए रोजमर्रा के लेनदेन को तेज, आसान और अधिक सुलभ बना दिया है। जैसे-जैसे यह सुविधा बढ़ रही है, उपयोगकर्ताओं के लिए जागरूक और सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित भुगतान के तरीके अपनाना आसान है और यह सुरक्षित डिजिटल अनुभव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनपीसीआई नागरिकों को सुरक्षित डिजिटल भुगतान के लिए 5 महत्वपूर्ण सुझावों के साथ सशक्त बनाता है जिनमें भुगतान करने से पहले हमेशा जांच करें, केवल विश्वसनीय भुगतान ऐप्स और वेबसाइटों का ही उपयोग करें, अपना पिन या ओटीपी किसी के साथ साझा न करें। जागरूकता और जिम्मेदार उपयोग के साथ, डिजिटल भुगतान रोजमर्रा की जिंदगी का एक भरोसेमंद और सशक्त हिस्सा बने रह सकते हैं। किसी भी संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करके या दूरसंचार विभाग के वेबसाइट के माध्यम से करें। संदेशों को सुरक्षित रखें, स्क्रीनशॉट लें और सभी बातचीत का रिकॉर्ड रखें। यह जानकारी आवश्यकता पड़ने पर रिपोर्ट दर्ज कराने में अधिकारियों की मदद कर सकती है।

शिक्षा और कौशल विकास की वास्तविकता डिग्री नहीं, दक्षता चाहिए : डॉ. आनंद रंजन झा

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं, बल्कि अधूरी शिक्षा है। ऐसी शिक्षा, जो डिग्री तो देती है, लेकिन जीवन जीने और रोजगार पाने की क्षमता नहीं देती। मैं वर्षों से शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। हजारों छात्रों से प्रत्यक्ष संवाद और प्रशिक्षण के अनुभव ने मुझे यह समझा दिया है कि हमारे युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है–कमी है तो केवल सही दिशा और व्यवहारिक कौशल की। डिग्री की दौड़ ने दिशा भटका दी है। आज का युवा डिग्री के पीछे भाग रहा है क्योंकि समाज ने उसे यही सिखाया है, लेकिन जब वही युवा नौकरी के लिए जाता है तो उससे पूछा जाता है–'आप क्या कर सकते हैं?' यहीं से उसकी वास्तविक परीक्षा शुरू होती है और दुर्भाग्य से, अधिकतर युवा इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें 'क्या पढ़ा है' सिखाया गया, 'क्या कर सकते हैं' नहीं। मैंने जमीनी सच्चाई देखी है-मेरे पास ऐसे अनगिनत छात्र आते हैं, जिन्होंने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की होती है, लेकिन जब उन्हें एक साधारण कंप्यूटर टास्क या प्रभावी संवाद करने के लिए कहा जाता है तो वे असहज हो जाते हैं। यह उनकी गलती नहीं है–यह हमारी व्यवस्था की कमी है। नीतियों की सफलता, क्रियान्वयन पर निर्भर है। सरकार की मंशा पर सवाल उठाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सच्चाई को अनदेखा करना भी उचित नहीं है। कौशल विकास के लिए योजनाएं बनती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब तक उनका सही और पारदर्शी क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक परिणाम अधूरे ही रहेंगे। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि कई बार प्रशिक्षण केंद्रों को समय पर संसाधन, स्पष्ट दिशा-निर्देश और प्रशासनिक सहयोग नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना एक चुनौती बन जाता है। कौशल ही आत्मनिर्भरता का वास्तविक आधार है। मेरे लिए कौशल विकास केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग है जब एक युवा किसी कौशल में दक्ष होता है तो वह अवसर खोजता नहीं–अवसर पैदा करता है। डिजिटल शिक्षा, तकनीकी दक्षता, संचार कौशल और उद्यमिता–ये आज के युग की अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। जो युवा इनसे जुड़ता है, वही आगे बढ़ता है। गांव बदलेगा, तभी देश बदलेगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत का भविष्य गांवों में तय होगा। ग्रामीण युवाओं में अद्भुत क्षमता है, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पाता। यदि कौशल विकास की रोशनी ईमानदारी से गांव-गांव तक पहुंचाई जाए, तो यह देश एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैंने स्वयं देखा है कि एक साधारण ग्रामीण छात्र जब डिजिटल रूप से सक्षम होता है तो उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब केवल बात नहीं, बदलाव चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम शिक्षा को केवल प्रमाणपत्र तक सीमित न रखें। हमें इसे जीवन, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। मैं सभी नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और संस्थानों से यह आग्रह करता हूं कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाएं। गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही–इन्हीं के आधार पर हम एक सशक्त भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अंत में मेरी एक स्पष्ट बात यदि हम अपने युवाओं को सही कौशल नहीं दे पाए तो डिग्रियों का यह ढेर किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन यदि हमने उन्हें दक्ष बना दिया तो वही युवा इस देश की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे।

पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा सुनीता सिंह के नेतृत्व में नए नामांकित बच्चों के बीच उपहार भेंट

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

हाजीपुर। पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, हाजीपुर की अध्यक्षा सुनीता सिंह के नेतृत्व में लिटिल ऐंजल्स किंडरगार्टन एंड प्ले स्कूल, कोनहाराघाट रेलवे कॉलोनी, हाजीपुर में नए बच्चों के नामांकन के उपलक्ष्य में सभी नए बच्चों को उपहारस्वरूप स्कूल बैग तथा कलर आर्ट किट प्रदान किया गया। इस अवसर पर संगठन की सचिव मनीषा सिन्हा, कोषाध्यक्ष पूनम श्रीवास्तव, स्कूल इंचार्ज प्रीति झा एवं नेहा सिंह उपस्थित थीं। इनके द्वारा विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को प्रारंभिक शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया जिसके फलस्वरूप वो अपने भविष्य को संवार सके। ज्ञात हो कि पूर्व मध्य रेल महिला कल्याण संगठन, हाजीपुर द्वारा संचालित लिटिल ऐंजल्स किंडरगार्टन एंड प्ले स्कूल, रेलवे कॉलोनी तथा उसके आस-पास रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए काफी लोकप्रिय हो रहा है।

नक्सलवाद से मुक्त हुआ बिहार, चार जिलों में सतर्क निगरानी जारी

एसटीएफ नक्सलियों के सफाए के साथ कुख्यात अपराधियों के खिलाफ भी कर रही कार्रवाई

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार अब नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो गया है। पिछले वर्ष से अब तक किसी तरह की कोई नक्सली वारदात प्रदेश में नहीं हुई है। फिर भी चार जिलों जमुई, लखीसराय, गया और औरंगाबाद में फिलहाल खासतौर से सतर्कता बरतते हुए चौकसी रखी जा रही है। इन 4 जिलों को एलएंडटी (लीड एंड थ्रस्ट) जिले के तौर पर चिन्हित करके रखा गया है। ताकि इन जिलों में फिर से नक्सली सक्रिय नहीं हो सके। एक समय ये चार जिले नक्सलियों के विशेष रूप से गढ़ माने जाते थे। पुलिस मुख्यालय में मंगलवार (28 अप्रैल) को हुई एक प्रेस वार्ता के दौरान यह जानकारी एसटीएफ के डीआईजी संजय कुमार ने साझा की थी। डीआईजी ने बताया कि जमुई और लखीसराय समेत अन्य संवेदनशील माने जाने वाले जिलों में भी पिछले वर्ष जुलाई से अब तक किसी तरह की कोई छोटी या बड़ी नक्सली वारदात नहीं हुई है। इस वर्ष जनवरी-फरवरी में तीन लाख रुपये का इनामी और 2 लाख रुपये के इनामी नक्सली के आत्मसर्पण करने के बाद बिहार के सभी संवेदनशील जिलों से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। इस वर्ष जनवरी से 22 अप्रैल तक 18 मुख्य नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें इनामी नक्सली भी शामिल हैं। नक्सलियों के सफाए में केंद्रीय पुलिस फोर्स के साथ ही एसटीएफ की भूमिका बेहद उल्लेखनीय है। जिन चार जिलों में चौकसी बरती जा रही है, उनमें एसटीएफ के स्तर से निरंतर चौकसी बरती जा रही है। सभी जंगली या नक्सलियों की मांद समझे जाने वाले इलाकों में भी निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने वाले 11 नक्सलियों के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया गया है।

चार महीने में गिरफ्तार किए गए 720 अपराधी

एसटीएफ के स्तर से नक्सलियों के साथ अपराधियों खासकर कुख्यात अपराधियों के खिलाफ भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस वर्ष जनवरी से 22 अप्रैल तक 720 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 35 इनामी अपराधी शामिल हैं। इसमें 17 अपराधियों को दूसरे राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 15 आधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। 2 एके-47, 1 एके 56, इनसास-2, ग्लाक पिस्टल-1, 5 सेमी-ऑटोमैटिक पिस्टल समेत अन्य हथियार शामिल हैं। इसके अलावा 178 देसी हथियार शामिल हैं।

सतर्कता टीम ने की भ्रष्टाचार में लिप्त टीटीई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

हाजीपुर। प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्यवाई करते हुए पूर्व मध्य रेल की सतर्कता टीम ने गाड़ी संख्या 18183 टाटा-बक्सर एक्सप्रेस की सघन जांच की एवं एसी कोच में कार्यरत टीटीई/आसनसोल के प्राईवेट एवं सरकारी धन की जांच की गई। उनके पास निजी धन में रुपए 4,300 की अधिकता पाई गई जिसे नियमानुसार रेलवे खाते में जमा किया गया। भ्रष्टाचार में लिप्त उक्त टीटीई के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस प्रकार की कार्रवाई रेलवे प्रशासन द्वारा पारदर्शिता एवं जबावदेही सुनश्चित करने के उद्देश्य से निरंतर की जा रही है।

अब पटना जू से हटेगा 'संजय गांधी' का नाम

बिहार कैबिनेट ने लिया फैसला

नवबिहार टाइम्स ब्यूरो

पटना। बिहार कैबिनेट ने एक अहम फैसला लेते हुए पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब इस उद्यान को 'पटना जू (पटना प्राणी उद्यान)' के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही उद्यान के संचालन के लिए गठित 'संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी' का नाम भी बदलकर 'पटना जू प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी' कर दिया गया है।

कैबिनेट के इस निर्णय के बाद राजधानी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल इस उद्यान की पहचान नए नाम के साथ स्थापित की जाएगी। संजय गांधी जैविक उद्यान लंबे समय से बिहार के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रहा है और यहां हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आते हैं। नए नाम के साथ इसके प्रबंधन और विकास कार्यों को भी नई दिशा देने की तैयारी है। फिलहाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभागों को नए नाम को लागू करने, आधिकारिक दस्तावेजों में संशोधन करने और संकेत पट्टों सहित अन्य व्यवस्थाओं को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

संपादकीय

महाशक्ति की सुरक्षा में सेंध

अमेरिका जैसे देश में राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा का घेरा दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन यहां भी अगर सुरक्षा में चूक हो जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित रात्रिभोज में गोलीबारी की घटना ने दुनिया भर में सबके कान खड़े कर दिए हैं। यह वारदात ऐसे मौके पर हुई, जब यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी एवं प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि बाद में सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल है कि विश्व की महाशक्ति होने का दंभ भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपने ही देश के भीतर इस तरह की चूक कैसे हो सकती है?कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर आयोजन स्थल में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गया! गोलीबारी की वजह से पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई और ट्रंप को उनकी पत्नी के साथ तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह घटना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी सबक है, जो मानते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा अभेद्य है।प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन यहां राष्ट्रपति की मौजूदगी से मामले की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी दो बार हमले हो चुके हैं, हालांकि यह बात अलग है कि उस दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। मार्च 2016 में लास वेगास में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी।हिरासत में पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद जुलाई 2024 में चुनावी रैली में ट्रंप पर उस समय खतरनाक हमला हुआ था, जब वह मंच से भाषण दे रहे थे। मगर गनीमत रही कि हमलावर की ओर से चलाई गई गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। यह बात समझ में आती है कि इन दो घटनाओं के दौरान ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रपति होते हुए अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती है, तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है।इस घटना की शुरुआती जांच में एक बात यह भी निकलकर सामने आई है कि हमलावर सोशल मीडिया पर ट्रंप विरोधी टिप्पणियां करता रहा है और वह उस होटल में कुछ दिन पहले ठहरा था, जहां यह समारोह आयोजित किया गया था। यानी उसने आयोजन स्थल को पहले ही अच्छी तरह जांच परख लिया था और उसके बाद सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम में घुसने की साजिश रची। यही नहीं खबरों के मुताबिक, हमलावर के परिवार ने उसकी मंशा को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहले सतर्क भी किया था, लेकिन स्पष्ट है कि इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया।इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर यह कार्यक्रम व्हाइट हाउस में निर्माणाधीन सैन्य रूप से अत्यंत गोपनीय 'बालरूम' में हुआ होता, तो इस तरह की वारदात नहीं होती। अदालत ने इस निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है। मगर सवाल सिर्फ किसी एक सुरक्षित स्थान का नहीं है।

उत्तर प्रदेश का एक पुराना घाव है पश्चिम और पूर्व के बीच की खाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा जैसे शहरों से परिभाषित होता है, में उद्योग हैं, बाज़ार हैं, रोजगार है, और एक खास किस्म की आधुनिकता भी है। लेकिन, जैसे-जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, बलियाज्एक अलग उत्तर प्रदेश मिलता है। वहां खेत हैं, मंदिर हैं, नदियां हैं, और असीम मानवीय संभावनाएं भी हैं, लेकिन उन संभावनाओं में अवसरों का घोर अभाव दिखता था। गंगा एक्सप्रेसवे इस विभाजन को पाटने की सबसे बड़ी भौतिक कोशिश है।

गंगा एक्सप्रेसवे- आर्थिक पुनर्जागरण की जीवंत रेखा

(संजय सिन्हा)

किसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि वह मेहनत नहीं करता, बल्कि यह है कि उसकी मेहनत का सही मूल्य उसे नहीं मिलता। फसल खेत में पकती है, लेकिन मंडी तक पहुंचते-पहुंचते उसकी ताजगी और उसकी कीमत दोनों गिर जाती हैं।गंगा की धारा जब किसी पत्थर से टकराती है, तो वह उसे काटती नहीं, बल्कि उसे घिसते-घिसते अपने रास्ते की शक्ल में ढाल लेती है। उत्तर प्रदेश की नियति भी कुछ ऐसी ही रही है । इस भूमि ने सभ्यताएं जन्मी हैं, क्रांतियां बोई हैं, फिर भी एक दशक पहले तक एक विडंबना इसके माथे पर चिपकी रही कि यह राज्य, जो देश की आबादी का छठा हिस्सा समेटे है, विकास की दौड़ में अक्सर पिछली पंक्ति में ही खड़ा दिखाई पड़ा। इतिहास की यह विरोधाभासी विरासत अब एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़ी है और उस दहलीज का नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, जो यूपी सरकार के संकल्प के एक बड़े प्रतिमान के रूप में अब साकार रूप में है।

594 किलोमीटर.मेरठ से प्रयागराज यह केवल एक सड़क की लंबाई नहीं है, बल्कि उस सोच की लंबाई है, जो मानती है कि किसी राज्य को बदलने के लिए पहले उसकी नसों में नई रक्त-संचार व्यवस्था बनानी पड़ती है। जब कोई जमीन पर इतनी बड़ी रेखा खींची जाती है, तो वह केवल भूगोल नहीं बदलती, वह उस भूगोल में जीने वाले लोगों की संभावनाओं का नक्शा बदल देती है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा ही एक परिवर्तनकारी हस्तक्षेप है, जिसे समझने के लिए केवल इंजीनियरिंग की नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और दूरदर्शिता की भाषा जाननी होगी।

उत्तर प्रदेश का एक पुराना घाव है पश्चिम और पूर्व के बीच की खाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, आगरा जैसे शहरों से परिभाषित होता है, में उद्योग हैं, बाज़ार हैं, रोजगार है, और एक खास किस्म की आधुनिकता भी है। लेकिन, जैसे-जैसे आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं प्रयागराज, वाराणसी, आजमगढ़, बलियाज्एक अलग उत्तर प्रदेश मिलता है। वहां खेत हैं, मंदिर हैं, नदियां हैं, और असीम मानवीय संभावनाएं भी हैं, लेकिन उन संभावनाओं में अवसरों का घोर अभाव दिखता था। गंगा एक्सप्रेसवे इस विभाजन को पाटने की सबसे बड़ी भौतिक कोशिश है।

जब मेरठ और प्रयागराज एक तेज, सुगम, भरोसेमंद सड़क से जुड़ जाते हैं, तो वास्तव में यह दो शहरों का नहीं, दो आर्थिक ध्रुवों का मिलन होता है। पूर्वांचल की श्रम शक्ति और कृषि उत्पाद पश्चिम के बाजारों तक पहुंचने लगते हैं। पश्चिम की पूंजी और उद्यमशीलता पूर्व की सस्ती जमीन और उपलब्ध श्रम को देखकर खिंचती है। यह वह आर्थिक गुरुत्वाकर्षण है जो तब उत्पन्न होता है जब दूरी सिकुड़ती है, न केवल किलोमीटर में, बल्कि समय और लागत में भी।

लॉजिस्टिक्स की दुनिया में एक पुराना सच है, माल की ढुलाई की लागत जहां कम होती है, वहां उद्योग खिंचे चले आते हैं। भारत में लॉजिस्टिक्स लागत विकसित देशों की तुलना में लगभग दोगुनी है। यह अतिरिक्त लागत उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर करती है, उत्पादों को महंगा बनाती है और निर्यात को बाधित करती है। जब गंगा एक्सप्रेसवे जैसे हाई-स्पीड कॉरिडोर बनते हैं, तो यह समीकरण बदलता है। माल तेज़ पहुंचता है, भंडारण की जरूरत घटती है, ट्रांसपोर्ट

का समय कम होता है और पूरी सप्लाई चेन अधिक विश्वसनीय बन जाती है।

उत्तर प्रदेश को एक नई 'ग्रोथ स्पाइन' मिल सकती है

गंगा एक्सप्रेसवे से होकर गुजरने वाला एक ट्रक केवल माल नहीं ढोएगा, वह उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को एक पायदान ऊपर ले जाएगा। लेकिन, असली रूपांतरण तब होगा जब एक्सप्रेसवे के किनारे एक औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र उगेगा। सरकार की योजना औद्योगिक नोड्स, वेयरहाउसिंग हब और एमएसएमई क्लस्टर विकसित करने की है। यह योजना अगर सही नीयत और सही क्रियान्वयन के साथ जमीन पर उतरी, तो उत्तर प्रदेश को एक नई 'ग्रोथ स्पाइन' मिल सकती है। वह रीढ़, जिसके सहारे एक पूरा आर्थिक शरीर खड़ा होता है। टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए / विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हरदोई, शाहजहांपुर, बदाये, संभल रायबरेली, उन्नाव, ये वे शहर हैं जो अब तक विकास की मुख्यधारा से किनारे पड़े थे। एक्सप्रेसवे की पहुंच उन्हें एक बड़े आर्थिक नेटवर्क से जोड़ेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे खेत से बाजार की यात्रा को तेज करेगा

किसानों की बात किए बिना यह विश्लेषण अधूरा है। किसान की सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं है कि वह मेहनत नहीं करता, बल्कि यह है कि उसकी मेहनत का सही मूल्य उसे नहीं मिलता। फसल खेत में पकती है, लेकिन मंडी तक पहुंचते-पहुंचते उसकी ताजगी और उसकी कीमत दोनों गिर जाती हैं। कोल्ड चेन की कमी, खराब सड़कें और बाजार तक पहुंच की धीमी रफ्तार, ये तीन चीजें मिलकर किसान की उपज का एक बड़ा हिस्सा बर्बाद कर देती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे खेत से बाजार की यात्रा को तेज करेगा। यदि इसके साथ-साथ एक्सप्रेसवे के किनारे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और एग्री-लॉजिस्टिक्स हब विकसित हों, तो किसान की तकदीर बदलने में देर नहीं लगेगी। यह विकास का वह बिंदु है जहां बुनियादी ढांचा सीधे मानवीय जीवन की गुणवत्ता से जुड़ता है।

एक्सप्रेसवे का एक और आयाम है जिसे अक्सर सार्वजनिक विमर्श में नजरअंदाज किया जाता है – रियल एस्टेट का रूपांतरण। जब भी किसी इलाके में हाई-स्पीड कनेक्टिविटी आती है, जमीन की कीमतें बदलती हैं। नए आवासीय क्षेत्र उभरते हैं, लोग शहर के महंगे इलाकों को छोड़कर एक्सप्रेसवे के किनारे बसने लगते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया में जमीन की सट्टेबाजी और असमान लाभ वितरण के खतरे भी हैं, जिनसे बचने के लिए सरकार को सक्रिय नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा। रणनीतिक दृष्टि से भी यह एक्सप्रेसवे महत्वपूर्ण है। इसकी संरचना ऐसी बनाई गई है कि आपात स्थिति में इसे वायुसेना की एयरस्ट्रिप के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह विशेषता इसे केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिसंपत्ति भी बनाती है।

गंगा एक्सप्रेसवे इस नई छवि का सबसे दृश्यमान प्रतीक

निवेशकों का मनोविज्ञान भी इस संदर्भ में विचारणीय है। जब कोई राज्य इस पैमाने की परियोजना को समय पर, पारदर्शिता के साथ और कार्यकुशलता के साथ पूरा करता है, तो वह केवल एक सड़क नहीं बनाता, वह एक संदेश देता है कि यह राज्य अब गंभीर है। यहां शासन काम कर रहा है। यहां आपकी पूंजी सुरक्षित है और आपकी परियोजनाएं अटकेंगी नहीं। यह अमूर्त भरोसा बहुत ठोस परिणाम देता है। उत्तर प्रदेश, जो कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, अब खुद को एक आधुनिक, निवेश-अनुकूल और महत्वाकांक्षी राज्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे इस नई छवि का सबसे दृश्यमान प्रतीक है।

लेकिन यहां एक चेतावनी भी जरूरी है। बुनियादी ढांचा अपने आप में परिवर्तन नहीं लाता, वह केवल परिवर्तन की शर्तें बनाता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां शानदार सड़कें बनीं, पुल उठे, बंदरगाह बने लेकिन उनके आस-पास का जीवन नहीं बदला, क्योंकि नीतिगत वातावरण उनके साथ नहीं बदला।

परिवर्तन तब होगा जब सड़क के साथ-साथ शासन के संकल्प धरातल पर दिखाई देंगे।। जब किसान को उचित मुआवजा मिलेगा, युवा को कौशल प्रशिक्षण मिलेगा, उद्यमी को त्वरित अनुमति मिलेगी और पर्यावरण का ध्यान रखा जाएगा। इन चुनौतियों के बावजूद, यह स्वीकार करना होगा कि गंगा एक्सप्रेसवे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस सोच की अभिव्यक्ति है जो मानते हैं कि उत्तर प्रदेश अब केवल 'सबसे बड़े राज्य' के अभिमान से नहीं, बल्कि 'सबसे तेज विकसित होते राज्य' की वास्तविकता से पहचाना जाएगा।

जब कोई सड़क बनती है, तो उस पर भविष्य की पदचापें भी अंकित होने लगती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर जो पहला ट्रक दौड़ेगा, जो पहली बस मेरठ से प्रयागराज जाएगी, जो पहला किसान अपनी सब्जी लेकर इस सड़क से गुजरेगा, वे सब इस परिवर्तन के पहले साक्षी होंगे। उनके लिए यह सड़क केवल सड़क नहीं होगी। यह एक वादे का पूरा होना होगा, उस वादे का, जो इस योगी सरकार से इस राज्य के करोड़ों लोगों ने मांगा था। (प्रो. संजय सिन्हा पलवल स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के स्किल फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च के डीन हैं। इस लेख में लेखक के निजी विचार हैं। जनसत्ता का इनसे सहमत होना जरूरी नहीं है।)

नोएडा की हड़ताल- आर्थिक विषमता के बढ़ते संकट और मजदूरों की गहराती बेचैनी का संकेत

(पीएस वोहरा)

एक कमरे के मकान में रहने वाले मजदूरों का मासिक किराया तीन से चार हजार रुपया होता है, जो उनके वेतन का करीब 40 फीसद होता है। बाकी बचा हुआ हिस्सा खाने-पीने के राशन, बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाए और अगर बुजुर्ग माता-पिता आश्रित हों या छोटे भाई-बहन भी, तो उनका गुजर-बसर कैसे होगा?

हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक प्रमुख हिस्से उत्तर प्रदेश के नोएडा में मजदूरों की हड़ताल चर्चा में रही और इसका मुख्य कारण उनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की मांग थी। कुछ दिनों तक चली ये हड़ताल आखिर में हिंसक हो गई और इसके चलते गरीब मजदूरों के पक्ष में समाज का संवेदनात्मक रुख मुड़कर 'निंदनीय' हो गया। यह सही है या गलत, इसका विश्लेषण व्यक्ति को खुद ही करना होगा, पर अब यह समझना आवश्यक है कि आज भारतीय समाज क्या उस मोड़ पर आकर नहीं खड़ा हो गया है, जहां आर्थिक विषमता एक बहुत बड़ा संकट बन चुकी है?

वास्तव में भारत एक गरीब मुल्क है, चाहे वह चार ट्रिलियन की बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया हो और इन दिनों डालर के सामने रुपए की गिरावट के चलते छठे स्थान पर आ गया हो। क्या इस तरक्की के साथ भारत के गरीब व्यक्ति का, उसके आर्थिक जीवन स्तर का, जो दशकों से संघर्षों से भरा हुआ है, कोई तालमेल दिखता है? यह बेवजह नहीं है कि एक लंबे अरसे से मजदूरों के मन में अपनी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने और एक सम्मानजनक जीवन जीने की प्रबल इच्छा उनकी मांग बन गई और वे सड़कों पर हड़ताल करने के लिए उतर गए। मजदूरों की मुख्य मांगों में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी, समय पर वेतन, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा, साप्ताहिक अवकाश, महिला श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार, आठ घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुना ओवरटाइम वेतन और वक्त पर वार्षिक बोनस शामिल था। इन मांगों का अपना औचित्य है, लेकिन सच्चाई का एक पक्ष यह भी है कि मजदूर हड़ताल करने के लिए इसीलिए उतारू हुए कि वे बढ़ती आर्थिक असमानता, जिसके अंतर्गत कंपनियों के मुनाफों में वृद्धि और मालिकों की अमीरी के लगातार बढ़ते स्तर को भी देख रहे थे। इन सबके बीच एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मजदूर भी अपने वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। यह छिपा नहीं है कि एक मजदूर का औसत वेतन दस से बारह हजार है, जिसमें कई बार उसे तकरीबन बारह घंटे श्रम करना पड़ता है। वहीं महंगाई पर नियंत्रण सरकार का नहीं है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गैस सिलेंडर के बढ़ते मूल्य हैं, जो अब मजदूरों की पहुंच से बाहर जा रहा है। एक कमरे के मकान में रहने वाले मजदूरों का मासिक किराया तीन से चार हजार रुपया होता है, जो उनके वेतन का करीब 40 फीसद होता है। बाकी बचा हुआ हिस्सा खाने-पीने के राशन, बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो जाए और अगर बुजुर्ग माता-पिता आश्रित हों या छोटे भाई-बहन भी, तो उनका गुजर-बसर कैसे होगा? स्थिति और भी गंभीर है कि जब भी मजदूर अपने हक की मांग करता है, तो उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। कई रपटों के आंकड़े ये भी सामने आए कि आंदोलन के बाद कई कर्मचारियों को काम मिलना बंद हो गया।

सरकारी संस्थान, सेंटर फार मानिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीआइएमई) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले छह वर्षों में मजदूरों को उत्पादन (विक्रय और भंडार में बदलाव) का 5.16 फीसद का हिस्सा घटकर अब 4.97 फीसद रह गया है। वर्ष 1991 में यह हिस्सा सात फीसद से अधिक हुआ करता था। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अंतर्गत यह भी बताया गया कि पिछले पंद्रह वर्षों में कंपनियों का कर चुकाने के बाद का लाभ 149 फीसद बढ़ा है, जबकि कर्मचारियों का वेतन मात्र 52 फीसद।

भारत के कई बड़े शहरों में कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी को अब ठेकेदारों के माध्यम से ही रखा जाता है। वर्ष 2000 तक ऐसे कर्मचारियों की तादाद 16 फीसद हुआ करती थी, जो अब 42 फीसद हो गई है। और इन सबकी वजह से कर्मचारी फैक्टरी के मालिकों से प्रत्यक्ष बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनके बीच कोई अनुबंध नहीं होता है और ठेकेदार कभी भी कर्मचारी का साथ नहीं देता। एक रपट में ये तथ्य दर्ज हैं कि निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत उम्र बढ़ने पर वेतन कम होने लगता है। 15 से 25 वर्ष तक की आयु के बीच निर्माण क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में मजदूरों का वेतन अधिक है, पर 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु के बीच में अन्य क्षेत्रों की तुलना निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मजदूरों के वेतन में 15 फीसद से लेकर 25 फीसद तक कमी देखी जाती है। अब इस पक्ष पर यह क्यों नहीं समझा जा रहा कि व्यक्ति पर इस आयु के दौरान पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है, तो वह निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत कम वेतन पर अपनी जिम्मेदारियां कैसे उठा पाएगा!

एक राष्ट्र एक चुनाव' से बदलेगी सत्ता की तस्वीर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश की किसी भी अन्य पार्टी से अलग है- चाहे वह अतीत की हो या वर्तमान की। इसका लक्ष्य केवल जितनी बार संभव हो उतनी बार चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना और हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना है। इस मायने में भाजपा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के समान है। सीपीसी ने जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भीषण युद्ध और वर्ष 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद 1949 में कुओमिंतांग (केएमटी) के खिलाफ गृहयुद्ध के माध्यम से सत्ता हासिल की। सीपीसी तब से सत्ता में बनी हुई है।

2029 से पहले भारत के सामने निर्णायक मोड़

(पी. चिदंबरम)

भाजपा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने में सफल हो जाती, तो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की आड़ में यह विधेयक परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के मनमाने ढंग से सीमांकन को अंजाम दे देता। नए कानून और उनका क्रियान्वयन दक्षिणी राज्यों को देश के शासन में अप्रासंगिक बना देता।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश की किसी भी अन्य पार्टी से अलग है- चाहे वह अतीत की हो या वर्तमान की। इसका लक्ष्य केवल जितनी बार संभव हो उतनी बार चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि चुनाव जीतना और हमेशा के लिए सत्ता में बने रहना है। इस मायने में भाजपा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के समान है। सीपीसी ने जापानी आक्रमणकारियों के खिलाफ एक भीषण युद्ध और वर्ष 1945 में जापान के आत्मसमर्पण के बाद 1949 में कुओमिंतांग (केएमटी) के खिलाफ गृहयुद्ध के माध्यम से सत्ता हासिल की। सीपीसी तब से सत्ता में बनी हुई है।

माओत्से तुंग ने वर्ष 1949 में चीन में एकदलीय शासन की घोषणा की, जबकि भारत ने वर्ष 1947 में ब्रिटेन से आजादी हासिल की और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक संविधान लिखने की दिशा में कदम बढ़ाया। वर्ष 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान में बहुदलीय व्यवस्था, नियमित चुनाव और केंद्र एवं राज्यों में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान है। यही चीन और भारत के बीच सबसे बड़ा अंतर है

भाजपा और आरएसएस: शुरुआत में जनसंघ, और बाद में भारतीय जनसंघ तथा इसके वर्तमान स्वरूप में भारतीय जनता पार्टी ने देश के संविधान में विश्वास रखा। इसे एक लोकतांत्रिक दल के रूप में पोषित किया गया और राजनीतिक तौर पर दक्षिणपंथ में स्थापित किया गया। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग दिखना चाहती थी, जो वामपंथी खेमे में थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा वर्षों तक एक लोकतांत्रिक पार्टी बनी रही। हालांकि, भाजपा के राजनीतिक गुरु आरएसएस का देश की शासन प्रणाली और राजनीतिक संरचना के बारे में एक अलग दृष्टिकोण था और आज भी है- आरएसएस का मानना है कि भारत एक भाषा, एक संस्कृति, एक राजनीतिक दल और यथासंभव एक धर्म वाला देश होना चाहिए।

प्रधानमंत्री और भाजपा के वास्तविक नेता नरेंद्र मोदी एक ऐसे विचारक हैं, जो भारत के संबंध में आरएसएस के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही वे इस बात को भी भलीभांति समझते हैं कि आरएसएस का लक्ष्य केवल चुनावी जीत से नहीं, बल्कि सुनियोजित कदमों से ही हासिल किया जा सकता है। वर्ष 2014 से मोदी सरकार द्वारा उठाए गए संवैधानिक, विधायी और प्रशासनिक कदमों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और समान नागरिक संहिता के लिए मोदी का पुरजोर समर्थन, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम का लागू होना, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 162 तथा संविधान के भाग 11, 12 और 14 के प्रावधानों की रचनात्मक व्याख्या, तथा एक राष्ट्र एक चुनाव (ओएनओई) को लागू करने का दृढ़ प्रयास, ये सभी तथाकथित विकसित भारत की स्थापना के लिए उठाए गए सुनियोजित कदम हैं।

उम्मीद और निराशा: वर्ष 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी प्रभावशाली रहे। उन्हें पूरा भरोसा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता उनकी पार्टी को 400 से अधिक सीटें देगी, लेकिन उन्हें करारा झटका लगा- जनता ने उन्हें केवल 240 सीटें दीं, जो कि 543 सीटों के साधारण बहुमत से भी कम है। इसके बाद से उनके सभी प्रयास वर्ष 2029 से पहले खोई हुई जमीन को वापस पाने पर केंद्रित हैं।

मान लीजिए कि भाजपा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 पारित करने में सफल हो जाती, तो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की आड़ में यह विधेयक परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के मनमाने ढंग से सीमांकन को अंजाम दे देता। नए कानून और उनका क्रियान्वयन दक्षिणी राज्यों को देश के शासन में अप्रासंगिक बना देता। इसके अलावा, भाजपा दबाव बनाकर संसद में अन्य संविधान संशोधन भी आसानी से पारित करा लेती, जिनमें 'एक राष्ट्र एक चुनाव' लागू करने का विधेयक भी शामिल है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों तक भाजपा को लगता था कि उसके पास चुनाव जीतने का एक कारगर फार्मूला है- नौ हिंदी भाषी राज्यों, गुजरात और जम्मू के जिलों में एक कठोर संगठनात्मक तंत्र, हिंदी जानने वाले राज्यों महाराष्ट्र और पंजाब में एक सक्षम पार्टी, धन बल, निर्देशों का अनुपालन करने वाले राज्यपाल, डरा हुआ नौकरशाही तंत्र, तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और अभियोजन चलाने की शक्ति रखने वाली आज्ञाकारी जांच एजंसियां, मीडिया पर पकड़, चुनाव आयोग का मौन समर्थन और एक संयमित न्यायपालिका। मगर पूर्ण सत्ता के रास्ते में बाधाएं दक्षिणी राज्य, पश्चिम बंगाल और विपक्ष की एकता थीं। इसीलिए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के विचार को आगे बढ़ाया गया।

एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को हराना होगा: मुझे डर है कि अगर 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक पारित हो गया, तो विपक्षी गठबंधन बिखर सकता है। क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी गठबंधन बनाती हैं। इनमें आपस में मतभेद हैं और ये राज्य विधानसभा और स्थानीय निकायों में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। साथ ही, इनमें लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनाने की क्षमता भी है, जैसा कि उन्होंने वर्ष 2024 में किया था। इन दलों को अपने मतभेदों को दूर करके एकजुट होना होगा और एक ऐसा गठबंधन बनाना होगा, जो उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने का सबसे अच्छा मौका देगी। हालांकि, 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक अगर पारित होता है, तो इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और अंततः स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने होंगे। एक साथ चुनाव होने से विपक्षी गठबंधन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए भाजपा इस विधेयक केपारित करने को अपनी बड़ी रणनीति का एक अहम हिस्सा मानती है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से यह सबक मिलता है कि कई दलों द्वारा विपक्षी गठबंधन बनाने के बावजूद वे भाजपा को नहीं हरा सके.

ड्रग्स के साथ पांच तस्कर धराये

मोबाइल एवं बाइक जब्त

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

बारसोई /कटिहार। आबादपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी 5 तस्कर के साथ 36.21 ग्राम स्मैक बरामद। गुप्त सुचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आबादपुर पुलिस ने मंगलवार की देर रात दो अलग-अलग स्थानों से छापेमारी कर कुल पांच स्मैक के तस्कर को रंगे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष मोहम्मद शादाब ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र से बाईक में सवार हो कर दो युवकों के द्वारा अत्यंत नशीला मादक पदार्थ स्मैक लाया जा रहा है। दोनों युवकों को पीछा किया गया।

थाना क्षेत्र स्थित बेराखोर ग्राम के समीप दोनों ही युवकों को धर दबोच लिया गया। तलाशी के क्रम में जलाल पिता लतीफुर से 9.43 ग्राम स्मैक तथा सद्दाम पिता जलालूद्दीन से 10.21 ग्राम स्मैक की बरामदगी की गई है। दोनों ही युवक आबादपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर पंचायत स्थित हाट-बलरामपुर ग्राम निवासी बताये जा रहे हैं। मौके से दोनों ही युवकों के पास से दो मोबाईल एवं उनकी बाईक को भी जब्त कर लिया गया है।

वहीं दूसरे मामले की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को यह गुप्त सुचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के लगूवा पंचायत स्थित बालदियागाछी ग्राम में कुछ युवकों के द्वारा नशे का अवैध कारोबार किया जा रहा है। देर रात बलदियागाछी ग्राम में पहुंच कर तीन युवकों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में से अफसर पिता ताहिर के पास से 5.72 ग्राम ड्रग्स की पुरिया तथा कबीर पिता अब्दुल समर के पास से 5.64 ग्राम ड्रग्स एवं हिसाबुल

पिता अब्दुल समर के पास से 5.21ग्राम ड्रग्स की पुरिया बरामद की गई है। तीनों ही युवक बलदियागाछी निवासी बताये जा रहे हैं। उक्त पांचों युवकों के पास से बरामद स्मैक(फुटुस) की कुल वजन 36.21ग्राम है। नशे के सौदागर उक्त पांचों युवकों पर एनडीपीएस के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें बुधवार को जेल भेज दिया गया। तथा पुलिस मामले की अनुसंधान कर रही है। वहीं स्मैक बेचने वाले की गिरफ्तारी से क्षेत्र के लोग राहत की सांस ली है तथा आबादपुर पुलिस की प्रशंसा कर रही है।

घर के आगे से ट्रैक्टर की चोरी, सीसीटीवी में कैद

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कुरसेला / कटिहार। थाना क्षेत्र के नगर पंचायत वार्ड संख्या 7 स्थित ट्रायसेम भवन के समीप मंगलवार की रात एक ट्रैक्टर की चोरी हो गई। चोरों की यह पूरी करतूत पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामले को लेकर पीड़ित ने थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित कामेश्वर मंडल ने बताया कि उनका ट्रैक्टर प्रतिदिन डीपू में काम करता है। मंगलवार की शाम उनका बेटा ट्रैक्टर को घर के आगे खड़ा कर दिया था। रात करीब 11 बजे परिवार के सभी लोग खाना खाकर सो गए।बुधवार सुबह जब वे उठकर बाहर निकले तो ट्रैक्टर गायब मिला। उन्होंने बताया कि घर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज में रात 12:36 बजे चोर के द्वारा ट्रैक्टर ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। घटना के बाद से परिवार में चिंता का माहौल है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।

मुख्यमंत्री से मिले पूर्व विधायक केशरी

क्षेत्र की लंबित विकास योजनाओं पर की चर्चा

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

फारबिसगंज। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फारबिसगंज के भाजपा के पूर्व विधायक विद्या सागर केशरी ने शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्र की विभिन्न लंबित विकास योजनाओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर श्री केशरी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सिंचाई एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष मजबूती से रखा।

उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता लंबित योजनाओं के पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विषयों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने एवं शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया।

यह महत्वपूर्ण मुलाकात क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देने और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने

की दिशा में एक सार्थक एवं प्रभावशाली पहल मानी जा रही है। पूर्व विधायक विद्या सागर केशरी ने कहाह्न जनता की आवाज को मजबूती से उठाना और उनके अधिकारों के लिए निरंतर प्रयास करना ही सच्ची जनसेवा का मूल मंत्र है।

संक्षिप्त खबरें

समेली में अनियंत्रित पिकअप पलटी, कोई हताहत नहीं

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कुरसेला /कटिहार। थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर समेली प्रखंड कार्यालय के समीप बुधवार की सुबह एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई। पुलिस फरार चालक की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप पटना से चप्पल लोड कर कटिहार की ओर जा रही थी। इसी दौरान समेली के पास वाहन चालक संतुलन खो बैठा, जिससे वाहन सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। हादसे के बाद पहुंचे स्थानीय लोगों ने चालक को पीकअप से सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

कार्यपालक पदाधिकारी को दी गयी श्रद्धांजलि

कुरसेला /कटिहार। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की गोली मारकर हत्या के बाद कुरसेला नगर पंचायत में शोक की लहर है। बुधवार को नगर पंचायत कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर कर्मियों व जनप्रतिनिधियों ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। 28 अप्रैल को सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिनदहाड़े फायरिंग में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार को गोली लगी थी। भागलपुर ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना में सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू गंभीर रूप से घायल हैं। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि संजीव कृष्णन उर्फ गुड्डू यादव ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बढ़ती आपराधिक घटनाएं चिंताजनक हैं और सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

हज के लिए मक्का रवाना

सालमारी /कटिहार। बलिया बेलौन क्षेत्र से बुधवार को दर्जनों जायरीन हज के लिए मक्का शरीफ रवाना हुए।हज की अदायगी के लिए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की जियारत कर खाने काबा का तव्वाफ करने के साथ मस्जिदें नबवी में इबादत करने के बाद हज का अरकान की अदायेगी की जायेगी। हज के लिए रवाना हो रहे जामीया ताजुस शरीया लील बनात शेखपुरा रेजा नगर के नाजीम रहबरे शयीयत मौलाना मुफ्ती मोजीबुर रहमान मिस्बाही रिजवी ने बताया की अहले निशाब पर हज वाजिब है। इस्लाम के पांच अरकान में से हज भी एक अरकान है। हज जिलहिज्जा के महिने के 10 वीं तारिख को अदा की जाती है। इस मौके पर खाने काबा का तव्वाफ, मस्जिदें नबवी में नमाज अदा करना, शैतान को कंकर मारना होता है, सफा मरवा का चक्कर लगाना आदि खान अरकान है। हज के लिए रवाना करते हुए स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि एकबाल हुसैन ने जायरीन से देश में अमन, शांति, भाईचारा, बीमार को सफा के लिए दुआ करने की दरखास्त की है। इस अवसर पर मारूफ अली, सालीम जर्राह, अनीस, अरब आलम, हाजी मुजफ्फर यजदानी, शाबान, जावेद आलम आदि ने अकीदत के साथ हज के लिए रवाना किये।

कुरेठा रेलवे स्टेशन से मनिया एनएच 81 जर्जर, राहगीर परेशान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मनसाही/कटिहार। प्रखंड क्षेत्र के कुरेठा पंचायत के कुरेठा रेलवे स्टेशन से मनिया एन एच 81 तक कुल 4.150 किमी की सड़क पिछले कई माह से लगातार जर्जर एवं गड्ढे में तब्दील हो चुका हैं। मगर संवेदक गहरी नींद में सोई हुई हैं। त्रिमूर्ति इंजिकान्स एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सड़क की मरमती के साथ-साथ पक्की करण को लेकर मनिया के समीप बोर्ड भी लगाया गया हैं।

जिसका कार्य आरंभ की तिथि 20 - 11- 2025 हैं जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 19 - 11 - 2026 हैं इसके उपरांत भी संवेदक अपना समय किसी तरह से पास कर रहा हैं जर्जर सड़क गड्ढे में तब्दील होने से रोजमर्रा करने वाले आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं जबकि हल्की बारिश होने से बीच सड़क

पर गड्ढे में पानी भर जाने के कारण सड़क झील में तब्दील हो जाता हैं इसके उपरांत भी लगे बोर्ड में संवेदक का फोन नंबर पर कई वार ग्रामीणों ने फोन किया फोन पर उन्होंने जवाब दिया कि जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा ऐसे लापरवाह संवेदक के कारण जर्जर सड़क में आए दिन घटना दुर्घटना होते रहते हैं पांच माह बीत जाने के बाद भी कार्य आरंभ नहीं होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त हैं यह आक्रोश सड़क जाम में कभी भी तब्दील हो सकता हैं।

विशेष कैंप का आयोजन

हसनगंज। प्रखंड में बुधवार को उत्क्रमित उच्च विद्यालय और उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं बीआरसी में एचपीवी वैक्सीन का दूसरा डोज और गार्डासिल वेक्सिनेशन के लिए विशेष कैंप लगाया गया। साथ ही चिकित्सकों द्वारा बच्चियों को इस वैक्सीन के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रभारी चिकित्सा प्रभारी आयुष भारद्वाज ने बताया कि महिलाओं में होने वाले सर्वाइवल कैंसर एक गंभीर बीमारी है,जिसके बचाव के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कैंप के माध्यम से बच्चियों को जागरूक किया जा रहा है और वैक्सीन के बारे सही जानकारी दी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गार्डासिल वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। सोशल मीडिया व यूट्यूब पर इसके बारे फैलाई जा रही गलत फहमियो को दूर करने के लिए बच्चियों को समझाया गया कि यह टीका सुरक्षित और प्रभावी है। यह वैक्सीन मुख्य रूप से 14 से 15 वर्ष की बच्चियों को दिया जाता है,ताकि भविष्य में गर्भाशय के कैंसर से बचाव हो सके। साथ ही 9 से 14 वर्ष की वो बच्चियां जिन्होंने एचपीवी का पहला डोज ले लिया है,उनके दूसरे डोज के लिए भी कैंप पीएचसी मे अभियान चलाया जा रहा है।

पर्यटन विभाग की टीम ने मंदिर का किया निरीक्षण

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

आलमारी /कटिहार। बाबा गोरखनाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। बिहार सरकार पर्यटन विभाग की ओर से 14 करोड़ 25 लाख 71 हजार की राशि से बाबा गोरखनाथ

धाम मंदिर का सौंदर्यीकरण हो रहा है। मंगलवार को पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता विकास कुमार, सहायक अभियंता विशाल कुमार, आर्किटेक्ट इंजिनियर माधव भारद्वाज के द्वारा बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर पहुंच कर निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संवेदक को आवश्यक निर्देश देते हुए निर्माण कार्य शीघ्र पुर्ण करने की सलाह दी गयी। कमेटी के सचिव पिंटू यादव ने बताया कि बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने के लिए बिहार सरकार द्वारा विकास कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बाबा गोरखनाथ धाम मंदिर में निर्माण कार्य का निरीक्षण विभाग के अभियंता की टीम द्वारा किया गया। विशेष रूप से मंदिर परिसर में स्थित शिव गंगा तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य श्रावण पूर्णिमा से पहले पूर्ण करने कि बात कहे। ताके कांवरियों को असुविधा नहीं हो। इस अवसर पर मंदिर न्यास समिति के सचिव पिंटू यादव, प्रदीप शर्मा,चन्दन यादव, देवनारायण नुनिया, पंचा यादव, सनी यादव,फनी सिंह , श्यामनगर यादव सहित अन्य कमेटी सदस्य उपस्थित रहे ।

मॉडल स्कूल को रद्द करने की मांग को ले चलाया हस्ताक्षर अभियान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

मनसाही/कटिहार। उच्च विद्यालय हफलागंज में कक्षा नवम में नामांकन को लेकर छात्र - छात्राओं को हो रही परेशानी तूल पकड़ रही हैं और उच्च विद्यालय को बनाए गए मॉडल स्कूल को रद्द करने की मांग तेज हो गई हैं। इस संबंध में छात्र - छात्राओं के अभिभावकों ने पंचायत में हस्ताक्षर अभियान चला कर शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव,स्थानीय सांसद, विधायक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के नाम आवेदन देकर मॉडल स्कूल को हटाने की मांग करेंगे। मामले को लेकर पंचायत के मुखिया मुकेश पासवान ने बताया कि सिरनिया पश्चिम पंचायत हफलागंज में एकमात्र हाई स्कूल हैं हजिसे मॉडल स्कूल बना दिया गया हैं।

बताया गया कि जहां मात्र 120 विद्यार्थियों का ही नामांकन लिया जाना हैं जबकि यहां छः सरकारी एवं निजी विद्यालय हैं जहां से हर साल 300 से 400 छात्र-छात्राएं कक्षा आठ की परीक्षा पास कर उच्च विद्यालय हफलागंज में नवम कक्षा में नामांकन लेते हैं। ऐसे में मॉडल विद्यालय में 120 नामांकन लेने के बाद सरकारी एवं निजी विद्यालय के छात्र-छात्राएं नामांकन के लिए भटक रहे हैं। और शिक्षा विभाग के कार्यालय के चक्कर भी काट रहे हैं जो कहीं से ठीक नहीं हैं । अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं और वर्तमान और भविष्य में नामांकन को लेकर आने वाली समस्याओं को देखते हुए मॉडल विद्यालय को हफलागंज से हटाने की मांग कर रहे हैं।

अभिभावक अमित कुमार साह, संजीव कुमार साह,मो. निजाम, मोतीलाल गुप्ता आदि ने बताया कि उनके बच्चे निजी विद्यालय से परीक्षा पास किए हैं जिसका नामांकन उच्च विद्यालय हफलागंज में नहीं हो रहा हैं। इस संबंध में विभाग के द्वारा नामांकन को लेकर कोई आदेश भी नहीं निकाला जा रहा हैं जिससे वे लोग परेशान हैं। अभिभावकों ने सरकार एवं प्रशासन से छात्र-छात्राओं के नामांकन को लेकर आवश्यक कदम उठाने की मांग की हैं।

भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही विकास योजना

पुरानी पीसीसी सड़क पर ही करा दी 'खानापूर्ति' वाली ढलाई

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

कोढ़ा /कटिहार। प्रखंड के भटवाड़ा पंचायत वार्ड संख्या 10 विकास के नाम पर सरकारी फंड की बंदरबांट का एक नया मामला जिला परिषद की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। भटवारा पंचायत के वार्ड संख्या 10 में जिला परिषद द्वारा कराई जा रही पीसीसी सड़क ढलाई विवादों के घेरे में है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने पहले से बनी हुई अच्छी-खासी पीसीसी सड़क के ऊपर ही दोबारा ढलाई कर दी है, जो सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, संबंधित स्थल पर पहले से ही एक मजबूत पीसीसी सड़क मौजूद थी। नियमानुसार, अगर सड़क जर्जर हो तो उसे मरम्मत की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ विभाग ने पुरानी सड़क को तोड़ने या उसे आधार बनाने के बजाय, उसके ऊपर ही सीमेंट की एक पतली परत

चढ़ा दी। अच्छी स्थिति वाली सड़क पर दोबारा काम करना केवल फंड खत्म करने की साजिश नजर आती है। कार्य में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता बेहद निम्न स्तर की बताई जा रही है, जिससे सड़क के जल्द ही उखड़ने का डर बना हुआ है। बिना बेस तैयार किए पुरानी सड़क पर ढलाई करना तकनीकी रूप से गलत है।

विभागीय जेई का तर्क: ₹मरम्मत का काम है₹ जब इस मामले को लेकर जिला परिषद विभाग के जेई बलवंत सिंह से संपर्क किया गया, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह कोई नई सड़क का निर्माण नहीं, बल्कि रिपेयरिंग (मरम्मत) का कार्य चल रहा है।

हालांकि, ग्रामीणों का तर्क है कि अगर यह मरम्मत है, तो रिपेयरिंग के नाम पर पूरे वार्ड की पुरानी सड़कों पर कंक्रीट की परत बिछाना सार्वजनिक धन की बबार्दी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्य की जांच नहीं की गई और गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ, तो वे इसकी शिकायत जिला अधिकारी और उच्चाधिकारियों से करेंगे। लोगों का कहना है कि जहाँ पंचायत में कई जगहों पर नई सड़कों की सख्त जरूरत है, वहाँ बनी-बनाई सड़क को दोबारा ढालना समझ से परे है।

सरकारी पैसे का इस तरह दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेई साहब इसे रिपेयरिंग कह रहे हैं, लेकिन धरातल पर यह सिर्फ खानापूर्ति है। अब देखना यह होगा कि क्या जिला प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर कार्य की जांच कराता है या ₹रिपेयरिंग₹ के नाम पर इसी तरह सड़कों पर सीमेंट की परतें चढ़ाकर कागजी खानापूर्ति चलती रहेगी।

शोक सभा का आयोजन

बारसोई /कटिहार। नगर पंचायत बारसोई में नगर कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को कृष्ण भूषण कुमार नगर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुल्तानगंज के आत्मा की शांति हेतु शोक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए नगर कार्यपालक पदाधिकारी रजनीश कुमार ने कहा कि श्री कृष्ण भूषण कुमार बिहार नगर सेवा के कर्तव्यनिष्ठ एवं कर्मठ पदाधिकारी थे। उनकी हत्या नगर परिषद कार्यालय सुल्तानगंज में कर्तव्य निर्वहन के दौरान कर दी गई। श्री कुमार ने अपनी जान को परवाह न करते हुए अपराधियों से संघर्ष किया और इसी क्रम में वह शहीद हो गए। इस निर्मम हत्या की घटना पर नगर कार्यपालक पदाधिकारी बारसोई रजनीश कुमार एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा दो मिनट का मौन रख कर उनके आत्मा की शांति एवं उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करने हेतु ईश्वर से कामना की गई। रजनीश कुमार ने कहा कि सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को मुआवजा एवं सुरक्षा प्रदान किया जाए। पूरे परिवार काफी दहशत में है।

नशा मुक्ति सह जागरूकता अभियान

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

समेली /कटिहार । प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय बिष्णुचक खैरा के छात्र-छात्राओं के बीच नशा के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाया गया ।इस अवसर पर प्रधान शिक्षक केशव कुमार मंडल के कुशल नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विधालय मलहरिया के बीके अमन , सुनील कुमार शर्मा, शिक्षिका साधना शर्मा के द्वारा छात्रों के बीच नशा मुक्ति सह जागरूकता अभियान का सफल आगाज किया गया ।छात्र-छात्राओं को नशीले पदार्थों से दूर रहने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई ।उन्हें जीवन में नशा से बचने के लिए कई तरह के टिप्स बताए गए। छात्र-छात्राओं को सही मार्गदर्शन देने हेतु गतिविधि कर छात्रों को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया गया । छात्रों को बताया गया कि इन दोनों सुखा नशा का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। इस बढ़ते सुखा नशे की चपेट में खासकर युवा पीढी ही आ रहे हैं। चिंताजनक बात यह है कि

छोटे-छोटे बच्चे भी इस दलदल में फंसते नजर आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून के बाद नशे के आदि लोगों के लिए शराब मंहगी और दुर्लभ हो गई है। जिससे लोग आसानी से मिलने वाले सुखा नशा जो चाय पान , किराना दुकान आदि जगहों पर सुलभ मिल रहा है। जिससे लोग आसानी से मिलने वाला सुखा नशा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं ।अगर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाला समय में यह सामाजिक , पारिवारिक दुष्परिणाम सामने आ सकता है ।ऐसे में जरूरी है कि अभिभावक, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रशासन के साथ मिलकर नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ-साथ बिक्री पर भी रोक लगाकर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मौके पर विद्यालय के सभी शिक्षक छात्र उपस्थित रहे ।

मगही एवं भोजपुरी भाषा को संविधान की अनुसूची आठ में शामिल करने की मांग

नवबिहार टाइम्स संवाददाता

गयाजी। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल सहित देश के कई राज्यों के बोल-चाल की प्रचालित लोकप्रिय भाषा मगही और भोजपुरी को संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकताओं ने केंद्र एवं राज्य सरकारों से किया है।

मांग करने वालों में बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के प्रदेश प्रतिनिधि सह प्रवक्ता विजय कुमार मिट्ठू, पूर्व विधायक मोहम्मद खान अली, जिला कॉंग्रेस उपाध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद सिंह, दामोदर गोस्वामी, विपिन बिहारी सिन्हा, विशाल कुमार, मोहम्मद शामिम आलम, मुन्ना मांझी, प्रद्युम्न दुबे, अशोक राम, रूपेश चौधरी आदि ने कहा कि वर्षो से बिहार सहित कई राज्यों के लोगों के द्वारा मगही और भोजपुरी भाषा को संविधान के अनुसूची में शामिल कराने की मांग को केंद्र एवं राज्य सरकारें अनसुनी किए हुए हैं। देश के 22 भाषायें संविधान के अनुसूची आठ में शामिल है। केंद्र की मोदी सरकार एक भी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में अभी तक शामिल किया है, जबकि पूर्व की सरकार ने 2003 में संविधान में 92 वां संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी को जोड़ा गया था। नेताओं ने कहा कि इन दोनों भाषाओं की पढ़ाई राज्य के मगध विश्वविद्यालय में मगही भाषा की तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में भोजपुरी भाषा वर्षो से पढ़ाई जारी है, परंतु संविधान के आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं होने से देश एवं राज्य के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन विषयों को शामिल नहीं करने से इस भाषा को जानने और पढ़ने वालों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।

नेताओं ने कहा कि मगही और भोजपुरी भाषा का इस्तेमाल फि ल्मों, सोशल मीडिया, कला के क्षेत्रों में काफी हो रहा है, तथा इसे देखने और सुनने वालों की संख्या काफी अधिक है। नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री से अविलंब मगही और भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग दोहराई है।

टैरिफ की जगह अब इंपोर्ट टैक्स लगाएंगे ट्रंप

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पसंदीदा टैरिफ (आयात शुल्क) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद अब एक नया रास्ता निकाला है। ट्रंप प्रशासन अब उन स्टॉपगैप (अस्थायी) टैक्स को स्थायी टैरिफ में बदलने की कोशिश कर रहा है, जिनकी समय सीमा अगले तीन महीनों में खत्म होने वाली है।

अमेरिकी खजाने में रेवेन्यू का प्रवाह बनाए रखने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था के चारों ओर एक संरक्षणवादी दीवार खड़ी करने के लिए प्रशासन युद्धस्तर पर काम कर रहा है। ट्रंप प्रशासन को उन अस्थायी 10 प्रतिशत टैरिफ को बदलने के लिए 24 जुलाई तक का समय है, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद लगाए गए थे।

नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले, महंगी वस्तुओं से परेशान जनता के बीच इस नए टैक्स का भारी विरोध हो सकता है। अगर ट्रंप नया टैक्स इंपोर्ट टैक्स लाते हैं तो इसका असर भारत पर भी दिखाई दे सकता है। ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया था तो सबसे ज्यादा दर वाले देशों में भारत भी था। ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया था।

क्या है ट्रंप का नया प्लान

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय इस सप्ताह दो प्रमुख जांच शुरू करने जा रहा है, जिनका अंत नए अमेरिकी टैरिफ के रूप में होने की उम्मीद है :

1. **जबरन श्रम की जांच:** इसमें नाइजीरिया से लेकर नॉर्वे तक की 60 अर्थव्यवस्थाओं की जांच की जा रही है, जो अमेरिका के कुल आयात का 99 प्रतिशत हिस्सा हैं। इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या ये देश जबरन श्रम से बने प्रोडक्ट के व्यापार को रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठा रहे हैं। स्न्नक्र जैमीसन ग्रीर के अनुसार, अमेरिकी कंपनियां उन विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकतीं जो जबरन श्रम के जरिए लागत कम करते हैं।
2. **अत्यधिक उत्पादन की जांच:** अगले हफ्ते चीन, यूरोपीय संघ और जापान सहित 16 व्यापारिक भागीदारों की जांच होगी। आरोप है कि ये देश वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कीमतें गिर रही हैं और अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। 70 प्रतिशत आयात के लिए जिम्मेदार हैं।

क्यों रद्द हुए थे पुराने टैरिफ

दो महीने पहले फरवरी को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पुराने टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का इस्तेमाल करके भारत समेत लगभग हर देश पर भारी टैक्स थोप दिया था। अदालत ने फैसला सुनाया कि उपयोग टैरिफ लगाने के लिए नहीं किया जा सकता। अब सरकार को आयातकों को वह पैसा रिफंड करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रंप अब 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का सहारा ले रहे हैं। इस कानून के तहत टैरिफ की दर पर कोई सीमा नहीं है। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ इसी कानून का इस्तेमाल किया था, जिसे अदालती चुनौती मिलने के बावजूद बरकरार रखा गया था। ये टैरिफ 4 साल तक प्रभावी रहते हैं और इन्हें आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आलोचक अमेरिका की इन जांचों को एक दिखावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने पहले ही तय कर लिया है कि वे टैरिफ लगाएंगे, जांच तो बस एक औपचारिकता है। क्योंकि आयातक ऊंची कीमतों के रूप में इसका बोझ आम जनता पर डालेंगे।

होर्मुज का गेट बंद हुआ तो सऊदी और यूएई ने निकाला 'सीक्रेट' रास्ता, भारत में नहीं होगी कच्चे तेल की कमी

नई दिल्ली, एजेंसी। वैश्विक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य में तेल आपूर्ति बाधित होने के बावजूद भारत के लिए राहत की खबर है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रूप से अपने शिपमेंट को वैकल्पिक बंदरगाहों पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। शिप-ट्रैकिंग फर्म केप्लर के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निखिल दुबे ने बताया कि सऊदी अरब और यूएई से होने वाली सप्लाई में बढ़ोतरी, ईरान और वेनेजुएला से फिर से शुरू हुए आयात और रूस से लगातार हो रही खरीद ने खाड़ी देशों से होने वाले अन्य नुकसान की भरपाई कर दी है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान के कारण इराक, कुवैत और कतर जैसे देशों से सप्लाई अभी भी ठप है। इकनॉमिक टाइम्स के अनुसार इससे बचने के लिए सऊदी और यूएई ने मास्टर प्लान तैयार किया है। सऊदी अरब : अपनी 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता वाली ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को फारस की खाड़ी के रास

तनुरा से लाल सागर के यनबु टर्मिनल पर भेज रहा है। यूएई : अपनी 1.7 मिलियन बीपीडी क्षमता वाली एडीसीओपी पाइपलाइन' के जरिए तेल को फुजैरा बंदरगाह भेज रहा है, जो ओमान की खाड़ी में स्थित है। ओमान : चूंकि ओमान का तट सीधे अरब सागर से लगता है, उसे होर्मुज पार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वहां से भी सप्लाई 18,000 से बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई है। इराक से सप्लाई बंद होने के बावजूद इन वैकल्पिक रास्तों और नए सोर्स ने भारत में कच्चे तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की है और कीमतों में संभावित भारी उछाल को रोकने में मदद की है। अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील मिलने से भारतीय रिफाइनरियों को बड़ी मदद मिली है। वेनेजुएला : नौ महीने के अंतराल के बाद वेनेजुएला से 2.58 लाख तेल भारत पहुंचा। जनवरी में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों में ढील दी थी।

अनिल अंबानी पर ईडी का बड़ा एक्शन, 3035 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, खंडाला का फार्महाउस भी जब्त

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस कम्युनिकेशंस बैंक धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी ग्रुप की 3034.90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। इसके साथ ही रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप से जुड़े मामलों में कुल जब्त संपत्तियों का मूल्य 19,344 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। ईडी ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 5 के तहत की गई है, ताकि संपत्तियों के बिखराव को रोका जा सके और बैंकों व आम जनता के हितों की रक्षा हो सके। यह जांच सुप्रीम

कोर्ट के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की जांच के तहत की जा रही है, जिसमें बैंक और सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग तथा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल हैं। जांच के अनुसार आरकाम और उसकी समूह कंपनियों ने घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से भारी कर्ज लिया था, जिसमें से कुल 40,185 करोड़ रुपये अभी भी बकाया हैं। ईडी ने यह जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई उन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और शिकायतों पर अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई थीं। ईडी की जांच में प्रमोटर समूह की कई महत्वपूर्ण संपत्तियों का खुलासा हुआ, जिन्हें अब कुर्क कर लिया गया है : मुंबई : उषा किरण बिल्डिंग में स्थित एक फ्लैट। खंडाला (पुणे) : एक फार्महाउस। साणंद (अहमदाबाद) : जमीन का एक बड़ा हिस्सा।

बंद होने की कगार पर हैं, मदद करो, एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट ने खड़े किए हाथ

नई दिल्ली, एजेंसी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने सरकार से तत्काल मदद की गुहार लगाई है। उसका कहना है कि विमान ईंधन एटीएफ की मौजूदा कीमतें इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हैं। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में एफआईए ने कहा है कि इस दबाव के कारण एयरलाइन इंडस्ट्री अब बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। एफआईए एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट की भागीदारी वाला संगठन है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत में 73 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते घरेलू उड़ानों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से घाटे का सौदा बन गया है। फेडरेशन ने आगे कहा कि एटीएफ की कीमत में 73 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अब पूरी तरह से घाटे का सौदा बन गया है। एफआईए ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एटीएफ की कीमत में 73 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके चलते घरेलू उड़ानों के साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का संचालन भी व्यावहारिक रूप से पूरी तरह से घाटे का सौदा बन गया है। अप्रैल 2026 में एविएशन सेक्टर को इसके कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा है।' एयरलाइन संस्था के मुताबिक, 'अप्रैल 2026 की कीमतों से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बीच कोई समानता सुनिश्चित नहीं हो पाती है।' एफआईए ने कहा कि आमतौर पर ञ्जस्न की कीमतें एयरलाइन की कुल लागत का लगभग 30 से 40 फीसदी होती हैं। लेकिन, अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण कीमतों में हुई बढ़ोतरी के चलते अब की लागत एयरलाइन के कुल परिचालन खर्च का 55 से 60 फीसदी तक पहुंच गई है। संस्था ने आगे कहा, 'इसके अलावा, रुपया भी और कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे एटीएफ की कीमतों के मामले में एयरलाइंस पर और ज़्यादा बोझ पड़ गया है।'

युद्ध का बहुत ज्यादा असर

एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) की ये नई कीमतें ऐसे समय में आई हैं, जब अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध के कारण तेल और गैस की सप्लाई का संकट गहरा गया है। इस चल रहे संघर्ष के कारण होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी हो गई है। यह स्ट्रेट दुनिया की लगभग 20 फीसदी ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण रूट है। एयरलाइन संस्था ने बताया, 'मौजूदा संघर्ष के कारण ब्रेंट क्रूड की कीमतें 72 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 118 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इसके चलते एटीएफ की कीमतें 87.24 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 260.24 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थीं। यह 295 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। फिलहाल, इसकी कीमत 235.63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल चल रही है। मार्च 2025 की कीमतों की तुलना में काफी ज्यादा है। मौजूदा संकट के जवाब में एयरलाइन संस्था ने सरकार को तीन सुझाव दिए हैं।

भारत को झटका, 5 महीने के निचले स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ

आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खराब खबर

नई दिल्ली, एजेंसी। आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए खराब खबर है। भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ यानी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि मार्च में घटी है। यह घटकर पांच महीने के निचले स्तर 4.1 फीसदी पर आ गई। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच मार्च में

मैन्युक्चरिंग सेक्टर के सुस्त प्रदर्शन और बिजली उत्पादन के लगभग स्थिर रहने से ऐसा हुआ। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक अहम इकोनॉमिक इंडेक्टर माना जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आधार पर मार्च 2025 में देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.9 फीसदी की दर से बढ़ा था। मार्च 2026 का 4.1 फीसदी ग्रोथ का आंकड़ा पिछले पांच महीनों का सबसे निचला स्तर है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में ग्रोथ रेट 0.5 फीसदी रही थी। इसके साथ ही एनएसओ ने फरवरी 2026 के औद्योगिक उत्पादन आंकड़े को भी संशोधित कर 5.1 फीसदी कर दिया है। यह 5.2 फीसदी के पिछले अनुमान से थोड़ा कम है। औद्योगिक क्षेत्रों के आंकड़ों के आधार पर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ मार्च महीने में 4.3 फीसदी रही। पिछले साल के चार फीसदी के मुकाबले यह मामूली रूप से ज्यादा है।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ऐसा रहा हाल

मार्च 2026 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के 23 में से 14 उद्योग समूहों में पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की गई। इनमें 'बुनियादी धातु' (8.6 फीसदी), 'मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर' (18.1 फीसदी) और 'मशीनरी और उपकरण' (11.2 फीसदी) का प्रमुख रहा। 'मूल धातु' श्रेणी में एमएस स्लैब, अलॉय स्टील के फ्लैट उत्पाद व माइल्ड स्टील के एचआर कॉइल और शीट्स ने ग्रोथ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपयोग पर आधारित वर्गीकरण के अनुसार, पिछले महीने प्राइमरी गुड्स का इंडेक्स 173.3, कैपिटल गुड्स का 156.2, इंटरमीडिएट गुड्स का 181.4 और बुनियादी ढांचा/निर्माण वस्तुओं का 229.0 रहा। इसके अलावा, कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं का सूचकांक 146.2 और नॉन-कंज्यूमर ड्यूरेबल वस्तुओं का 150.6 रहा।

जोमैटो की पैरेंट कंपनी इंटरनल के शेयरों में 4.5 प्रतिशत की तेजी

नईदिल्ली, एजेंसी। जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के शेयरों में आज बुधवार की सुबह 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में यह उछाल तिमाही नतीजों की वजह से दर्ज की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इटरनल के शेयरों की कीमतों में मौजूदा स्तर से 95 प्रतिशत तक की तेजी की उम्मीद है। बीएसई में आज सोमवार इटरनल के शेयर 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के बाद 265 रुपये के स्तर पर ओपन हुए हैं। कुछ ही देर के बाद कंपनी के शेयरों का भाव 265.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, इटरनल के नेट प्रॉफिट में 346 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

एक्सचेंज को दी जानकारी में इस कंपनी ने बताया है कि जनवरी से मार्च 2026 के दौरान कुल 174 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हुआ है। जोकि सालाना आधार पर 346 प्रतिशत अधिक है। ब्लिंकिट और

जोमैटो की पैरेंट कंपनी का रेवन्यू साल दर साल आधार पर 196 प्रतिशत बढ़ चुका है। मार्च तिमाही में यह 17292 करोड़ रुपये

रहा है। ब्लिंकिट का नवंबर सालाना आधार पर 95 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 14386 करोड़ रुपये रहा है। ईबीआईटीडीए भी पॉजिटिव हो गया है। इस बार यह 37 करोड़ रुपये रहा है। बता दें, जोमैटो के रेवन्यू में सालाना आधार पर 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। मार्च तिमाही में यब 2737 करोड़ रुपये रहा है। नुवामा इक्विटी ने इटरनल के शेयरों के लिए रेटिंग दी है। ब्रोकरेज हाउस ने 380 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। बता दें, इस ब्रोकरेज हाउस ने पहले इटरनल के शेयरों के लिए 430 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया था। मोतीलाल ओसवाल ने भी इटरनल के शेयरों के लिए खरीदी रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 340 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। सितंबर 2027 के लिए 370 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज हाउस सीएलएसए ने 505 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है।

क्लाइमेट फंड रेनमैटर का समर्थन

किसानों की आमदनी 3 गुनी करने वाली एफ 4 एफ की सक्सेस स्टोरी नितिन कामथ की जुबानी

नईदिल्ली, एजेंसी। पिछले हफ्ते गर्मी ने कहर बरपाया। नागपुर में 45ए, अहमदाबाद में 44ए, प्रयागराज में 43ए, दिल्ली में 42ए तापमान रहा। बेंगलुरु में भी 37ए पहुंच गया

और अभी अप्रैल ही चल रहा है। तापमान बढ़ने का एक बड़ा कारण जंगलों का घटना है और भारत ने बहुत सारे जंगल खो दिए हैं। 2020 में हम 'फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट्स नाम की टीम से मिले थे।' यह जेरोधा के फाउंडर नितिन कामथ के उस ङ्ग पोस्ट का अंश है, जो उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को शाम 5:51 बजे किया था। इसे अबतक 4.91 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।

दरअसल कहानी यहां व्यूज की नहीं है। यह एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें पारंपरिक खेती की तुलना में किसानों की आमदनी 3 गुना बढ़ गई। एफ4एफ की शुरुआत 2019 में भारत में हुई। इसे अर्ति धर, आदित्य अविनाशे और कृतिका रविशंकर ने मिलकर स्थापित किया। ये टीम ईको सिसटम, ग्रामीण विकास और तकनीक के क्षेत्र से आती है। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाने की ठानी, जहां किसान सिर्फ फसल उगाने वाले न हों, बल्कि प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाले कार्बनदाता बनें। भारत में खेती अब भी सबसे बड़ी आजीविका का साधन है, लेकिन किसानों के सामने कम आय, बेमौसम बारिश और बंजर होती जमीन जैसी समस्याएं हैं। एफ4एफ का मानना है कि किसानों को प्रोत्साहित करके उनकी जमीन पर पेड़ लगाने और ईको सिस्टम सुधारने का काम किया जा सकता है। इसे कृषि-वानिकी (अग्रोफॉरेस्ट्री) कहते हैं। इससे न केवल मिट्टी अच्छी होती है, बल्कि जैव विविधता बढ़ती है और कार्बन क्रेडिट या टिकाऊ उपज से किसानों की अतिरिक्त आय भी होती है। यानी खेती को खत्म नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाना है। शुरुआत में ही नितिन कामथ के क्लाइमेट फंड रेनमैटर का समर्थन मिला। रेनमैटर ऐसे ही असरदार और बड़े पैमाने पर लागू होने वाले जलवायु समाधानों को अपनाता है। यह समर्थन देखकर लगा कि अब भारत के नए उद्यमी सिर्फ फिनटेक और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर जलवायु समाधानों पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में नितिन कामथ ने बताया कि उनकी टीम पहली बार 2020 में एफ4एफ से मिली थी। तब यह 50 एकड़ में काम कर रहा था। आज यह 5,000 एकड़ में फैल चुका है और अगले तीन साल में 40,000 एकड़ तक पहुंचने के लिए फंडिंग मिल चुकी है।

भारत नहीं लौटना चाहते एनआरआई

शख्स ने श्रीधर वेम्बु को चुन-चुनकर बताए कारण, कहा- सिर्फ 'वतन प्रेम' काफी नहीं

नई दिल्ली, एजेंसी। जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बु की ओर से अमेरिका में बसे भारतीयों से वतन वापसी की अपील के बाद एक नई बहस छिड़ गई है। शिकागो स्थित निवेशक विनीत के ने वेम्बु के 'ओपन लेटर' का जवाब देते हुए उन बुनियादी कारणों को गिनाया है, जिनकी वजह से प्रवासी भारतीय विदेश में ही रुकना पसंद करते हैं। विनीत के अनुसार, अब बात केवल ज्यादा पैसों की नहीं रह गई है, बल्कि यह बेहतर जीवनशैली और विश्वसनीय व्यवस्था से जुड़ी है। विनीत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में उन एनआरआई लोगों का अनुभव शेयर किया है जिन्होंने विदेश में रहने का फैसला किया है। उन्होंने इसके पीछे कई बुनियादी कारण बताए। उन्होंने लिखा है कि रोजमर्रा के जीवन में कम भ्रष्टाचार है। साथ ही बुनियादी सेवाओं के लिए जुगाड़ या पहचान पर

निर्भरता कम है। बेहतर बुनियादी ढांचा। अमेरिका में साफ-सुथरे शहर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बिना टेंशन वाली सड़कें हैं। अनुशासन और सुरक्षाः बेहतर नागरिक अनुशासन और आपात स्थिति के दौरान मजबूत सुरक्षा तंत्र है। स्थिरताः विनीत ने कहा कि यह विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी जीवन जीने का तरीका है।

क्या था श्रीधर वेम्बु का प्रस्ताव

श्रीधर वेम्बु ने हाल ही में अमेरिका में रह रहे भारतीयों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने तर्क दिया था कि देश को अपनी युवा आबादी का मार्गदर्शन करने के लिए अनुभवी प्रतिभाओं की जरूरत है। उन्होंने प्रवासियों से अपील की थी कि वे वापस आएं और भारत के तकनीकी नेतृत्व में योगदान दें। उन्होंने लिखा था कि भारत की वैश्विक स्थिति और समृद्धि तकनीकी ताकत पर निर्भर करेगी।

सिर्फ वतन प्रेम काफी नहीं'

विनीत ने सीधे सवाल किया कि आखिर प्रवासियों के पास वापस लौटने के लिए क्या प्रोत्साहन है उन्होंने कहा, 'हम आखिर कब तक सिर्फ मातृभूमि की भावना का हवाला देकर लोगों से लौटने की उम्मीद करते रहेंगे कई लोगों ने भारत को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जगह अपना जीवन बनाया है जहां सिस्टम उन्हें स्थिरता देता है।' उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो लोग भारत में रह रहे हैं, उन्हें बाहर वालों को वापस बुलाने के बजाय देश की घरेलू चुनौतियों को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। इंटरनेट पर एक बड़ी चर्चा को जन्म दे दिया है। एक तरफ वे लोग हैं जो मानते हैं कि प्रतिभा का देश वापस आना विकास के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ विनीत के तर्कों से सहमत लोग कह रहे हैं कि जब तक भारत में 'क्वालिटी ऑफ लाइफ' और 'सिविक सेंस' में सुधार नहीं होता, तब तक केवल भावनात्मक अपीलों से कुशल लोगों को वापस लाना मुश्किल होगा।

अब मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं

अभिनेत्री करिश्मा कपूर लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर हैं। हालांकि, उनका कहना है कि वो अब समय को ज्यादा महत्व देती हैं और चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर ही काम करना चाहती हैं। हाल ही में अभिनेत्री ने अपने करियर और काम के प्रति अपने जुनून को लेकर बात की। उन्होंने बताया कि अब वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं।

अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं

करिश्मा कपूर ने दशकों से इंडस्ट्री को करीब से देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज काम जुनून और उद्देश्य से जुड़ा है। मैं इंडस्ट्री में पली-बढ़ी हूं और मुझे कमर्शियल ब्लॉकबस्टर से लेकर एक्सपेरिमेंटल फिल्मों तक, हर तरह की भूमिकाएं निभाने का सौभाग्य मिला है। अब हर जगह मौजूद रहने के बजाय मैं उन प्रोजेक्ट्स को चुनती हूं जो मेरे दिल को छूते हैं। अभिनेत्री स्वीकार करती हैं कि अब समय उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले लगातार काम करने और एक सेट से दूसरे सेट पर जाने की वजह से काफी भागदौड़ रहती थी। अब मैं समय को ज्यादा महत्व देती हूं। मैं सोच-समझकर प्रोजेक्ट चुनती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि हर प्रोजेक्ट के लिए समय निकालना सार्थक हो और साथ ही परिवार को भी पर्याप्त समय मिल सके। स्क्रिप्ट तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही लोग और कहानी के पीछे का मकसद भी मायने रखता है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि बड़े पर्दे का अपना ही जादू है, यहीं से मैंने शुरुआत की थी और यह हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह रखेगा। लेकिन मुझे यह भी पसंद है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ कहानी कहने का तरीका कैसे विकसित हुआ है। वेब मुश्किल कहानियों और अलग-अलग तरह के किरदारों के लिए मौका देता है। मेरे जैसी किसी के लिए जो आगे क्या करना है, इस बारे में सोच-समझकर फैसला लेती है यह एक बेहतरीन क्षेत्र है। हालांकि, मैं बड़े पर्दे को कभी नहीं छोड़ूंगी।

वर्कफ्रंट की बात करें तो करिश्मा कपूर आखिरी बार साल 2024 में आई मर्डर-मिस्ट्री फिल्म 'मर्डर मुबारक' में नजर आई थीं। यह एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जो ओटीटी पर रिलीज हुई थी। हालांकि, फिल्म को खास प्रतिक्रियाएं नहीं मिली थीं। उनके आगामी प्रोजेक्ट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है।

'कॉकटेल 2' में होगी दीपिका पादुकोण की एंट्री, वेरोनिका के किरदार में करेंगी वापसी?

दीपिका पादुकोण बीते दिनों अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा के बाद सुर्खियों में आ गई थीं। इस बीच अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने वेरोनिका के किरदार में वापसी कर सकती हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में अपने 'कॉकटेल' के किरदार में ही कैमियो कर सकती हैं। जानिए आखिर क्यों उठीं ऐसी चर्चाएं हैं और क्या है सच्चाई?

ऐसे शुरू हुई चर्चाएं

दरअसल, रेडिट पर एक पोस्ट के बाद से ही फैंस के बीच इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि दीपिका 'कॉकटेल 2' में 2012 की 'कॉकटेल' के लोकप्रिय और बिंदास किरदार वेरोनिका में कैमियो करेंगी। पोस्ट के अनुसार, दीपिका कुछ महीने पहले मैडॉक फिल्म्स के ऑफिस गई थीं। उस समय कई लोगों ने अनुमान लगाया था कि यह मुलाकात 'महावतार' से जुड़ी थी। लेकिन पोस्ट में दावा किया गया है कि दरअसल उन्हें सीक्वल में वेरोनिका के किरदार में आने के लिए बार-बार संपर्क किया जा रहा था। उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और उसी दौरान अपने हिस्से की शूटिंग भी कर ली।

'कॉकटेल' में दीपिका ने किया था वेरोनिका का किरदार

वेरोनिका दीपिका के सबसे चर्चित किरदारों में से एक है। 2012 में आई 'कॉकटेल' में वेरोनिका अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा (डायना पेंटी) और उसके लवर गौतम (सैफ अली खान) के साथ लव ट्रायंगल में फंस जाती है। हालांकि, अभी तक दीपिका के फिल्म में कैमियो करने की अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इस चर्चा ने 'कॉकटेल 2' को लेकर नई हलचल मचा दी है, जो पहले से ही अपनी कास्ट, संगीत और माहौल के लिए ध्यान आकर्षित कर रही है।

19 जून को रिलीज होगी 'कॉकटेल 2'

होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 2012 की 'कॉकटेल' का सीक्वल है। हालांकि, इस बार फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग होने की बात कही जा रही है। फिल्म में रोमांस, प्यार और रिश्तों को एक अलग तरह से दिखाया जाएगा। हाल ही में फिल्म का पहला गाना रिलीज किया गया है, जिसे पसंद भी किया जा रहा है। 'कॉकटेल 2' 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

मृणाल ठाकुर की जगह श्रुति हासन होंगी 'पेद्दी' का हिस्सा

राम चरण की अदाकारी वाली फिल्म 'पेद्दी' जून 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले ही काफी चर्चा में है। बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है। खबरें हैं कि फिल्म के निर्माता श्रुति हासन को लेकर एक स्पेशल गाने की योजना बना रहे हैं।

क्या 'पेद्दी' में कैमियो करेंगी श्रुति हासन?

गल्ट के मुताबिक श्रुति हासन को 'पेद्दी' में एक स्पेशल कैमियो रोल के लिए साइन किया जा सकता है। उम्मीद है कि यह अभिनेत्री एक डांस नंबर में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग अभी बाकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस गाने की शूटिंग 26 अप्रैल, 2026 को हैदराबाद में शुरू हो सकती है। हालांकि, फिल्म निर्माताओं ने अभी तक श्रुति के इस फिल्म में शामिल होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

मृणाल ने किया मना

इससे पहले, ऐसी खबरें थीं कि इसी स्पेशल डांस नंबर के लिए मृणाल ठाकुर पर विचार किया जा रहा था। लेकिन, अब माना जा रहा है कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया है, जिससे अब श्रुति हासन के इस फिल्म में आने की संभावना बढ़ गई है।

'कांतारा' मिमिक्री विवाद में रणवीर सिंह ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी

'कांतारा: चैप्टर 1' मिमिक्री विवाद से जुड़े मामले में अभिनेता रणवीर सिंह ने आज कोर्ट में माफी मांगी। रणवीर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में संशोधित हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने रणवीर सिंह की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई। यह एफआईआर पिछले साल आयोजित कार्यक्रम में रणवीर द्वारा फिल्म के एक पात्र की मिमिक्री करने और एक मंदिर की देवी के संबंध में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद दर्ज हुई थी। रणवीर सिंह की ओर से एडवोकेट सज्जन पूवैय्या ने अदालत को बताया कि अभिनेता ने बिना शर्त माफी वाला नया हलफनामा दाखिल किया। उन्होंने यह भी कहा कि अभिनेता ने मंदिर जाकर श्रद्धा प्रकट करने का भी आश्वासन दिया।

मामला कानूनी नहीं आस्था से जुड़ा है

शिकायतकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था से जुड़ा है। इस पर अदालत ने कहा कि इसी कारण अब तक एफआईआर पर रोक नहीं लगाई गई। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि आदेश में यह दर्ज किया जाएगा कि अभिनेता चार सप्ताह के भीतर मंदिर जाएंगे। साथ ही अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह इस मामले में एक्टर को चेतावनी भी देगी।

हम धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं

वहीं रणवीर सिंह की ओर से कहा गया कि वह धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं। इसी कारण मामले के गुण-दोष पर बहस नहीं की जा रही है। मामले के अंत में अदालत ने कहा कि वह हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका का निपटारा करेगी। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि केवल प्रसिद्ध व्यक्ति होने के कारण कोई किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता और सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

पिता ने लॉन्च करने से किया इनकार, अपने दम पर बनाई अलग पहचान

हिंदी सिनेमा में कई ऐसे कलाकार हुए हैं, जिन्हें परिवार से फिल्मी माहौल तो मिला, लेकिन पहचान उन्हें मेहनत और संघर्ष से बनानी पड़ी। बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे होने के बावजूद उनके लिए फिल्मों में जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था। कहा जाता है कि डेविड धवन चाहते थे कि उनका बेटा अपने दम पर आगे बढ़े और खुद मेहनत करके पहचान बनाए। यही वजह थी कि उन्होंने वरुण को अपने बैनर से लॉन्च नहीं किया। आज वरुण धवन उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और लगातार काम के दम पर बॉलीवुड में अपनी खास जगह बनाई। 24 अप्रैल 1987 को मुंबई में जन्मे वरुण धवन फिल्मी माहौल में बड़े हुए। उनके पिता डेविड धवन हिंदी सिनेमा के बड़े निर्देशकों में गिने जाते हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में बनाई हैं। उनके बड़े भाई रोहित धवन भी निर्देशक हैं। घर में हमेशा बड़े कलाकारों का आना-जाना लगा रहता था। ऐसे माहौल में बड़े होने के कारण वरुण का झुकाव भी फिल्मों की तरफ हो गया। उनके पिता चाहते थे कि वह पहले पढ़ाई पूरी करें। वरुण ने मुंबई में पढ़ाई करने के बाद इंग्लैंड की नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई खत्म करने के बाद वरुण भारत लौट आए। उस समय हर किसी को लगता था कि डेविड धवन अपने बेटे को बड़े लेवल पर लॉन्च करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेविड धवन ने साफ कहा कि वरुण को खुद मेहनत करनी होगी। यही वजह रही कि वरुण ने फिल्मों में सीधे अभिनेता बनने के बजाय शुरुआत सहायक निर्देशक के तौर पर की। उन्होंने 'माई नेम इज खान' में करण जौहर के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने फिल्म बनाने की बारीकियां सीखीं और कैमरे के पीछे का काम समझा। इसके बाद, साल 2012 में करण जौहर ने वरुण को 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से लॉन्च किया। इस फिल्म में उनके साथ आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आए। फिल्म बड़ी हिट साबित हुई और वरुण रातोंरात युवाओं के पसंदीदा स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 'हम्प्टी शर्मा की दुल्हनियां', 'बदलापुर', 'एबीसीडी 2', 'जुड़वा 2', 'अक्टूबर' और 'सुई धागा' जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग-अलग तरह के किरदार निभाए। खास बात यह रही कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी ही नहीं, बल्कि गंभीर भूमिकाओं में भी अपनी अभिनय क्षमता साबित की।

रणवीर शौरी ने बताया करियर पर कैसा पड़ा 'बिग बॉस' का असर

अभिनेता रणवीर शौरी इन दिनों अपने नए प्रोजेक्ट 'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में अमर उजाला से खास बातचीत में उन्होंने फिल्म, अपने किरदार, करियर, इंडस्ट्री और अपनी सोच पर खुलकर बात की। बातचीत के दौरान, अभिनेता ने बिग बॉस के अपने अनुभव पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इस शो के बाद उनके करियर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन्हे जबर्दस्त पहचान जरूर मिली।

'एवरीबडी लव्स सोहराब हांडा' से जुड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या रही?

बहुत सीधा सा जवाब है। एक शब्द में कहूं तो राजत कपूर। और अगर एक नाम और जोड़ना हो तो विनय पाठक। कई बार स्क्रिप्ट से पहले आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं, जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं। मुझे पता था कि इन लोगों के साथ कुछ दिलचस्प ही बनेगा। इसलिए यह फैसला बहुत आसान था।

अपने किरदार माधवन के बारे में बताइए

माधवन एक दोस्त है उस ग्रुप का, जिसमें चार पांच कपल्स हैं और सब एक साथ एक एनिवर्सरी हॉलिडे के लिए मिलते हैं। वह दर्शनशास्त्र का प्रोफेसर है। लेक्चर देता है, घूमता है और जिंदगी को बहुत इंटेलेक्चुअल नजरिए से देखता है। उसे लगता है कि उसे इंसानियत की पूरी समझ है। वह बहुत पॉलिश्ड और इवॉल्व्ड इंसान है और सच कहूं तो मुझसे काफी अलग है। लेकिन यही तो दिलचस्प होता है कि आप किसी ऐसे इंसान को निभा रहे होते हैं, जो खुद को बहुत सही समझता है।

क्या आपने किरदार में अपनी तरफ से कुछ जोड़ा

हां, और यह बहुत जरूरी भी होता है। अच्छे डायरेक्टर आपको थोड़ा स्पेस देते हैं। रजत कपूर भी वैसे ही हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें क्या चाहिए, लेकिन वह आपको अपनी तरफ से कुछ जोड़ने देते हैं। इस फिल्म में भी कुछ जगह मैंने इम्प्रोवाइज किया और अच्छी बात यह रही कि उन्होंने उसे रखा। एक एक्टर के लिए यह बहुत अच्छा लगता है।

अब आप किस तरह के रोल करना चाहते हैं...

अब मैं चाहता हूं कि मुझे ज्यादा लीड रोल मिलें। जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं खुद कहता था कि लीड रोल जरूरी नहीं होते, अच्छे रोल होने चाहिए, रोल छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता। उस समय यह भी सोचता था कि अगर कैमियो भी है लेकिन क्रिएटिव है, दिलचस्प है, तो वह भी करना चाहिए। मेरे लिए तब काम की क्वालिटी और उसमें क्रिएटिव संतोष ज्यादा मायने रखता था...न कि स्क्रीन टाइम या पोजिशन। लेकिन अब लगभग दस साल हो गए हैं जब मुझे लीड रोल नहीं मिले हैं। तो अब नैचुरली लगता है कि मिलने चाहिए। एक समय के बाद आपको यह महसूस होता है कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं.. और शायद आपको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे। इसलिए अब चाहत है कि ऐसे रोल आएं जहां मैं कहानी को लीड कर सकूं और अपने आपको उस तरह एक्सप्लोर कर सकूं।

इसके पीछे क्या वजह देखते हैं?

इसमें मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। मैं न प्रोड्यूसर हूं, न डायरेक्टर। वही लोग तय करते हैं कि किसे कौन सा रोल मिलेगा। हमारे यहां अक्सर आपको उसी तरह के रोल मिलते हैं, जिसमें आप पहले सफल रहे हैं। अगर आपने सपोर्टिंग रोल में ज्यादा सफल फिल्में की हैं तो आपको वही रोल बार-बार मिलते हैं। शायद यही वजह है कि मुझे अब लीड रोल के ऑफर कम मिलते हैं।

नई पीढ़ी के एक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे

नई पीढ़ी के एक्टर्स के लिए मैं यही कहूंगा कि मौके सिर्फ टैलेंट और एबिलिटी के आधार पर मिलते हैं। जेनरेशन के आधार पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नए एक्टर्स के लिए जरूरी है कि वे अपने काम पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स पर काम करें और लगातार बेहतर बनने की कोशिश करें। मौके देर से मिलें या जल्दी, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वह दिखती जरूर है।

आईपीएल इतिहास में तीसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने वैभव सूर्यवंशी

● 16 बॉल पर बनाए 43 रन, पारी में 5 छक्के, 3 चौके ● 9 मैचों में 400 रन, ऑरेंज कैप के लिए टॉप पर

चंडीगढ़ (एजेंसी)। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के बीच मैच खेला गया। मुकाबला न्यू चंडीगढ़ स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेला गया था। पंजाब किंग्स ने 223 रन का टारगेट दिया था, जिसे राजस्थान ने 4 गेंद रहते हासिल कर लिया और 6 विकेट से जीत हासिल कर लिया।

जवाबी पारी के दौरान वैभव ने पहले ओवर में बैक टू बैक 3 बाउंड्री जड़े। अर्शदीप की चौथी बॉल पर उन्होंने डीप बैकवर्ड

स्क्वैयर में छक्का लगाया। इसके बाद लगातार दो चौके लगाए। तीसरे ओवर में वैभव अर्शदीप की गेंद पर आउट हो गए। उन्होंने 16 गेंद पर 43 रन बनाए। उनकी पारी में 5 छक्के और 3 चौके शामिल हैं। इस इनिंग के साथ ही वे ऑरेंज कैप के लिए टॉप पर आ गए हैं। उन्होंने 9 मैचों में 400 रन बनाए।

15 साल के वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज 50 छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने मात्र 36 गेंदों में अपना दूसरा शतक जड़ दिया। उन्होंने 36 गेंदों में 103 रन बनाए। इस धमाकेदार पारी में उन्होंने 12 छक्के और 5 चौके लगाए।

इसी के साथ वे आईपीएल के इतिहास में तीसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। गेल ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 30 गेंद पर शतक लगाया था। इसके अलावा वैभव आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय भी बन गए हैं।

वैभव एक आईपीएल इनिंग में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय- वैभव ने अपनी शतकीय पारी में 12 छक्के लगाए। वे आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड मुरली विजय के नाम था, जिन्होंने 2010 में ××के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे। वैभव ने भी 2025 में जीटी के खिलाफ 11 छक्के लगाए थे।

दिग्गज भारतीय गोल्फर विजय कुमार का निधन

नईदिल्ली (एजेंसी)। पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन और भारतीय गोल्फ के दिग्गज विजय कुमार का 57 साल की उम्र में निधन हो गया है. प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने बुधवार को सोशल मीडिया के जरिए इस खबर की पुष्टि की और चार बार के 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' विजेता के निधन पर शोक जताया। पीजीटीआई ने कहा, 'हम श्री विजय कुमार के निधन से बहुत दुखी हैं. वे भारतीय गोल्फ के सच्चे दिग्गज और पूर्व इंडियन ओपन चैंपियन थे. विजय की सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 में दिल्ली गोल्फ क्लब में इंडियन ओपन जीतना थी. विजय ने

स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में खेले गए 1999 के अल्फ्रेड डनहिल कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था।' पीजीटीआई नें अपने बयान में आगे कहा, 'उनकी असाधारण उपलब्धियां, जो उनकी प्रतिभा, सालों की कड़ी मेहनत, लगन और खेल के प्रति जुनून का नतीजा थीं, उन्होंने भारतीय गोल्फ पर एक गहरा असर छोड़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. अपनी उपलब्धियों के अलावा, हमेशा मुस्कुराने वाले विजय को उनके सकारात्मक रवैये, खुशमिजाज स्वभाव, बेहतरीन हास्य-बोध और खेल भावना के लिए याद किया जाएगा. पीजीटीआई के सभी पेशेवरों और अधिकारियों की ओर से, हम विजय कुमार के परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं।'

विजय कुमार की उपलब्धियां- 29 दिसंबर, 1968 को लखनऊ में जन्मे विजय 1988 में पेशेवर खिलाड़ी बने. उन्होंने 1990 के दशक के मध्य से अगले दशक की शुरुआत तक भारतीय घरेलू गोल्फ पर अपना दबदबा बनाए रखा. उनका शानदार करियर कई खिताबों से भरा रहा. वे भारतीय पेशेवर सर्किट पर चार बार (1995-96, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000) 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन बने।

चीन से 0-5 से हारकर

भारत उबेर कप से बाहर

अब थॉमस कप पर निगाहें

होर्सेंस (डेनमार्क)(एजेंसी)। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मजबूत स्थिति में होने का फायदा नहीं उठा पाई जबकि अन्य खिलाड़ियों ने भी महत्वपूर्ण मौकों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया जिससे भारत उबेर कप में चीन से 0-5 से हारकर इस बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गया।

भारतीय महिला टीम ने मेजबान डेनमार्क से 2-3 की हार के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उसने यूक्रेन पर 4-1 से जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की अपनी उम्मीद बनाए रखी थी।

उबेर कप में 16 बार के चैंपियन चीन से भारत को पिछले तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. सिंधु ने भारत की तरफ से शुरुआत की जबकि उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की जगह अन्य दो एकल मुकाबलों के लिए ईशरानी बरुआ और देविका सिहाग को टीम में शामिल किया गया।

सिंधु निर्णायक सेट में 18-12 से आगे थी लेकिन आखिर में वह विश्व की दूसरे नंबर की खिलाड़ी वांग झियी से 16-21, 21-19, 19-21 से हार गईं. इससे चीन ने सोमवार को ग्रुप ए के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली।

सिंधु ने बाद में कहा, 'यह एक अच्छा मैच था. अगर मैं जीत हासिल करने में सफल रहती तो और भी अच्छा होता. मुझे मौके मिले, लेकिन ऐसा नहीं था कि कुछ अंक आसान थे. प्रत्येक अंक के लिए कड़ा मुकाबला हुआ. हम वास्तव में प्रत्येक अंक के लिए बहुत संघर्ष कर रहे थे।' प्रिया कोंजेंगबम और श्रुति मिश्रा पहले युगल मुकाबले में विश्व की नंबर एक जोड़ी लियू शेंग शू और टैन निंग के सामने नहीं टिक पाई और 11-21, 8-21 से हार गईं। इशारानी बरुआ ने तोक्यो ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई के सामने कड़ी चुनौती पेश की लेकिन विश्व में 38वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी ने पहले गेम में 20-19 पर एक आसान मौका गंवा दिया. विश्व में चौथे नंबर की खिलाड़ी युफेई ने यह मैच 44 मिनट में 22-20, 21-13 से जीतकर चीन को 3-0 की अजेय बढ़त दिला दी।

भारत की निगाहें अब पुरुष टीम पर

भारत की निगाहें अब पुरुष टीम पर टिकी हैं जो थॉमस कप में ग्रुप ए में अपने आखिरी मुकाबले में चीन का सामना करेगा. 2022 की चैंपियन भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पर 5-0 की शानदार जीत से पहले ही क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत और चीन इस ग्रुप में शीर्ष पर हैं. भारत ने कनाडा पर 4-1 से जीत के साथ शुरुआत की थी. चीन ने अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराया था. उसने सोमवार को कनाडा को 4-1 से पराजित किया। भारत और चीन अब बुधवार को अपने अंतिम ग्रुप मुकाबले में एक दूसरे का सामना करेंगे, जिससे ग्रुप में शीर्ष स्थान पर रहने वाली टीम का फैसला होगा।

पंजाब 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा बार हारा

राजस्थान का आईपीएल में तीसरा सबसे बड़ा रनचेज; फरेरा का 105 मीटर लंबा सिक्स

चंडीगढ़ (एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के 40वें मैच में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ पंजाब आईपीएल में 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा बार हारने वाली टीम बन गई। राजस्थान ने अपना तीसरा सबसे बड़ा रनचेज किया। डोनोवन फरेरा ने 105 मीटर लंबा सिक्स लगाया।

चेज करते हुए राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी जीत- राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 223 रन का टारगेट चेज किया। यह आईपीएल में चेज करते हुए टीम की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। राजस्थान ने 2020 में शारजाह में पंजाब के खिलाफ ही 224 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। दूसरे नंबर पर 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मिली जीत है।

200+ रन डिफेंड करते हुए पंजाब सबसे ज्यादा हारा- आईपीएल में 200 या उससे ज्यादा रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा हार झेलने का रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम है, टीम को ऐसे मैचों में 8 बार हार मिली है। दूसरे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है, जिसने 7 बार 200+ स्कोर डिफेंड करते हुए मैच गंवाया है।

● **प्रभसिमरन पंजाब के लिए तीसरे सबसे ज्यादा अर्धशतक वाले बैटर-** प्रभसिमरन सिंह पंजाब के लिए सबसे ज्यादा फिफ्टी लगाने के मामले में तीसरे स्थान पर हैं। उनके नाम 12 अर्धशतक हैं। इस सूची में पहले स्थान पर केएल राहुल (25) और दूसरे स्थान पर शॉन मार्श (21) हैं।

● **आर्चर ने रबाडा की बराबरी की-** आईपीएल 2026 में पावरप्ले के दौरान सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जोफा आर्चर और कगिसो रबाडा संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। दोनों के नाम 9-9 विकेट हैं। दूसरे स्थान पर भुवनेश्वर कुमार (7 विकेट) हैं, जबकि तीसरे स्थान पर मोहम्मद शमी (6 विकेट) मौजूद हैं।

● **अर्शदीप ने पंजाब के लिए दूसरा सबसे महंगा स्पेल फेंका-** अर्शदीप सिंह पंजाब के लिए एक मैच में सबसे ज्यादा रन देने वाले दूसरे बॉल बन गए। उन्होंने 4 ओवर के स्पेल में 68 रन देकर एक विकेट लिया।

पहले नंबर पर जेवियर बार्टलेट हैं, जिन्होंने इसी सीजन दिल्ली के खिलाफ 1/69 का स्पेल स्पेल फेंका था।

विनेश फोगाट की 20 महीने बाद रेसलिंग में वापसी

● गोंडा रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, डब्ल्यूएफआई से विवाद के बाद 57केजी में उतरेंगी

नईदिल्ली (एजेंसी)। विनेश फोगाट 20 महीने बाद किसी रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश की नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। विनेश ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि विनेश ने पहले आरोप लगाया था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्हें टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से रोक रहा है। विनेश ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'आज सुबह मेरा रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। कल लिंक बंद होने की वजह से मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाई थी। सबके सपोर्ट के लिए शुक्रिया।

रजिस्ट्रेशन में देरी पर डब्ल्यूएफआई ने सफाई दी- विनेश के रजिस्ट्रेशन में हुई देरी पर डब्ल्यूएफआई ने बताया कि पोर्टल में तकनीकी दिक्कत आई थी। इसकी वजह से सिर्फ विनेश नहीं, बल्कि कई पहलवानों का रजिस्ट्रेशन अटका हुआ था। बाद में लिंक खुलने पर एंट्री सबमिट हुई है। फेडरेशन ने कहा कि विनेश का रजिस्ट्रेशन सोमवार रात 10:29 बजे पूरा हो गया था, जबकि विनेश ने अपनी पोस्ट में मंगलवार सुबह इसका जिक्र किया है।

पेरिस ओलिंपिक के बाद संन्यास लिया था- पेरिस ओलिंपिक 2024 में विनेश ने 50 किलोग्राम फ्री-स्टाइल कुश्ती में हिस्सा लिया था। उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में

जगह बना ली थी, लेकिन मुकाबले से पहले उनका वजन लगभग 100 ग्राम ज्यादा पाया गया।

इसके बाद ओलिंपिक नियमों के तहत उन्हें टूर्नामेंट से डिसक्वालिफाई कर दिया गया। इससे दुखी होकर विनेश ने 8 अगस्त को संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि दिसंबर 2024 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट वापस ले लिया।विनेश को फाइनल से पहले ओवरवेट की वजह से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था।

● भारतीय बैटर्स विदेशियों पर भारी, कुल रन के 69 प्रतिशत इनके नाम, स्ट्राइक रेट में अव्वल

आईपीएल के 19वें सीजन में भारतीय बल्लेबाजों का रिकॉर्ड योगदान

नईदिल्ली (एजेंसी)। आईपीएल 2026 में पूरी तरह भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा दिख रहा है। सीजन के शुरुआती 38 मैचों में कुल 13 हजार 100 रन बने हैं। इनमें से भारतीय बल्लेबाजों ने 9066 रन ठोके हैं, जो कि कुल रनों का 69.21त्न है। यह किसी एक सीजन के शुरुआती 38 मैचों के बाद भारतीय बल्लेबाजों के योगदान का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल इस स्टेज तक 12,858 रन बने थे, जिसमें भारतीय बैटर्स ने 66.25 प्रतिशत का योगदान दिया था।

आईपीएल के शुरुआती वर्षों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत के आसपास रहता था

और 2009 में तो यह 47.51 प्रतिशत तक गिर गया था। लेकिन इस साल भारतीय बल्लेबाजों ने रनों का जो अंबार लगाया है, उसने विदेशी बल्लेबाजों की चमक फीकी कर दी है।

विदेशी बल्लेबाजों ने इस सीजन 30.79 प्रतिशत रन (4034) बनाए हैं, जो भारतीय बैटर्स का आधा भी नहीं है।स्ट्राइक रेट में भी भारतीय बैटर्स ने विदेशियों को पीछे छोड़ दिया है। इस सीजन बने कुल रनों में स्ट्राइक रेट 154.17 रहा है।इनमें भारतीय बैटर्स के 9066 रन 158.86 की स्ट्राइक रेट से आए हैं, जबकि विदेशियों ने अपना योगदान 144.59 के स्ट्राइक रेट से दिया है।

विदेशी दिग्गजों का फ्लॉप शो

एक तरफ भारतीय बल्लेबाज और युवा सितारे तूफानी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया भर की टी20 लीग्स में खेलने वाले बड़े विदेशी नाम बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं।

हेड और एडेन मार्करम जैसे दिग्गजों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है, लेकिन वे भी 8 पारियों में 200 रन का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 से कम रहा है।

श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष शम्मी सिल्वा का इस्तीफा

● पूरी कार्यकारिणी ने भी पद छोड़ा, पूर्व क्रिकेटर रोशन महानमा को अंतरिम कमेटी में जगह मिल सकती है

कोलंबो (एजेंसी)। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) में लंबे विवाद और राजनीतिक खींचतान के बीच बुधवार को अध्यक्ष शम्मी सिल्वा ने इस्तीफा दिया। उनके साथ पूरी कार्यकारी समिति ने भी सामूहिक इस्तीफा सौंपा। यह फैसला अनुरा कुमारा दिसानायके से बातचीत के बाद लिया गया। बोर्ड पर वित्तीय अनियमितताओं और मिसमैनेजमेंट के आरोप थे, जिससे उन पर पद छोड़ने का दबाव था।

पूर्व सांसद संभाल सकते हैं कमान, महानमा और सिदथ वेट्टिमुनी को भी जिम्मेदारी संभव- रिपोर्ट के मुताबिक सरकार बोर्ड के कामकाज के लिए अंतरिम कमेटी बनाने की तैयारी में है। इसकी अध्यक्षता पूर्व सांसद एरन विक्रमरत्ने कर सकते हैं। रोशन महानमा और सिदथ वेट्टिमुनी को भी बड़ी भूमिका मिल सकती है।सरकार का उद्देश्य क्रिकेट प्रशासन में तेजी से सुधार करना है, हालांकि आधिकारिक घोषणा बाकी है।

7 साल का कार्यकाल और विवाद- शम्मी सिल्वा फरवरी 2019 में पहली बार अध्यक्ष बने थे। 7 साल में वे

चार बार चुने गए, तीन बार निर्विरोध। उनके कार्यकाल में महिला और पुरुष टीमों ने एशिया कप जीता, लेकिन पुरुष टीम की रैंकिंग गिरी।टीम 2023 वनडे वर्ल्ड कप में 9वें नंबर पर रही और 2026 टी-20 वर्ल्ड कप में भी प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसी महीने गैरी कर्स्टन को हेड कोच बनाने के बावजूद नेतृत्व बदलने की मांग जारी रही

आईसीसी के बैन का खतरा- सरकारी दखल पर कड़ा रुख- इस बदलाव में सबसे बड़ी बाधा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी है।आर्टिकल 2.4 (डी) के मुताबिक, बोर्ड में सरकारी हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। नवंबर 2023 में खेल मंत्री द्वारा बोर्ड बर्खास्त करने पर आईसीसी ने श्रीलंका की सदस्यता निलंबित कर दी थी और अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी छीन ली थी।

2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने श्रीलंका क्रिकेट में बनाए गए सिदथ वेट्टिमुनी की अगुवाई वाले कमेटी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

2015 में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने श्रीलंका क्रिकेट में बनाए गए सिदथ वेट्टिमुनी की अगुवाई वाले कमेटी को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।

सबसे अमीर खेल संस्था, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप

शम्मी सिल्वा बोर्ड को देश की सबसे अमीर खेल संस्था बताते थे, जिसने आर्थिक संकट में भी रिकॉर्ड कमाई की। इसके बावजूद बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 2023 के अंत में ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त करने की कोशिश हुई, लेकिन वे कोर्ट से स्टे ले आए थे। अब देखना होगा कि नई अंतरिम कमेटी आईसीसी के नियमों और जनता की उम्मीदों में कैसे तालमेल बिठाती है।

राजस्थान के कप्तान रियान पराग ई-सिगरेट पीते दिखे

ड्रेसिंग रूम का वीडियो वायरल, देश में बैन, बीसीसीआई कार्रवाई कर सकता है

मुल्लांपुर (एजेंसी)। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 में एक बार फिर विवादों घिर गई है. इस बार टीम अपने कप्तान रियान पराग के गलत कारणों से सुर्खियों में आई है. यह दाएं हाथ का बल्लेबाज पहले से ही अपने खराब प्रदर्शन के कारण सवालों के घेरे में है, और अब एक और विवाद ने उन पर सबका ध्यान खींच लिया है. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक मैच के दौरान लाइव प्रसारण के एक क्लिप में रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। यह घटना न्यू-चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स के 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान 16वें ओवर में कैमरे में कैद हुई.

संक्षिप्त समाचार

दिल्ली-एनसीआर में देर रात बारिश और तेज हवाओं से मौसम बदला

नई दिल्ली, एजेंसी। पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे दिल्ली समेत एनसीआर के निवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। रात से ही दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में चल रही तेज ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने ने पारे को नीचे गिराना शुरू कर दिया है, जिससे लोगों को झुलसाती गर्मी से काफी हद तक निजात मिली है। मौसम का मिजाज बदलते ही साइबर सिटी गुग्राम में तेज बारिश शुरु हो गई जिससे लोगों को गर्मी से मिली। कुछ ऐसा ही नजारा ग्रेटर नोएडा और हापुड़ में भी देखने को मिला जहां लोगों ने राहत की सांस

ली। फरीदाबाद में भी सुबह से मौसम बदला रहा और हल्की बूंदाबांदी से लोगों को आराम मिला जेवर में सुबह से ही मौसम में बदलाव दिखा, तेज हवा और बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया। हल्की बूंदाबांदी से धूल भरी आंधी से मिली लोगों को राहत मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो-तीन दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ आंधी में वर्षा की संभावना है। रात से ही 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, आज दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की भी होगी। इसके चलते अधिकतम तापमान, जो पिछले दिनों 40-42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वह गिरकर 36-38 डिग्री सेल्सियस तक आने की उम्मीद है।

भाजपा में शामिल हुईं स्वाति मालीवाल ने बोला तीखा हमला

नई दिल्ली, एजेंसी। आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली सांसद स्वाति मालीवाल ने

आप की कार्यप्रणाली की आलोचना की। कहा कि आप झूठ व फरेब का उदाहरण बन गई है। अरविंद केजरीवाल को राजघाट पर बैठकर चिंतन करना चाहिए कि आखिर वह करना क्या चाहते हैं? न्याय व्यवस्था और प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना और निजी टिप्पणी कर वह किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप नेताओं की गलत राजनीति से त्रस्त होकर उन्हें आप छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। वह वर्ष 2006 में अरविंद केजरीवाल की संस्था से जुड़कर सामाजिक संघर्ष का रास्ता चुना था। झुग्गियों, गांवों व आपदा प्रभावित क्षेत्रों में रहकर काम किया और आरटीआइ की लड़ाई लड़ी। महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, अनशन किया, लाठियां भी खाई। पार्टी से लेकर दिल्ली महिला आयोग में की प्रत्येक जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाई। मेरे वर्षों के संघर्ष को देखकर पार्टी ने राज्यसभा भेजा लेकिन कुछ ही महीनों बाद केजरीवाल के निजी सहायक ने उनके साथ मारपीट की। उन्हें बदनाम किया गया और संसद में बोलने के लिए पार्टी ने मौका नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अमित शाह के रूप में देश को एक दृढ़ और निर्णायक गृह मंत्री मिले हैं।

गंगा एक्सप्रेसवे पर रनवे सा एहसास: स्मार्ट कंट्रोल रूम

मेरठ से प्रयागराज सिर्फ 6 घंटे में पहुंचें

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली-नोएडा से प्रयागराज की दूरी को कम करने वाले बहुप्रतिक्षित गंगा एक्सप्रेसवे को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को सौंप देंगे। 594 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाली गंगा एक्सप्रेस की अनुमानित लागत करीब 36,402 करोड़ रुपये बताई जा रही है। स्मार्ट कंट्रोल रूम वाली सुविधा के साथ इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग के दौरान नींद की झपकी आने पर जगाने वाले फीचर का भी ध्यान रखा गया है।

गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत कई जिलों से होकर गुजर रहा है। इससे इन संबंधित जिलों के लोगों को आवाजाही में आसानी तो होगी साथ ही रोजगार के भी नए अवसरों की राह खुलेगी। इस एक्सप्रेसवे पर देश में पहली बार ट्रॉमा सेंटर की सुविधा भी मिलेगी।

दावा किया जा रहा है कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी और समय दोनों को आधा कर देगा।

जहां पहले यही दूरी तय करने में 10 से 12 घंटे लगते थे। वहीं, अब यह लंबा सफर महज 5 से 6 घंटे में पूरा होगा। इस एक्सप्रेसवे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे एवं नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जाने वाले मार्ग को जोड़ रहा है। साथ ही, हरिद्वार की कनेक्टिविटी को भी आसान बनाएगा। यही कारण है कि इसकी चौड़ाई भविष्य में बढ़ाकर 8 लेन भी की जा सकती है। आशा जताई जा रही है कि इससे उद्योग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। ऐसे में आने वाले समय में यह आर्थिक ढांचे की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे को आधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। इसमें स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, आपातकालीन सेवाएं, कैमरा निगरानी और एयरस्ट्रिप जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

औद्योगिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ यात्रियों की दूरी को ही कम नहीं करेगा यह रोजगार के अनेक अवसर भी मुहैया कराएगा। इसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इसके किनारे 12 औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर विकसित करने की योजना है, जिनमें लगभग 47,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं।

दिल्ली में बिना हेलमेट की सवारी बन रही मौत का सबब, 15 अप्रैल तक 188 बाइकर्स की मौत

नई दिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, जो अब गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। लोग अपनी सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए बेखौफ सड़कों पर मोटरसाइकिल और स्कूटी दौड़ा रहे हैं। हालात यह हैं कि कई वाहन चालक न सिर्फ बिना हेलमेट सफर कर रहे हैं, बल्कि चलते वाहन पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए भी नजर आते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस वर्ष 15 अप्रैल तक सड़क हादसों में 188 दोपहिया वाहन चालकों की मौत हो चुकी है। चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में चालकों ने हेलमेट नहीं पहना था। सिर्फ चालक ही नहीं, बल्कि अन्य लोग भी इस लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। इसी अवधि में लापरवाही से दोपहिया वाहन चलाने वालों की चपेट में आने से 62 लोगों की जान चली गई। इससे साफ है कि बिना हेलमेट और असावधानी से वाहन चलाना न सिर्फ चालक के लिए, बल्कि सड़क पर मौजूद अन्य लोगों के

लिए भी खतरनाक साबित हो रहा है।

यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, दिल्ली में बिना हेलमेट वाहन चलाने के बढ़ते चलन को देखते हुए यातायात पुलिस ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर 15 अप्रैल तक 4.24 लाख चालान काटे जा चुके हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए आगे भी सख्ती जारी रहेगी। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि केवल चालान काटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। जब तक लोग खुद अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक हादसों में कमी लाना मुश्किल होगा।

सड़क सुरक्षा अभियान का भी नहीं दिख रहा असर

यातायात पुलिस द्वारा स्कूल, कॉलेजों, मॉल व अन्य सार्वजनिक जगहों पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी लोगों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। यातायात पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता लाना है, जिससे सड़क हादसों में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सके।

दिल्ली विधानसभा में गूंजा बेसहारा गायों का मुद्दा, सड़क जाम और हादसों पर विधायकों की सख्त कार्रवाई की मांग

नई दिल्ली, एजेंसी। सड़कों पर बेसहारा गायों के जमावड़े से जनता ही नहीं, विधायक भी परेशान हैं। मंगलवार को विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान विशेष उल्लेख (नियम संख्या 280) के तहत अनेक विधायकों ने यह मुद्दा उठाया। विधायक श्याम शर्मा, कुलवंत राणा एवं हरीश खुराना ने इस पर प्रमुखता से अपनी बात रखी। उनका कहना था कि सड़कों पर जहां तहां बेसहारा गायों का झुंड देखने को मिल जाता है। दिन में यह झुंड ट्रैफिक जाम की वजह बनता है और रात के अंधेरे में हादसों का सबब। इन विधायकों का कहना था कि उनके कार्यालय में भी हर रोज इस संदर्भ में शिकायतें आती रहती हैं। इन सभी विधायकों की ओर से इस समस्या का गंभीरता से कोई निदान निकालने की मांग भी की गई। मांडल टाउन से विधायक अशोक गोयल ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नशीले पदार्थों की उपलब्धता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि खुलेआम नशे का कारोबार बढ़ रहा है और पुलिस भी इस पर लगाम नहीं लगा पा रही। ग्रेटर कैलाश से विधायक शिखा राय ने खिड़की एक्सटेंशन और प्रेस एनक्लेव के बीच ट्रैफिक जाम का मुद्दा उठाया। उन्होंने यहां से आउटर रिंग रोड तक लिंक रोड बनाने की मांग रखी। विधायक संजय गोयल ने फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग रखी ताकि लंबित मामले निपटाए जा सकें। उनका कहना था कि न्याय देरी से मिलना नहीं मिलने के बराबर है। इसलिए इस दिशा में तेजी से काम होना चाहिए। विधायक कुलदीप सोलंकी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट का मुद्दा उठाया और इसे लेकर सख्ती करने की मांग उठाई। विधायक गजेंद्र दराल ने अपने इलाके में पेयजल किल्लत की समस्या उठाई। उन्होंने मांग की कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल्द से जल्द जलापूर्ति की कमी दूर की जाए और पानी की लाइनें भी बदली जाएं। डा अनिल गोयल ने पूर्वी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था का मुद्दा रखा। साथ ही पूरे क्षेत्र का एक सर्वे करवाकर यहां की व्यवस्था सुधारने को यथावश्यक कदम उठाने की मांग की।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अयोग्य घोषित उम्मीदवार को जेईई एडवांस्ड-2026 में बैठने की दी इजाजत

नई दिल्ली, एजेंसी। आइआइटी में प्रवेश स्वीकार करने के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जेईई एडवांस्ड-2026 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता को परीक्षा के लिए पंजीकरण करने की अनुमति दी और आयोजन अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर उसे टिकट जारी करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि आप इस संस्थान का महत्व नहीं समझते और आइआइटी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है। कक्षा एक से ही बच्चों की यह महत्वाकांक्षा होती है कि उन्हें आइआइटी में सीट मिले। पीठ ने कहा कि यह बच्चों का सपना होता है और अदालत इसे अनदेखा नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि उम्मीदवार कल किसी अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लेगा और यह प्रतिभा पलायन होगा। अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 17 मई 2026 को होने वाली प्रस्तावित परीक्षा, जेईई एडवांस्ड 2026 में बैठने के लिए अब से एक सप्ताह के भीतर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार टिकट जारी कर दिया जाएगा। पीठ ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, तो उसकी याचिका निष्फल हो जाएगी और यदि वह मुकदमा हार जाता है, तो उसकी परीक्षा रद घोषित की जा सकती है। उम्मीदवार की तरफ से पेश हुई अधिवक्ता तन्वी दुबे ने कहा कि उनके मुवक्किल जेईई (मेन्स) 2025 सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की और जेईई (एडवांस्ड) 2025 के लिए अर्हता प्राप्त की, लेकिन किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया। अदालत को बताया गया कि काउंसलिंग के छठे दौर में, आइआइटी गुवाहाटी में एक सीट को स्वीकृत मान लिया गया और जुलाई 2025 में उसकी सहमति के बिना उसे आवंटित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि यद्यपि उसने आइआइटी गुवाहाटी में शामिल होने की अनिच्छा तुरंत बता दी थी, फिर भी आयोजन समिति ने अधिकारियों ने उन्हें इस वर्ष आइआइटी प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोक दिया क्योंकि वे जेईई एडवांस्ड 2026 के मानदंड ए-पांच के अनुसार पात्र नहीं है।

गृह विभाग की फंडिंग खत्म होने की कगार पर, टीएसए कर्मचारियों के वेतन पर भी खतरा; हवाई सुरक्षा पर असर की आशंका

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में एक बार फिर सरकारी फंडिंग को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है। व्हाइट हाउस ने कांग्रेस को चेतावनी दी है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और उससे जुड़े अहम विभागों के पास कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए फंड जल्द ही खत्म हो सकता है। इससे देश की हवाई सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रबंधन और बजट कार्यालय ने सांसदों को एक मेमो भेजकर बताया है कि परिवहन सुरक्षा प्रशासन और अन्य कर्मचारियों की सैलरी के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कार्यकारी आदेश से दिया गया पैसा मई तक खत्म हो जाएगा। इससे एयरपोर्ट संचालन और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। सरकार का कहना है कि अगर जल्द ही बजट पारित नहीं किया गया तो सुरक्षा कर्मियों के वेतन और संचालन दोनों पर संकट गहरा जाएगा। मेमो में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा को सीनेट द्वारा पिछले हफ्ते पास किए गए बजट प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देनी चाहिए, ताकि विभाग को पूरा फंड मिल सके। मेमो के अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी विभाग जल्द ही जरूरी फंड से खत्म हो जाएगा, जिससे जरूरी कर्मचारियों और कामकाज पर खतरा पैदा हो सकता है। अमेरिकी

संसद में बजट को लेकर राजनीतिक खींचतान लगातार जारी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच सहमति न बनने के कारण कई महत्वपूर्ण विभागों की फंडिंग अटक गई है। इस बीच, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी आंतरिक विवाद के चलते बजट प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, जिससे पूरा सिस्टम लगभग ठप जैसा हो गया है। ट्रंप प्रशासन का यह दबाव हाउस स्पीकर माइक जॉनसन के लिए मददगार साबित हो सकता है। उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास बहुत कम बहुमत है और पार्टी के अंदर कई मुद्दों पर मतभेद चल रहे हैं, जिनमें होमलैंड सिक्योरिटी की फंडिंग भी शामिल है। इसी वजह से सदन का कामकाज लगभग ठप पड़ा हुआ है। अब उम्मीद है कि प्रतिनिधि सभा बुधवार को सीनेट द्वारा पास किए गए बजट प्रस्ताव पर वोट करेगी। यह प्रस्ताव एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करेगा जिससे विभाग को पूरी फंडिंग मिल सकेगी। प्रशासन ने रिपब्लिकन सांसदों को चेतावनी दी है कि अगर वे इस प्रस्ताव में बदलाव करते हैं तो बिल पास होने में देरी हो सकती है। मेमो में यह भी कहा गया है कि ष्ठ॥स् के लिए फंडिंग बहाल करना अब पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। इसका कारण हाल की एक घटना है, जब बंदूक और चाकू लेकर एक व्यक्ति व्हाइट हाउस संवाददाता डिनर में घुसने की कोशिश कर रहा था।

ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर की संसद में बड़ी जीत

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने संसद में एक महत्वपूर्ण वोट जीत लिया है। सांसदों ने उनके खिलाफ नैतिकता जांच शुरू करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव के विरोध में 335 और पक्ष में 223 वोट पड़े। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि स्टार्मर ने पीटर मैंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत नियुक्त करने के मामले में संसद को गुमराह किया है। मैंडेलसन के संबंध यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से रहे हैं। इस विवाद के कारण स्टार्मर पिछले कई महीनों से भारी दबाव में थे। वोटिंग से पहले स्टार्मर ने अपनी लेबर पार्टी के सांसदों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने इस प्रस्ताव को विरोधियों का राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनावों से ठीक पहले उन्हें काम करने से रोकने के लिए यह सब किया जा रहा है। दूसरी ओर, विपक्षी नेता केमी बेडनोच ने तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो सांसद इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट दे रहे हैं, उन्हें अपने विवेक की जांच करनी चाहिए। इस बीच, स्टार्मर के पूर्व मुख्य सलाहकार मॉर्गन मैकस्वीनी ने भी इस नियुक्ति को एक गंभीर गलती बताया और इसकी जिम्मेदारी ली। भले ही स्टार्मर ने यह वोट जीत लिया है।

पूर्व राष्ट्रपति येओल की पत्नी को चार साल की कैद, भ्रष्टाचार के मामले में ठहराई गई दोषी

सियोल, एजेंसी। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल की पत्नी किम किओन ही को भ्रष्टाचार के एक और मामले में चार साल की सजा सुनाई है। दो महीने पहले उनके पति को देश में जबरन मार्शल लॉ लगाने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

जनवरी में एक जिला अदालत ने पूर्व प्रथम महिला किम को 20 महीने की सजा सुनाई थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने राजनीतिक लाभ देने के वादे के बदले यूनिफिकेशन चर्च से उपहार लिए थे। इन उपहारों में एक ग्राफ कंपनी का हीरे का हार और एक चैनल बैग शामिल था। हालांकि, उसी समय उन्हें एक शेयर कीमत में हेरफेर के मामले में बरी कर दिया गया था, जो मामला उनके प्रथम महिला बनने से पहले का था।

सियोल हाईकोर्ट ने सजा बढ़ाकर चार साल की: बाद में दोनों पक्षों ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। मंगलवार को सियोल हाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर चार

साल कर दी। अदालत ने उन्हें यूनिफिकेशन चर्च से एक और चैनल बैग (कीमती हैंडबैग) लेने और शेयरों की कीमत में हेरफेर के मामले में भी दोषी पाया। दंपती की स्थिति उस समय बदली, जब दिसंबर 2024 में यून ने मार्शल लॉ लगाया, जिसके कारण उनके खिलाफ महाभियोग शुरू हुआ और उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद उन पर कई आपराधिक मामले चले। जांचकर्ताओं का कहना है कि किम का मार्शल लॉ लागू करने से कोई संबंध नहीं था।

अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति की पत्नी होने के नाते किम देश का प्रतिनिधित्व करती हैं और राष्ट्रपति पर उनका प्रभाव होता है। लेकिन उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया और अपने प्रभाव का उपयोग करके उपहार प्राप्त किए। किम और स्वतंत्र जांच टीम दोनों के पास अब सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए एक सप्ताह का समय है। जांच टीम ने पहले 15 साल की सजा की मांग की थी। जबकि किम के वकीलों का कहना है कि जांच राजनीतिक रूप से प्रेरित थी।

पिछले साल अगस्त से जेल में हैं किम: किम पिछले साल अगस्त से जेल में हैं। तब अदालत ने उन्हें सबूत नष्ट करने की आशंका के कारण गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया था। अपने कार्यकाल के दौरान भी किम कई विवादों में घिरी रहीं, जिससे राष्ट्रपति की लोकप्रियता प्रभावित हुई। तीन दिसंबर 2024 को यून ने अचानक मार्शल लॉ लगा दिया था और संसद पर सैनिकों और पुलिस को भेज दिया। उन्होंने कहा था कि वह 'देश विरोधी ताकतों' और 'उत्तर कोरिया समर्थकों' को खत्म करना चाहते हैं। बाद में उन्होंने कहा कि यह कदम विपक्ष के खिलाफ संघर्ष के लिए जरूरी था। फरवरी में सियोल की एक अदालत ने यून को विद्रोह का दोषी पाया, क्योंकि उन्होंने सेना और पुलिस का उपयोग करके संसद पर नियंत्रण करने, राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार करने और लंबे समय तक बेरोकटोक सत्ता चलाने की कोशिश की थी।

ओपेक से बाहर हुआ यूएई: पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका, भारत को होगा फायदा?

अबुधावी, एजेंसी। संयुक्त अरब अमीरात ने करीब 60 साल बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओपेक) से बाहर होने का फैसला किया है। यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक भी माना जा रहा है, जिससे सऊदी अरब और उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान पर असर पड़ सकता है।

यूएई और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था, खासकर तेल उत्पादन को लेकर। यूएई ज्यादा उत्पादन करना चाहता था, जबकि सऊदी अरब कम उत्पादन के पक्ष में था। इसके अलावा, यूएई पाकिस्तान से भी नाराज था, क्योंकि वह अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था और ईरान के हमलों पर कड़ा रुख नहीं अपना रहा था।

ओपेक छोड़ने से यूएई को क्या फायदा? यूएई 1967 में ओपेक में शामिल हुआ था और यह संगठन का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। लेकिन उत्पादन कोटा सऊदी अरब के नियंत्रण में होने से यूएई अपनी पूरी क्षमता से तेल निर्यात नहीं कर पा रहा था।ओपेक से बाहर होने के बाद अब यूएई अपनी जरूरत के हिसाब से उत्पादन बढ़ा सकेगा और ज्यादा मुनाफा कमा सकेगा। इस फैसले से सऊदी अरब की वैश्विक तेल बाजार में पकड़ भी कमजोर हो सकती है।

खाड़ी देशों के साथ बढ़ा मतभेद- यूएई ने यह फैसला ऐसे समय लिया, जब खाड़ी देशों की बैठक चल रही थी। ईरान के हमलों के बाद भी इन देशों के बीच कोई संयुक्त कार्रवाई नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के अनुसार, यूएई चाहता था कि सऊदी अरब और कतर मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक समर्थन न मिलने के कारण यूएई ने आर्थिक रूप से अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। यूएई की सरकारी कंपनी के मुताबिक, उसका तेल उत्पादन 2027 तक 3.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से बढ़कर 5 मिलियन बैरल हो सकता है। ईरान के कारण पहले ही तेल उत्पादन में गिरावट आई है, जिससे ओपेक की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। यूएई का यह कदम वैश्विक तेल बाजार के संतुलन को बदल सकता है।

पाकिस्तान फैक्टर भी अहम- यूएई पहले ही पाकिस्तान पर दबाव बना चुका है। हाल ही में उसने पाकिस्तान से 3.5 अरब डॉलर वापस ले लिए, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बढ़ती नजदीकियां भी यूएई को पसंद नहीं हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ओपेक छोड़कर यूएई सऊदी-पाक गठजोड़ को भी कमजोर करना चाहता है। यूएई के इस फैसले से वैश्विक बाजार में तेल की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे कीमतों में कमी आ सकती है। इसका सीधा फायदा भारत जैसे आयात करने वाले देशों को मिलेगा।

क्योंकि उनका तेल खर्च कम होगा और महंगाई पर भी असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है।

बरगद की छांव तले बिरहोर कण्डा में सजा भरोसे का जनता दरबार

जहां कभी नक्सल साये ने रोकी थी विकास की राह, वहीं आज डीसी-एसपी ने लोक संवाद से जगाया भरोसा

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटविकासर दूर, कभी घोर नक्सल प्रभाव के कारण भय और उपेक्षा की पहचान बना गोमिया प्रखंड के सियारी पंचायत अंतर्गत बिरहोर कण्डा (डुमरी) बुधवार को उम्मीद और विश्वास के नए अध्याय का साक्षी बना। लोक संवाद के तहत उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा और पुलिस अधीक्षक (एसपी) नाथू सिंह मीना जब पहाड़ पर बरगद की छांव तले पीवीजीटी बिरहोर परिवारों के बीच बैठे, तो यह सिर्फ जनता दरबार नहीं, बल्कि शासन के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की संवेदनशील पहल बन गई। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने यह संदेश दिया कि जो क्षेत्र कभी मुख्यधारा से दूर माना जाता था, वहां अब सरकार खुद पहुंच रही है। समस्याएं सुनी गईं, अधिकारों पर चर्चा हुई और विकास का भरोसा भी मिला। बरगद तले बैठ यह संवाद मानो दूरस्थ पहाड़ियों में विश्वास का नया बीज बो गया। ग्रामीणों ने क्रमवार आवास, पेयजल, सड़क, तालाब जीर्णोद्धार, शिक्षा तथा अन्य बुनियादी समस्याएं उपायुक्त (डीसी) श्री अजय नाथ झा के समक्ष रखीं। ग्रामीणों की मांग पर मध्य विद्यालय डुमरी बिरहोर को उच्च विद्यालय में अपग्रेड करने की दिशा में की जा रही पहल की जानकारी देते हुए उपायुक्त ने कहा कि जिला से प्रस्ताव विभाग को भेजा जा चुका है और इसकी वे स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि बच्चों को दूर पढ़ने नहीं जाना पड़े।

वन अधिकार, विकास और आजीविका पर विशेष जोर

उपायुक्त ने कहा कि यह क्षेत्र आदिवासी और गैर-आदिवासी सामाजिक समरसता का सुंदर उदाहरण है। उन्होंने सामूहिक वन अधिकार के तहत पात्र लोगों को पट्टा दिलाने हेतु ग्रामसभा से प्रस्ताव पारित कर प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही वन अधिकार कानून के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया उन्होंने पंचायत क्षेत्र की सड़कों, विद्यालय और जलापूर्ति योजनाओं के समाधान के लिए ग्रामसभा आधारित प्रस्ताव जिला को भेजने को कहा। पीएम जनमन योजना के तहत जर्जर आवास वाले पात्र परिवारों को लाभान्वित करने का निर्देश भी दिया। उपायुक्त ने मुखिया रामवृक्ष मुर्मू से पंचायत क्षेत्र में बिना भेदभाव सभी गांवों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की अपील करते हुए कहा - मिलजुल कर रहिए, यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत है।

परंपरा भी बचे, विकास भी बढ़े...

उपायुक्त ने कल्याण विभाग के माध्यम से वाद्य यंत्र वितरण तथा सप्ताह में एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर स्थानीय परंपरा और संस्कृति को जीवित रखने की बात कही। जनता दरबार के दौरान बच्चों के बीच कॉपी-कलम, फुटबॉल, बैट-बॉल आदि का वितरण कर स्नेह जताया गया। वहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन बॉल में बोकारो का मान बढ़ाने वाली सुश्री रेशमा कुमारी को डीसी - एसपी ने प्रशस्ति पत्र और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।

डरने की जरूरत नहीं, प्रशासन आपके साथ है: एसपी

मौके पर पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना ने कहा कि यह क्षेत्र कभी नक्सल समस्या से प्रभावित रहा, जिससे विकास बाधित हुआ, लेकिन अब स्थिति नियंत्रित है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि किसी भी भ्रामक या असामाजिक तत्व को दोबारा पनपने न दें। उन्होंने कहा, किसी फर्जी समूह से डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी समस्या की जानकारी प्रशासन को दें हर संभव सहयोग मिलेगा।

डीडीसी ने भी दिया भरोसा, लगा स्वास्थ्य शिविर

मौके पर उप विकास आयुक्त (शताब्दी मजूमदार ने भी ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने ग्रामीणों द्वारा पत्तल निर्माण एवं रस्सी निर्माण के लिए मशीन उपलब्ध कराने की मांग पर सकारात्मक पहल करने की बात कहीं। मौके पर प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर आवश्यक परामर्श दिया गया।

बरगद तले बैठा यह संवाद बन गया विश्वास की नई मिसाल

यह आयोजन केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह संदेश भी दे गया कि शासन अब दूरस्थ पहाड़ियों और अंतिम छोर के गांवों तक पहुंच रहा है। बरगद की छांव तले बैठा यह जनता दरबार ग्रामीणों के मन में यह विश्वास छोड़ गया कि प्रशासन सिर्फ सुनने नहीं, साथ खड़े होने आया है।

लुगुबुरु की वादियों में प्रशासन-जनता के बीच विश्वास का संवाद

उपायुक्त ने सुनी ग्रामीणों की पीड़ा, कहा हर समस्या के समाधान की होगी टाइम लाइन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। लुगुबुरु पहाड़ की तलहटी में प्रकृति की गोद में बसे गोमिया प्रखंड के गोसे गांव में बुधवार को प्रशासनिक संवेदनशीलता और जन विश्वास की एक भावनात्मक तस्वीर देखने को मिली। गांव के बीच पेड़ की छांव तले ग्रामीणों के बीच बैठकर उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना, उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार समेत जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी ने सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिया। ग्रामीणों के बीच संवाद करते हुए उपायुक्त (डीसी) अजय नाथ झा ने कहा कि यह सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि भरोसे को मजबूत करने की पहल है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आया राम - गया राम नहीं होगाङ्ग आपकी समस्याओं को सूचीबद्ध कर लिया गया है। दो-तीन दिनों में संबंधित विभागों के साथ बैठक कर समाधान की समय-सीमा तय की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सड़क, पुल, सिंचाई, जल संरक्षण, वन विभाग से जुड़े मसले, स्कूल और आंगनबाड़ी की समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल होगी। स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय करते हुए फलदार पौधारोपण, मधुमक्खी पालन जैसे आजीविका के नए अवसरों से ग्रामीणों को जोड़ने की बात कही। वहीं, टीवीएनएल से संबंधित लंबित मुआवजा मामलों पर भी उपायुक्त ने भू-अर्जन विभाग के साथ बैठक कर समाधान का भरोसा दिया। उपायुक्त ने ग्रामीणों से कहा कि आप सभी खुश रहने की आदत मत छोड़िएङ्ग प्रशासन आपके साथ है। मौके पर पुलिस अधीक्षक (एसपी) नाथू सिंह मीना ने कहा कि आप सबों के सहयोग से क्षेत्र के असामाजिक तत्वों को नियंत्रित किया गया है और विकास कार्यों में जो विलंब हुआ, उसे दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस और अंचल प्रशासन एक टीम की तरह काम करेंगे। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक गुरुवार को थानों में थाना दिवस आयोजित होगा, जहां भूमि संबंधी मामलों के निष्पादन हेतु थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। आम जनता की शिकायतों को सूचीबद्ध कर संबंधित कार्यालयों तक पहुंचाया जाएगा।

जब दूरी अधिक हो, प्रशासन खुद गांव आता है : डीडीसी

मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार ने कहा कि जिला मुख्यालय में प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को "हम आपको सुनते हैं " (जनता दरबार) आयोजित होता है, लेकिन गोसे जैसे दूरस्थ गांवों की दूरी को देखते हुए प्रशासन ने गांव पहुंचकर सीधे समस्याएं सुनने की पहल की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सभी समस्याओं को दर्ज कर लिया गया है और उनके समाधान के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संवेदनशील प्रशासन की मिसाल बना गोसे गांव में संवाद

यह आयोजन केवल समस्याएं सुनने का मंच नहीं, बल्कि प्रशासन और जनता के बीच भरोसे, अपनत्व और सहभागिता की एक जीवंत मिसाल बना है। लुगुबुरु की शांत वादियों में पेड़ के नीचे बैठा यह संवाद ग्रामीणों के मन में यह विश्वास छोड़ गया कि शासन अब सिर्फ दफ्तरों में नहीं, गांव की चौपाल तक पहुंच चुका है। जनता दरबार के दौरान डीसी- एसपी- डीडीसी आदि ने उपस्थित बच्चों के बीच कॉपी-कलम, बैट-बॉल, चॉकलेट व बिस्कुट वितरित कर स्नेह जताया मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा सुचीता किरण, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

बेसहारा गौवंश की सुरक्षा और गौ सेवा के प्रति जागरूकता अभियान

चंदनकियारी/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, और इसी आस्था को सेवा के संकल्प में बदलने के लिए आज चास में 'गौ सेवा आह्वान अभियान' की शुरूआत की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बेसहारा गौवंश की सुरक्षा और समाज में गौ सेवा के प्रति जागरूकता फैलाना है। बोकारो के चास में गौ भक्तों और सामाजिक कार्यकताओं ने मिलकर 'गौ सेवा आह्वान अभियान' का शंखनाद किया। इस अभियान के तहत न केवल सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के चारे और पानी की व्यवस्था की जा रही है, बल्कि आम जनमानस से भी अपील की जा रही है कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ सेवा का संकल्प लें। सेवा का संकल्पः ग्रामीणों और शहरवासियों से प्रतिदिन 'पहली रोटी गौ माता के नाम' निकालने का आह्वान किया, वोही बीमार और घायल गायों के लिए तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरूआत। इस दौरान लक्ष्मीकांत झा ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि कोई भी गौवंश भूख से न तड़पे। इस अभियान के जरिए हम हर घर को जोड़ रहे हैं ताकि गौ सेवा केवल एक नारा न रहकर एक जन-आंदोलन बन सके। गौ भक्त सौरभ झा का कहना है कि यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक क्षेत्र की हर गौशाला आत्मनिर्भर नहीं हो जाती और हर गाय को सुरक्षित ठिकाना नहीं मिल जाता। अब देखना यह होगा कि समाज इस आह्वान पर कितनी तत्परता से आगे आता है। मौके पर अशोक कुमार शर्मा, रविन्द्र कुमार सिन्हा, राजकुमार, विश्वमोहन कुमार, सुरजीत कुमार राकेश, मुकेश कु० कश्यप, राजेन्द्र कुमार मिश्र, प्रशांत कुमार ठाकुर, बिनोद राम, श्याम सुन्दर सिंह, बिहारी प्रसाद, नेहरू बेसरा, गणेश धीवर,रंजीत महतो समेत अन्य गौ भक्त मौजूद रहे।

संकट मोचन हनुमान अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में कलाकारों ने बांधा समां

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। प्रख्यात संगीतज्ञ पं बच्चन जी महाराज के संयोजन में मंगलवार की शाम सेक्टर 4 डी शिव हनुमान मंदिर परिसर में श्री श्री संकट मोचन हनुमान जी अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिक्षाविद् व साहित्यकार डॉ आर एन सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि संगीत सतत साधना की चीज है। संगीत ईश्वर की आराधना का सबसे सुगम मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है साहित्य, संगीत से विहीन मनुष्य पशु तुल्य है। पं बच्चन जी महाराज इस तरह के संगीत समारोह के माध्यम से बोकारो में संगीत का अलख जगाने का पुनीत कार्य कर रहे हैं जो बहुत ही प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से कलाकारों को मंच मिलता है और उनकी कला प्रतिभा को प्रोत्साहन मिलता है। इस अवसर पर बोकारो व बाहर से आमंत्रित कलाकारों ने गायन व वादन की सुमधुर प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। जवाहर नवोदय विद्यालय, अंडमान निकोबार से पधारे संगीत शिक्षक व गया घराने के शास्त्रीय गायक अभिनंदन पाठक ने राग बिहाग में धमार गायन प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। चंद्र कान्त शर्मा ने राग जोग में गायन, गोमो से पधारे पंडित रुपेंद्र गोस्वामी व सूरज गोस्वामी ने भजन, बोकारो के शंकर भगत, प्रमोद कुमार व देवदीप ने भजन, बाल कलाकार प्रियनंदिनी पाठक ने राग भीमपलासी व भजन गाया। कार्यक्रम में तबले पर शिव चरण गोस्वामी उर्फ राजू गोस्वामी, आदित्य कुमार दुबे, शुभाशीष पाठक, पियुष अनुराग, रुद्र आनंद, आकाश गोस्वामी व हारमोनियम पर अभिनंदन, दीप नारायण गोस्वामी, देवदीप, राजू गोस्वामी व चंद्र कांत शर्मा, सिंथेसाइजर पर सदय कुमार झा ने संगति की। मंच संचालन शिव चरण गोस्वामी व

धनबाद की युवती की बेंगलुरु में संदिग्ध मौत, मजबूत थी, सुसाइड नहीं कर सकती : परिजन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। धनबाद की रहने वाली 34 वर्षीय पूजा दत्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में बेंगलुरु में मौत का मामला सामने आया है। पूजा का शव उनके किराए के फ्लैट से नग्न और खून से लथपथ अवस्था में बरामद किया गया। शव अर्ध-सड़ी हुई हालत में था, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी मौत दो से तीन दिन पहले हो चुकी थी। घटना का खुलासा तब हुआ जब अपार्टमेंट के लोगों ने फ्लैट से दुर्गंध आने की शिकायत पुलिस से की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और शव को बरामद किया। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि कमरे में फटे हुए कागज जरूर पाए गए हैं। पुलिस आत्महत्या और अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। मृतका पूजा दत्ता मूल रूप से धनबाद के हीरापुर स्थित इंद्रदेव टावर के पांचवें तल्ले पर बने फ्लैट में अपनी माँ, पिता, भाई और भाभी के साथ रहती थी। वह एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थीं और पहले बॉस इंडिया लिमिटेड कंपनी में कार्यरत थीं। वर्ष 2018 में कंपनी के काम से उन्हें जर्मनी भी भेजा गया था। बाद में उन्होंने कंपनी की नौकरी छोड़ दी थी। इस संबंध में कंपनी का एक पत्र उनके घर भी पहुंचा था, जिस पर परिवार ने पूछताछ की तो पूजा ने कहा था कि सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। परिजनों के अनुसार, पूजा के पति इंदरनील बीट की मृत्यु मार्च 2021 में कोविड के दौरान हो गई थी। इस घटना से वह जरूर टूट गई थीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए एक महीने के भीतर ही वर्क फ्रॉम होम के जरिए दोबारा काम शुरू कर दिया था। वर्ष 2023 में उन्होंने परिवार को बताया था कि वह अब पूरी तरह ठीक हैं और बेंगलुरु में रहकर काम करना चाहती हैं, जिसके बाद परिवार ने उन्हें वहां शिफ्ट होने में मदद की।

गैंगस्टर प्रिंस खान का राइट हैंड मेजर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर, कई राज खुलेंगे

धनबाद/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। आपराधिक नेटवर्क और राज्य पुलिस के बीच ऑन-गोइंग खेल का एक नया निर्णायक मोड़ आ चुका है. प्रिंस खान गैंग का माना जाने वाला उसका दाहिना हाथ और डिजिटल थिंक टैंक 'सैफी अब्बास नकवी' उर्फ सैफी उर्फ मेजर अब धनबाद पुलिस की हिरासत में है. इंटरपोल और झारखंड-बंगाल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में उसे दुबई से गिरफ्तार कर कोलकाता लाया गया, और अब उसे धनबाद पुलिस के 3-दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि इस रिमांड में गैंग के नेटवर्क, फंडिंग, फरार सरगना प्रिंस खान के ठिकाने और रंगदारी के बंटवारे तक जैसे कई राज खुलेंगे.

सैफी अब्बास कौन है?

सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर धनबाद से ताल्लुक रखने वाला शख्स है, जिसे गैंग के भीतर सैफी और मेजर के नाम से जाना जाता है. पुलिस और जांच एजेंसियों के मुताबिक प्रिंस खान और गोपी खान के बाद गैंग में सैफी की हैसियत नंबर तीन की थी. यानी गैंग का एक मजबूत और भरोसेमंद स्तंभ. वह गैंग में 'टेक्नोक्रेट' और डिजिटल थिंक टैंक की भूमिका निभाता था. उसके पास अच्छी इंग्लिश, तेज दिमाग और डिजिटल मीडिया की गहरी समझ है, जिसे गैंग ने धमकी, ऑनलाइन वसूली और ऑपरेशन मैनेजमेंट के लिए भरपूर इस्तेमाल किया.

दुबई में कैसे हुई गिरफ्तारी

सैफी करीब 5 साल से भगोड़ा था. वह यूएई के अजमान में छिपकर गैंग को ऑनलाइन और डिजिटल रूप से ऑपरेट कर रहा था. मीडिया रिपोर्ट्स भी बताती हैं कि वह वहां एक लॉन्ड्री बिजनेस चलाकर खुद को ढकोसला करता था, जबकि असली काम रंगदारी और फंड-फ्लो मेनेजमेंट था. इंटरपोल की मदद से धनबाद पुलिस ने उसका डिजिटल ट्रेल ट्रैक किया और उसकी लोकेशन को दुबई-अजमान क्षेत्र में पकड़ लिया. वहां से उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया. उसे कोलकाता एयरपोर्ट पर इंटरपोल और झारखंड-बंगाल टीम ने रिसीव किया, जहां प्रारंभिक पूछताछ की गई. बाद में उसे पश्चिम बंगाल से ट्रांजिट रिमांड पर धनबाद लाया गया और कोर्ट ने उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, ताकि झारखंड पुलिस उससे गहन जांच कर सके.

बोकारो हवाईअड्डा राजनीति का अड्डा नहीं बने, उड़ान शुरू हो: धर्मवीर

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो हवाईअड्डा का शीघ्रता शीघ्र परिचालन प्रारंभ हो इस हेतु राष्ट्र भक्त समाज एवं श्री करणी सेना के द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज करणी सेना के जिला कार्यालय दुंदीबाग में एक आवश्यक बैठक हुई जिसमें करणी सेना के द्वारा हवाई अड्डा शीघ्रता शीघ्र शुरू करने हेतु इस अभियान का पुरजोर समर्थन करते हुए आवाज बुलंद किया गया। राष्ट्र भक्त समाज के केन्द्रीय अध्यक्ष एवं श्री करणी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जनता के इनकम टैक्स का पैसा लगभग 100करोड की लागत से बोकारो हवाई अड्डा बनकर तैयार है फिर इसका परिचालन/उड़ान प्रारंभ क्यों नहीं हो रहा।कौन बाधक है और क्या समस्या है इसे बोकारो की जनता जानना चाहती है। बोकारो हवाई अड्डा बोकारो के शहरी एवं ग्रामीण जनता की मांग है। उन्होंने कहा, बोकारो हवाई अड्डा को राजनीति का अड्डा नहीं बनने दिया जाए। बोकारो हवाई अड्डा शुरू होने से बोकारो के 100 के एम के दायरे के सभी शहरी ग्रामीण एवं विस्थापित जनता का समग्र विकास होगा। बैठक का संचालन प्रदेश महामंत्री गोपाल सिंह ने किया।

आतंकवादी स्लीपर सेल की गहन जांच की मांग, सौंपा ज्ञापन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। नासिक, महाराष्ट्र की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में हिंदू महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण के लिए दबाव, गोमांस खाने की मजबूरी और नमाज पढ़ने के जो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। उनके पीछे की जहरीली जिहादी मानसिकता और संगठित अपराध को खत्म किया जाना चाहिए, ऐसी मांग हिंदू जनजागृति समिति ने की है। यह केवल नासिक तक सीमित नहीं है, बल्कि मुंबई सहित देश की अन्य शाखाओं में फैला हुआ एक बड़ा 'कॉपोरेट जिहाद' हो सकता है। इसके पीछे के 'लव जिहाद', 'धार्मिक आतंक' और 'धर्मांतरण रैकेट' की गहन जांच कर राष्ट्रव्यापी श्रृंखला का पदार्फाश किया जाए, अन्यथा समिति जन-आंदोलन छेड़ेगी। यह चेतावनी हिन्दू जनजागृति समिति ने जिला उपायुक्त कार्यालय, बोकारो के माध्यम से राज्य प्रशासन तथा पुलिस को दिए गए एक ज्ञापन के माध्यम से दी है। इस अवसर पर समिति के पूर्व-पूर्वोत्तर भारत राज्य समन्वयक श्री शंभू गवारे, अन्य कार्यकर्ता सर्वश्री रणजीत सिंह, राजेश कुमार सिंह एवं मधुरंजन सिंह, उपस्थित थे। उक्त कंपनी में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नासिक में 7 मिले हैं, तो अन्य शहरों में कितने होंगे? यह एक बड़ा 'कॉपोरेट षड्यंत्र' हो सकता है।

कार्मिकों के हित में कनीय प्रबंधक परीक्षा नीति 2026 में बदलाव करे प्रबंधन

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने प्रभारी चेयरमैन सह निदेशक कार्मिक को पत्र लिखकर कनीय प्रबंधक परीक्षा नीति 2026 में बदलाव करने का पुनः मांग किया है । अपने पत्र के माध्यम से यूनियन महासचिव हरिओम कुमार ने लिखा है कि सेल कॉपोरेट कार्यालय द्वारा 24 अप्रैल 2026 को कनीय प्रबंधक पदोन्नति परीक्षा हेतु सर्कुलर जारी किया गया है । जिसमें कई नीति पदोन्नत कार्मिकों के हितो के विरुद्ध है । यूनियन ने कई बार पुर्व में उपरोक्त मूद्दो पर पत्र भी दिया था । यूनियन द्वारा परीक्षा नीति मे बदलाव हेतु मांग की गई। पिछले कई परीक्षा में कुछ विषयों हेतु चयनित प्रश्न काफी कठिन पुछे गए थे , जिसके कारण उपरोक्त कठीन प्रश्नो वाले विषय में अधिकतर वरिष्ठ कर्मचारी असफल हो गए थे । वरिष्ठ कर्मचारियों की उम्र , शिक्षण के प्रति रुची को ध्यान में रखकर ही प्रश्न पत्र सेट किया जाना चाहिए ।

बीएसएल में स्क्रैप डंपिग क्षेत्र का हुआ कायाकल्प

बोकारो/नवबिहार टाइम्स ब्यूरो। बोकारो इस्पात संयंत्र में स्वच्छता एवं प्रभावी हाउसकीपिंग को बढ़ावा देते हुए सीओ एंड सीसी विभाग द्वारा कोक ओवन बैटरी संख्या 7 एवं 8 के समीप स्थित स्क्रैप-डंपिंग क्षेत्र का सफलतापूर्वक कायाकल्प किया गया है। पूर्व में यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मिश्रित स्क्रैप, जैसे भारी धातु अवशेष, पाइप एवं विघटित संरचनाओं से आच्छादित था, जिसके कारण सुरक्षा एवं संचालन संबंधी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही थीं। इस क्षेत्र के पुनर्विकास के अंतर्गत सुव्यवस्थित योजना के माध्यम से स्क्रैप का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण एवं निष्पादन सुनिश्चित किया गया। संबंधित टीमों द्वारा विभागीय संसाधनों का कुशल एवं प्रभावी उपयोग करते हुए पूरे क्षेत्र का समतलीकरण, व्यापक साफ-सफाई तथा मानकों के अनुरूप सुरक्षा बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, जिससे इसे पूर्णतः सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जा सका। कर्मियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थल पर सुव्यवस्थित बाइक स्टैंड तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था भी विकसित की गई है। इस परिवर्तन से न केवल संभावित जोखिमों का प्रभावी निराकरण हुआ है, बल्कि कार्यस्थल की सौंदर्यता एवं उपयोगिता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। नव विकसित स्थल के औपचारिक उद्घाटन के अवसर पर हरित पहल को प्रोत्साहित करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, जो पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के प्रति संयंत्र की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह पहल बोकारो इस्पात संयंत्र की सुरक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण एवं उत्कृष्ट कार्यस्थल प्रबंधन के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है तथा औद्योगिक परिसर में उच्च स्तरीय हाउसकीपिंग मानकों की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक कमल किशोर द्वारा डी.बी. कॉर्प. लि. के लिए भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, गोविंदपुर मेन रोड, अशोक नगर, केजी आश्रम, धनबाद (झारखंड) से मुद्रित तथा प्लांट नंबर-31, कॉपरेटिव कॉलोनी, बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो (झारखंड) से प्रकाशित। संपादक कमल किशोर, नवबिहार टाइम्स (दैनिक), सत्येंद्र नगर, औरंगाबाद (बिहार), स्थानीय संपादक : मनोज विशाल
फोन नंबर- 9431145865 8210783623
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या : JHAHIN/2017/72655
E-mail- nbtimesbihar@gmail.com